प्रेरणा

समय को दोष देने से बेहतर है उसे दिशा देना।
-बेंजामिन फ्रैंकलिन

संपादकीय

समय रहते ही चुनौतियों के लिए तैयारी करनी होगी

होर्मुज मार्ग खोलने को लेकर ट्रम्प के अल्टीमेटम और उस पर ईरान की उतनी ही संगीन धमकी के बाद प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक में कई अन्य मंत्रालयों को बुलाकर युद्ध के फौरी, मध्य और दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा की। उधर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भले ही कहा हो कि भारत पर वैश्विक बाजार में क्रूड तेल के दाम 90-100 डॉलर प्रति बैरल तक रहने पर भी कोई खास असर नहीं होगा और अगर कीमत 130 डॉलर तक छह से नौ माह तक रहे, तब जाकर महंगाई बढ़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री आसन्न संकट के प्रबंधन की तैयारी में लग गए हैं। वैश्विक तेल उत्पादन 30% कम हो गया है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। अरब देशों में ईरानी हमलों के डर से सारे कारोबार ठप हैं। ऐसे में चिंता यह है कि वहां काम करने वाले एक करोड़ भारतीय क्या अब रोजगार में रहेंगे? क्या वे भारत में पैसे भेज पाएंगे? उनके वापस लौटने से बेरोजगारों की फौज में और इजाफा नहीं होगा? दुनिया में रेमिटेंस से सबसे ज्यादा आय (120 अरब डॉलर) भारत की है। हमारे कुल रेमिटेंस का 38% खाड़ी देशों से आता है। तेल आयात पर भारत की निर्भरता 90% है। परिवहन के लिए भारत ने चीन की तरह ईवी पर शिफ्ट नहीं किया है, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का कच्चा माल भारत में पैदा होता है। हमें समय रहते आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करनी होगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

सांसारिक धूप में छांव का काम करती है हमारी परम्परा

प्रकृति ने सुख और दुःख का संतुलन दे रखा है। इंसान न तो केवल सुख पचा पाएगा, और न ही दुःख। समझदारी इसी में है कि दोनों को लेकर चलें। कथा सुनने के बाद गरुड़ जी ने काकभुशुंडि जी से कहा था- जो अति आतप ब्याकुल होई, तरु छाया सुख जानइ सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। आज हमारी युवा पीढ़ी की जो जीवनशैली है, वो भविष्य में उनको और परेशान करने वाली है। और यह भारत में ही है, ऐसा नहीं है। रूस की सीमा से लगा एक देश है एस्टोनिया, जिसकी राजधानी का नाम है टालिन। मैं सुंदरकांड पर वहां बोल रहा था तो वहां के एक निवासी ने बताया राष्ट्रभक्ति और परिवार के प्रति जिम्मेदारी यहां की युवा पीढ़ी में कम हो गई है। मैंने पूछा आप निदान क्या निकाल रहे हैं? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक परम्परा है, संस्कृति है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को शास्त्रों से जोड़ें, जो सांसारिक धूप में छांव का काम करेंगे। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • पार्टी को अपेक्षा से बढ़कर सफलता मिली

राज्यसभा चुनावों ने भाजपा को और मजबूत बनाया है

सियासत

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार
neerja_chowdhury@yah oo.com

इस साल राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव सामान्य से अधिक चर्चा में रहे। चूंकि 37 सीटों में से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए तो प्रथमदृष्टया लग सकता था कि चुनाव साधारण रहे होंगे। लेकिन ये एक तरीके से भाजपा का शो बन गए। पार्टी को उसकी जरूरत से भी ज्यादा सीटें मिल गईं। इसमें बिहार, ओडिशा और हरियाणा में हुई क्रॉस वोटिंग का अहम योगदान रहा, जिसने सीधे-सीधे विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाया। चुनावों ने ये भी दिखाया कि भाजपा की अपने उम्मीदवारों को सशक्त बनाने और विरोधियों को कमजोर करने की दोधारी रणनीति का मुकाबला करने में विपक्ष विफल रहा। लेकिन चुनावों का असली महत्व तो नीतीश कुमार के अप्रत्याशित नामांकन और शरद पवार के फिर से राज्यसभा में जाने में था।

और इसी में भाजपा की सफलता की कहानी छिपी है। नीतीश और पवार, दोनों ही भारतीय राजनीति के दिग्गज हैं। दोनों ही अपने-अपने राज्यों में कई बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यहां तक कि दोनों को कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक माना जाता था। दोनों ही आज स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाजपा काफी समय से 'पाटलिपुत्र' की गद्दी पर नजरें गढ़ाए थी। वह तो 2025 का बिहार चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ने से हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा। चूंकि चुनाव नीतीश के नाम पर जीता गया और जदयू ने अपनी सीटें लगभग दोगुनी कर लीं तो भाजपा ने भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखने का निर्णय किया- भले ही वह 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि नीतीश के पास 85 सीटें थीं।

हालांकि यह सभी को पता था कि मौका मिलते ही भाजपा पटना में नेतृत्व परिवर्तन का प्रयास करेगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना कोई नेता बैठाएगी। बिहार भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जहां वह कभी सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन बदलाव इतनी जल्दी होगा, इसकी उम्मीद कम थी। सबसे जटिल मसला यह था कि नीतीश को कैसे हटने के लिए राजी किया जाए? क्योंकि अपने मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखने के लिए ही तो वे इतनी मशक्कत करते आ रहे थे। पटना की गद्दी पर बने रहने के लिए ही उन्होंने कई बार गठबंधन बदले थे।

भाजपा की सफलता केवल यही नहीं है कि उसने नीतीश को बिहार से अपदस्थ कर दिया, बल्कि यह है कि ऐसा उसने स्वयं नीतीश की सहमति से किया। नीतीश ने खुद कहा कि वे अब राज्यसभा का अनुभव लेना चाहते हैं। लेकिन बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री पद देना ही उनके कुर्सी छोड़ने का कारण नहीं हो सकता। नीतीश पूर्व समाजवादी हैं और परिवारवाद के खिलाफ रहे राम मनोहर लोहिया व कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी रहे हैं। वे चाहते तो बेटे को कभी भी राजनीति में ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया।

वैसे याद रहे कि इस समय जदयू के 12 लोकसभा सांसद भाजपा के लिए बेहद अहम हैं। चूंकि भाजपा 240 सांसदों के साथ लोकसभा में अल्पमत में है, इसलिए वह अपने सहयोगियों पर निर्भर है। वह सुनिश्चित करना चाहेगी कि लोकसभा में उसकी सीटों के गणित को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो।

शरद पवार का निर्विरोध निर्वाचन भी इसी परिप्रेक्ष्य में गौरतलब है। भाजपा ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जैसे उसने बिहार और ओडिशा के विपक्षी दलों के सामने उतारे थे। इसी से उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्ष हारा। पवार को महा विकास अघाड़ी ने राज्यसभा के लिए नामित किया था। इसके तीन दलों में एनसीपी (एसपी) सबसे छोटी सहयोगी है। बाकी दो दल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) हैं। इस फैसले ने सभी को चौंकाया, क्योंकि पवार तो संन्यास लेने की

बिहार, ओडिशा और हरियाणा में हुई क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाया। भाजपा की अपने उम्मीदवारों को सशक्त बनाने और विरोधियों को कमजोर करने की दोधारी रणनीति का मुकाबला करने में विपक्ष विफल रहा।

बात कर रहे थे। ऐसे में शिवसेना को चिंता है कि भविष्य में पवार एनडीए की सहयोगी एनसीपी के करीब जा सकते हैं, जिसका नेतृत्व दिवंगत अजित पवार कर रहे थे। सभी जानते हैं कि शरद और अजित गुट के बीच विलय की बातचीत चल रही थी।

महा विकास अघाड़ी ने शायद यह सोचते हुए पवार को उम्मीदवार बनाया कि उन्हें पर्याप्त समर्थन मिल जाएगा, जबकि किसी अन्य का भाजपा विरोध कर सकती है। भाजपा के इस सद्भावना भरे रवैए से लग रहा है कि उसे उम्मीद है शरद पवार की पार्टी के आठ सांसद भी जरूरत पड़ने पर रिजर्व फोर्स की तरह लोकसभा में उसके काम आ सकते हैं।

कुल मिलाकर, नीतीश का राज्यसभा जाना उन्हें और जदयू पर उनकी पकड़ को कमजोर करने वाला है। जबकि पवार का दोबारा राज्यसभा में जाना उन्हें और उनकी पार्टी को मजबूती देगा। और ये दोनों ही कदम अंततः भाजपा को और ताकतवर करेंगे।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)

दूरदृष्टि • ताकत की भाषा बोल रही हैं महाशक्तियां

चीन अमेरिका से सीख रहा है कि ताइवान को कैसे हड़पें

भू-राजनीति

ब्रह्मा चेलानी
पॉलिसी फॉर सेंटर रिसर्च के प्रोफेसर एमेरिटस

पिछले वर्ष सत्ता में आने के बाद से ट्रम्प ने कैरेबियाई क्षेत्र से लेकर पूर्वी-प्रशांत और अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व तक सैन्य-हमलों के आदेश दिए हैं। उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करके उसके नेता मादुरो का अपहरण कर लिया। और अब उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान से युद्ध छेड़ रखा है। इस बीच, अमेरिका क्यूबा पर भी चारों ओर से फंदा कस रहा है। उसे उम्मीद है कि इससे उत्पन्न होने वाली मानवीय-त्रासदी से घबराकर क्यूबा उसके लिए दरवाजे खोल देगा।

जैसे-जैसे ट्रम्प अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बेधड़क अवमानना कर रहे हैं, चीन भी इससे सबक ले रहा है। ट्रम्प का क्यूबा-मॉडल तो शी जिनपिंग के सामने ताइवान को हड़पने का एक उपयोगी खाका प्रस्तुत करता है। यह इस बात का खुलकर मुजाहिरा है कि महाशक्तियां किस प्रकार से किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए उसका गला घोंट सकती है।

आधुनिक समाज कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियों- जैसे भोजन, जल, परिवहन और संचार पर निर्भर करते हैं। लेकिन एक प्रणाली इन सब पर हावी है : ऊर्जा। बिजली से ही पानी के पम्प, रेफ्रिजरेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल नेटवर्क, औद्योगिक-कृषि उत्पादन संचालित होते हैं। जैसे ही बिजली ग्रिड फेल होती है, अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां चरमराने लगती हैं और सामाजिक स्थिरता के समक्ष खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि जो देश बिजली उत्पादन के लिए आयातित ईंधन पर अत्यधिक निर्भर हैं, वे मूलतः असुरक्षित होते हैं।

क्यूबा लंबे समय से मुख्यतः वेनेजुएला और मैक्सिको से खरीदे गए तेल पर निर्भर रहा है। ट्रम्प ने उसकी इसी असुरक्षा का फायदा उठाते हुए ईंधन आपूर्ति पर पूर्ण नाकाबंदी लागू कर दी है। लाखों लोग बिजली से वंचित हो गए हैं। जल-पम्पिंग स्टेशन बंद हो गए हैं। ट्रैक्टर और डिलीवरी ट्रक निष्क्रिय पड़े हैं, जिससे खाद्य कीमतों में उछाल आ गया है और खाद्य संकट बढ़ता जा रहा है। अस्पताल अनियमित ब्लैकआउट के बीच काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

शी जिनपिंग इससे सबक सीखकर ताइवान की भी इस प्रकार की दमनकारी घेराबंदी कर सकते हैं। वे ताइपेई पर मिसाइलें दागने या ताइवान के समुद्र तटों पर धावा बोलने के बजाय उसके चारों ओर एक समुद्री क्वारंटीन या कस्टम-निरीक्षण व्यवस्था घोषित कर सकते हैं, जिसमें चीनी तटरक्षक पोत ताइवानी बंदरगाहों की ओर जा रहे ऊर्जा टैंकरों को सुरक्षा जांच या तस्करी-विरोधी अभियानों के नाम पर रोक सकते हैं।

इस तरह के मामूली व्यवधान भी तेजी से आपूर्ति-अवरोध पैदा कर सकते हैं। चूंकि ताइवान अपने लगभग पूरे ईंधन (मुख्यतः एलएनजी) का आयात करता है और मुश्किल से दो सप्ताह के भंडार को ही बनाए रखता है, ऐसे में तट से दूर प्रतीक्षा कर रही एलएनजी टैंकरों की कतार कुछ ही हफ्तों में वहां शृंखलाबद्ध किल्लत को जन्म दे सकती है। क्यूबा की तरह ताइवान को भी ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसके जल-आपूर्ति और स्वास्थ्य-सेवा तंत्र बाधित होंगे। औद्योगिक उत्पादन- जिसमें वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले सेमीकंडक्टर संयंत्र भी शामिल हैं- ठप हो जाएगा।

चीन का मकसद ताइवान का तत्काल आत्मसमर्पण भले न हो, लेकिन इस तरह से वो धीरे-धीरे उसकी जड़ें कमजोर कर सकता है। वैसी स्थिति में चीन ताइवान में स्थिरता लाने या वहां के लोगों की रक्षा करने का हवाला देकर उसे हड़प सकता है। वैसे भी ट्रम्प-युग में फ्रेंडली-टेकओवर को किसी कॉर्पोरेट-रीस्ट्रक्चरिंग जैसा बना दिया गया है।

महाशक्तियां एक-दूसरे का बारीकी से मुआयना करती हैं। ऐसे में जो एक के लिए कारगर हो, वह दूसरे के लिए एक मिसाल बन जाता है। आज अमेरिका जो कर रहा है, वह चीन के लिए एक पूर्वाभ्यास और परीक्षण की तरह है।

फॉर्मूला सरल है : किसी देश में समस्याएं पैदा करो और फिर उनका समाधान देने का हवाला देकर उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने लगो।

अगर चीन ताइवान पर सीधे हमला बोलता है तो अन्य देशों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर जहाजों के रूटीन निरीक्षणों का हवाला देकर ताइवान की आपूर्ति को बाधित कर दिया जाए तो वह किसी बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहराएगा। वैसे भी शी जिनपिंग ऐसी रणनीतियों के माहिर हैं, जिसके चलते उन्होंने दक्षिण चीन समुद्र और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में एक भी गोली चलाए बिना बड़े सामरिक लाभ हासिल किए हैं।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

इस हफ्ते चर्चा में...

इलेक्ट्रिक कारों की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद

24 प्रतिशत रही
अमेरिका में इस माह इलेक्ट्रिक कारों के लिए ऑनलाइन सर्च। फरवरी में 21 % थी। युद्ध से तेल, गैस संकट कारण हो सकता है।

9.34 लाख करोड़ रुपए
जुटाने की तैयारी कर रहे हैं अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए।

12 प्रतिशत इजाफा
हुआ है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के मूल्य में ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला होने के बाद से अब तक।

समरनीति • इजराइल के दो शहरों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से मचा हड़कंप

इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सेंध लगने की जांच शुरू, यूएस से अधिक गोला-बारूद की मांग

इसाबेलकर्नर

इजराइल में शनिवार को डिमोना और नजदीकी शहर अराद पर गिरी ईरान की दो बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइलियों को स्तब्ध कर दिया है। इजराइल के दक्षिण नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित उसके प्रमुख परमाणु रिसर्च सेंटर और रिएक्टर के मुकाबले कुछ ही स्थान ऐसे होंगे जो इनसे ज्यादा सुरक्षित हों। इसलिए तीन घंटे के अंतर से गिरी दो ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले साल ईरान से 12 दिन के युद्ध में इनका जखीरा खत्म हो गया होगा। यह चिंता आने वाले सप्ताहों में और गहरी होगी। इजराइल के सैनिक अधिकारियों ने बताया, वे जांच कर रहे हैं कि गड़बड़ी कहां हुई है। लेकिन विस्तृत ब्योरे पर चुप्पी साध रखी है।

रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रभावित स्थानों का दौरा करने के बाद इजराइलियों से कहा कि वे बेफिक्र न रहें। मिसाइल अलर्ट आने पर बम शेल्टर में शरण लें।

इजराइली सेना ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की दर 90% बताई है। अधिकारियों का कहना है कि डिफेंस सिस्टम रोकथाम की 100% क्षमता कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। इजराइली एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पूर्व कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रैन कोचाव ने बताया कि डिमोना बहुस्तरीय इजराइली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित था। यह ऑपरेशनल नाकामी है।

इजराइल के मिसाइल डिफेंस में आयरन डोम प्रमुख है। लेकिन इसे हमास की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का उसका सबसे आधुनिक हथियार एरो-3 है, लेकिन एरो-3 सिस्टम महंगा है। उसे बनाने में समय लगता है। इजराइली मीडिया ने रविवार को बताया कि अराद और डिमोना में एरो-3 तैनात नहीं था। इजराइल और अमेरिका द्वारा तैयार एंटीबैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम धरती के वातावरण के बाहर अंतरिक्ष में मिसाइलों को रोकता है। इजराइल में अमेरिका का थाड सिस्टम भी तैनात है।

© The New York Times

इजराइल के सेफ्टी सिस्टम के कमजोर होने पर चिंता

डिमोना में बैलिस्टिक मिसाइल से इमारतों को हुए नुकसान के बाद बचाव में लगे इजराइली सैनिक।

पिछले साल जून में 12 दिन के युद्ध की समाप्ति के बाद इजराइली सेना ने चिंता जताई थी कि क्या देश का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खत्म होने से पहले ही चुक जाएगा। उस वक्त अधिकारियों ने कहा था कि इजराइल को अपने इंटरसेप्टर बचा कर खर्च करना होंगे। उसे सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अहमियत देना पड़ेगी। वैसे इजराइली सेना ने इन बातों का खंडन किया है।

अधिक इंटरसेप्टर की मांग

इजराइली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल अमीर बराम इस माह अधिक इंटरसेप्टर और गोला-बारूद सप्लाई करने की मांग करने वाशिंगटन गए थे। नाम न बताने की शर्त पर तीन इजराइली अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या अमेरिका अधिक सप्लाई के लिए सहमत हो गया है।

क्लस्टर मिसाइलों से खतरा

जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर फटने वाली ईरान की क्लस्टर मिसाइलें घातक साबित हो रही हैं। अराद, डिमोना, तेल अवीव और यरूशलम के पास बेट शेमेश पर हमलों के अलावा अन्य इलाकों में बड़े मिसाइल के हिस्सों या क्लस्टर मिसाइलों से कई बिल्डिंग और सड़कों को नुकसान पहुंचा है।

कानून

कोर्ट ने कहा निवेशकों की हानि के लिए मस्क दोषी

केट कॉन्गर, नताली रोया

सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने कहा है कि ट्विटर (अब एक्स) निवेशकों के कुछ नुकसान के लिए कंपनी के मालिक इलॉन मस्क जिम्मेदार हैं। मुकदमा दायर करने वालों के वकीलों ने बताया कि मस्क को ट्विटर के पूर्व शेयरधारकों को 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक चुकाने होंगे। मस्क ने कहा था कि वे कंपनी को खरीदने का सौदा अभी नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ शेयरधारकों ने ट्विटर के अपने शेयर बेच दिए थे, लेकिन अक्टूबर 2022 में मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया।

शेयरधारकों ने उसी साल मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका दावा था कि मस्क ने अपने ऑफर पर नए सिरे से बातचीत के लिए शेयर के दाम गिराने के लिए ऐसा किया। निवेशकों ने याचिका में जिक्र किया कि मस्क ने कई सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ट्विटर पर फर्जी अकाउंट की भरमार है और वे उसकी खरीद अस्थायी तौर पर रोक रहे हैं। इन पोस्ट के कारण कई शेयरधारकों ने कंपनी के शेयर कम मूल्य पर बेच दिए। अगर सौदा होता तो उन्हें ज्यादा मूल्य मिल सकता था। मस्क के वकीलों ने कहा कि वे ज्यूरी के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

© The New York Times

बिजनेस • हर साल 5% बढ़ रही अमेरिका के ए-क्लास के मॉल्स की आय

मॉल जाकर शॉपिंग करना पसंद कर रही जेन-जी

ज्यानप्रिश्च

अमेरिका में रियल एस्टेट डेवलपर ऐसा सोचते रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स खत्म हो गए हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। नई पीढ़ी (जेन-जी) खुद जाकर शॉपिंग करना पसंद कर रही है। लिहाजा खास किस्म के मॉल चलने लगे हैं।

अमेरिका में ज्यादातर ए-क्लास मॉल्स की मालिक साइमन प्रॉपर्टी के न्यूयॉर्क शहर के रूजवेल्ट फील्ड पर स्थित मॉल की 96.3% जगह किराए पर है। एक्स फैंटी, अरमानी, हर्मीस और रोलेक्स उसकी किराएदार हैं।

शॉपिंग मॉल्स की नई सफलता और इनोवेशन में युवाओं खास तौर पर जेन-जी की अहम भूमिका है। इस्पॉस कंज्यूमर ट्रैकर के सर्वे के अनुसार 18 से 34 वर्ष आयु के 58% खरीदारों ने बताया कि वे अक्सर मॉल्स में शॉपिंग करते हैं। उनकी ये दर 55 साल की आयु के लोगों से दोगुनी है।

1990 के दशक में शॉपिंग मॉल किसी बड़ी कंपनी या स्टोर के कारण ही सफल हो पाते थे। आज साइमन व जीजीपी जैसी कंपनियों के मॉल रिटेल, खानपान, मनोरंजन सहित कुछ नए स्टोर की वजह से चलने लगे हैं। हालांकि बी और सी क्लास के मॉल्स की आय हर साल 5% कम हो रही है।

टॉप 100 मॉल्स की हिस्सेदारी 50%

अमेरिका में लगभग 900 मॉल हैं। लेकिन उनमें कुछ ही कामयाब हैं। टॉप 100 मॉल्स का मूल्य पूरे सेक्टर का 50 फीसदी है। जबकि सबसे निचले 350 मॉल का मूल्य सिर्फ दस प्रतिशत है। ए-मॉल्स की आय हर साल पांच फीसदी बढ़ रही है। ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज के मॉल्स डिवीजन जीजीपी के किराएदारों की बिक्री 2019 के बाद बीस प्रतिशत बढ़ी है। कंपनी हर साल किराया बढ़ा रही है।

शॉपिंग मॉल्स K-आकार की रिकवरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अच्छे मॉल और ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, वहीं पुराने और साधारण मॉल तेजी से बंद हो रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर के अनुसार 2024 में मॉल्स में आने वाले कंज्यूमर की संख्या में 9.7% बढ़ोतरी हुई है।

© The New York Times

स्वास्थ्य

पेसमेकर नाकाम होने की घटनाएं बढ़ रही हैं

केटी थॉमस

2024 में अमेरिका के आयोवा में 93 साल की ग्लेडिस नेपर की मौत के बाद डॉक्टरों ने बताया कि आयु अधिक होने के कारण महिला की मौत हुई थी। बाद में पता लगा कि पेसमेकर की बैटरी बंद होने से उनके दिल की धड़कन रुक गई थी। पेसमेकर निर्माता कंपनी बोस्टन साइंटिफिक ने भी यह चूक स्वीकारी है। इससे दो साल पहले फिनलैंड में ऐसी ही गड़बड़ी के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की छानबीन में पता लगा कि ग्लेडिस की मौत के छह माह बाद कंपनी ने पेसमेकर का एकोलेड मॉडल वापस लिया। कंपनी ने बताया कि यह गड़बड़ी सितंबर 2018 के बाद बने लगभग दो लाख डिवाइस में थी। 2025 में एक जांच में पाया गया कि नए पेसमेकर की बैटरी भी खराब थी।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी • काम की समीक्षा एआई के उपयोग से हो रही

टेक दिग्गज टोकन से कर्मचारियों के एआई इस्तेमाल पर रख रहे नजर

केविन रूज

मेटा और शॉपिफाई जैसी कंपनियों में मैनेजरों ने कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा के लिए एआई को शामिल किया है। दरअसल कंपनियों को उम्मीद है, एआई के बढ़ते उपयोग से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।

ओपनएआई सहित कुछ कंपनियों में कर्मचारियों के बीच होड़ लगी है कि वह कितने टोकन इस्तेमाल करते हैं। टोकन से पता चलता है एआई का कितना इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण के लिए एक निबंध लिखने वाले छात्र को दस हजार टोकन (लगभग 7500 शब्द) लगते हैं। अभी हाल तक चैटजीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करने में यूजर को कंप्यूटर पर घंटों टाइपिंग करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एजेंटिक कोडिंग टूल्स किसी सुपरविजन के बिना घंटों काम कर सकते हैं। कुछ कर्मचारी अपना काम ऑटोमैटिक करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इससे टोकनों की संख्या बढ़ती है।

210 अरब टोकन किए प्रोसेस

ओपनएआई में एक इंजीनियर ने पिछले सप्ताह कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के जरिये करीब 210 अरब टोकन प्रोसेस किए। यह इतना टेक्स्ट है, जिससे विकीपीडिया को कम से कम 33 बार भरा जा सकता है।

एंथ्रोपिक ने अपने एजेंटिक कोडिंग टूल्स की तेज रफ्तार के कारण इस साल के पहले दो महीनों में आय के दोगुना होने का अनुमान लगाया है। ओपनएआई ने बताया कि उसके एजेंटिक कोडिंग टूल कोडेक्स से यूजर्स की संख्या इस साल तीन गुना बढ़ी है। © The New York Times

बिजनेस ब्रीफ

कोटक डॉयचे बैंक का रिटेल बिजनेस खरीदेगी

मुंबई | कोटक महिंद्रा बैंक डॉयचे बैंक के भारत स्थित रिटेल कारोबार को खरीदने के करीब है। ये डील 4.5 हजार करोड़ की हो सकती है। डील में 27 हजार करोड़ की का रिटेल पोर्टफोलियो है, जिसमें होम, पर्सनल लोन, एमएसएमई फाइनेंसिंग व वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस शामिल हैं।

अब सरल भाषा में मिलेगी आईपीओ की जानकारी

मुंबई | सेबी ने आईपीओ से जुड़ी जानकारी को ज्यादा आसान और समझने लायक बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब आईपीओ लाने जा रही कंपनियों को दस्तावेज के साथ एक संक्षिप्त पार्ट 'एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस' देना होगा। इसमें बिजनेस, वित्तीय स्थिति और जोखिम जैसी अहम जानकारी सरल भाषा और तय शब्दसीमा में देनी होगी।

एअर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व एमडी इंडिगो से जुड़े

नई दिल्ली | देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सोमवार को एअर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व एमडी आलोक सिंह को नया चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर (सीएसओ) नियुक्त किया। यह नियुक्ति इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद हुई है, जिसे कंपनी के भविष्य की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

भास्कर एनालिसिस बाजार में बड़ी गिरावट में डीआईआई ने संभाला मोर्चा

घरेलू निवेशकों की सबसे तेज खरीदारी, 12 दिनों में ही लगा दिए एक लाख करोड़ रुपए

भास्कर न्यूज | मुंबई

शेयर बाजार के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच पिछले एक माह में सेंसेक्स 10,000 अंक (12%) और निफ्टी-50 लगभग 3,000 अंक (12%) तक टूट चुका है। बावजूद इसके घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) इस वर्ष अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे लगा चुके हैं। पहले 1 लाख करोड़ रुपए 39 सत्र में लगाए, दूसरे 1 लाख करोड़ सिर्फ 12 दिनों लगाए, जो अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। यह खरीदारी इस बात का संकेत है कि घरेलू निवेशक गिरावट को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय बाजार से अपना भरोसा कम किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 की निकासी अब तक 88,180 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जा चुके हैं। 2026 में अब तक कुल निकासी 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। यह स्थिति फरवरी के उलट है, जब विदेशी निवेशकों ने 22,615 करोड़ लगाए थे, जो 17 माह का उच्चतम स्तर था।

भास्कर एक्सपर्ट सनी अग्रवाल, डीवीपी, रिसर्च हेड, एसबीआई सिक्युरिटीज

छोटी कंपनियों के पिटे शेयर बेचें, क्वालिटी स्टॉक्स में शिफ्ट हों, एकमुश्त की जगह धीरे-धीरे निवेश बढ़ाएं

बाजार की गिरावट में भी डीआईआई आक्रामक खरीदारी क्यों कर रहे?

कई म्यूचुअल फंड कंपनियां लंबे समय से 15-20% कैश लेकर बैठी थीं। अब जब एफआईआई की बिकवाली से फ्रंटलाइन कंपनियां 10-15% सस्ती हुई हैं, तो उन्हें बेहतरीन 'एंट्री पॉइंट' मिल रहा है। प्राइवेट बैंकों और ऑटो जैसे सेक्टर की कीमतें 2-3 साल पुराने स्तर पर हैं, जबकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं। इससे कम कीमत पर हाई-क्वालिटी स्टॉक मिल रहे हैं। मार्केट में ऐसी स्थिति बेहद दुर्लभ है।

छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए?

अगर सरप्लस पैसा है जिसकी 2 साल जरूरत नहीं है, तो धीरे-धीरे क्वालिटी शेयरों में निवेश करें। बच्चों की शिक्षा/शादी का पैसा इस वक्त बाजार में न डालें क्योंकि अनिश्चितता बनी हुई है। यदि निवेशक स्टॉक्स चुनने में असहज हैं तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी ईटीएफ सबसे सुरक्षित विकल्प हैं।

मौजूदा निवेशकों को क्या करना चाहिए?

मौजूदा निवेशकों के लिए सलाह यह है कि पैनिक होकर न बेचें, क्योंकि अधिकांश करेक्शन हो चुका है। पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। एसएमई या कमजोर कंपनियों से निकलकर पैसा बड़ी और मजबूत कंपनियों में शिफ्ट करें, क्योंकि संकट में छोटी कंपनियों को उबरने में वक्त लगता है।

किन सेक्टर्स, शेयरों पर नजर रखनी चाहिए?

प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी ज्यादा टूटे हैं, रिकवरी भी तेज होगी। आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस आकर्षक दिख रहे हैं। ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो पर नजर रखें। लार्सन एंड टुब्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन, टाटा स्टील और आईटी में एचसीएल टेक में एंट्री ले सकते हैं।

बाजार की असली तस्वीर क्या है? तेज गिरावट का दौर कब तक थम सकता है?

बाजार 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में है। ट्रम्प के लिए भी यह युद्ध राजनैतिक रूप से नुकसानदेह है, इसलिए उम्मीद है कि वे जल्द सुलह का रास्ता निकालेंगे। 1-2 हफ्तों में सुलह होती है, तो कच्चा तेल 70-80 डॉलर के स्तर पर आ जाएगा। ऐसे में निफ्टी तेजी से 23,500 पार जा सकता है। कंपनियों की कमाई पर असर नहीं पड़ेगा। युद्ध 3 माह से ज्यादा खिंचता है, तो दबाव बढ़ेगा और निफ्टी 22,000 तक जा सकता है।

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट जंग की आंच टाइल्स कारखानों तक

मोरबी के 600 सिरेमिक फैक्ट्री बंद, इससे राजस्थान की 2300 ग्राइंडिंग यूनिट ठप

भीलवाड़ा से जसराज ओझा व मोरबी से किशन परमार की रिपोर्ट

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग से राजस्थान और गुजरात का खनन उद्योग पर बड़ी मार पड़ी है। गुजरात के मोरबी की 600 टाइल्स फैक्ट्रियों में 15 अप्रैल तक शटडाउन है। वजह इन उद्योगों में 70 लाख क्यूबिक गैस की खपत है और गुजरात के मोरबी में प्रोपेन और नेचुरल गैस की आपूर्ति न्यूनतम स्तर पर है। इसका असर राजस्थान की 3400 खदानों पर दिख रहा है। यहां 2300 ग्राइंडिंग यूनिट्स बंद हो गई हैं। इनमें ही क्वार्ट्ज व फेल्सपार पत्थर पीसकर पाउडर बनता है। हर माह 50 हजार टन पाउडर गुजरात जाता है। गुजरात से खाड़ी देशों को होने वाला 20% निर्यात ठप है। यहां एक यूनिट में सोडा, पोटाश का 100 टन माल की खपत है।

मोरबीः 250 फैक्ट्रियों में ईंधन खत्म, मजदूर यूपी-बिहार वापस जा रहे

गैस की किल्लत से मोरबी स्थित 600 सिरामिक फैक्ट्रियां बंद है। सिरामिक उद्योग बंद होने से इससे जुड़ी पेपर मिलों, कच्चे माल के परिवहन और पैकेजिंग उद्योग को भी झटका लगा है। यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा से आए 4 लाख से अधिक श्रमिकों की स्थिति खराब है। मोरबी, वांकानेर और राजकोट रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। सिरेमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज एरवाड़िया बताते हैं कि सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है। उद्योगपति राजन पटेल ने बताया कि फैक्ट्री बंद होने के बावजूद फिक्स चार्ज का बोझ बरकरार है।

असरः मोरबी का वार्षिक बाजार 60,000 करोड़ का है, जिसमें से 20,000 करोड़ का निर्यात होता है। शिपिंग भाड़ा दोगुना बढ़कर 4000 डॉलर हो गया है। पूर्व अध्यक्ष नीलेश जेतपुरिया ने कहा, 20% निर्यात ठप है। विदेशी पोर्ट पर फंसे कंटेनर वापस लाने से घाटे बढ़ रहा है।

भीलवाड़ाः ग्राइंडिंग यूनिटों में सन्नाटा, ₹50-70 करोड़ का व्यापार प्रभावित

राजस्थान की 3400 से ज्यादा खदानों से क्वार्ट्ज व फेल्सपार पत्थर निकलता है। इन पत्थरों को पीसकर पाउडर बनता है और ये काम करने वाली 2300 ग्राइंडिंग यूनिट में भी सन्नाटा है। भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री मालिक बृजेश काकानी बताते हैं कि लम्पस, दाने व पाउडर के रूप में 50 हजार टन माल प्रोडक्ट से जाता है, जो बंद है। राजपूताना माइंस ऑनर्स एंड मिनरल मर्चेंट एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष आरवी माहेश्वरी ने कहा कि मोरबी में 600 फैक्ट्रियों में टाइल्स बनती है, इसका बड़ा असर यहां पड़ा है।

असरः भीलवाड़ा में 275, ब्यावर-अजमेर में 1200, सीकर 200, राजसमंद 500, उदयपुर 125 ग्राइंडिंग यूनिट है। यहां 3400 खदानों से पत्थर आता है। गुजरात से मांग खत्म हो गई है। व्यापारी मानवेंद्र कुमावत ने बताया कि इससे 50-70 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ।

बोइंग के गढ़ सिएटल में बड़ा प्रयोग... दो इमारतों के बीच लटका 180 टन का प्लेन

वर्ल्ड ब्रीफ

~~ब्रिटेनः रूसी जासूस को जहर देने से जुड़े सेलिसबरी में फिर दो लोग बीमार, रास्ते बंद कर दिए गए~~

~~लंदन। ब्रिटेन के जिस सेलिसबरी शहर में रूसी जासूस ... घातक ... प्रयास किया गया था, वहीं एक और जोड़ा बीमार पड़ गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए सड़कों को सील कर दिया है। गत मार्च में स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया ... इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है।~~

सिएटल | अमेरिका के सिएटल में रियल एस्टेट और एविएशन का अद्भुत संगम दिख रहा है। यहां 2.10 लाख करोड़ रुपए लागत से '1,200 स्टुअर्ट' प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत रिटायर बोइंग 747 विमान के मुख्य हिस्से (फ्यूजलेज) को दो 48 मंजिला आवासीय टावरों के बीच लटकाया जा रहा है। 180 टन वजनी इस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को खास वॉक-वे, आर्ट गैलरी और क्रिएटिव वर्कस्पेस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विमान का अगला हिस्सा सड़क की तरफ झांकता दिखेगा, वहीं पिछला हिस्सा नीचे बने म्यूजिक वेन्यू के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल होगा। सिएटल बोइंग का गढ़ है, इसलिए शहर के इस विमानन इतिहास को सम्मान देने के लिए यह अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। इसे देखने के लिए अभी से लोगों की भारी भीड़ जुट रही है।

बीमा सरेंडर से 2.33 लाख करोड़ निकाले

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारत के जीवन बीमा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹6.30 लाख करोड़ के कुल लाभ का भुगतान किया। इसी के साथ बीमा इंडस्ट्री का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% तक पहुंच गया। कुल भुगतान का 92% हिस्सा 'लिविंग बेनिफिट्स' के रूप में मिला। कुल भुगतान नेट प्रीमियम का 71.92% रहा। बीमा नियामक इरडा की 2024-25 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, अब बीमा केवल मृत्यु के बाद सुरक्षा नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए लक्ष्यों को पूरा करने का माध्यम है। इसमें से ₹2.33 लाख करोड़ की राशि पॉलिसी निकासी और सरेंडर से मिली, जो बीते साल से 1.8% अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 87% के पास पर्याप्त जीवन बीमा नहीं है।

पुणे के ऑटोमोबाइल हब में उत्पादन थमा, पलायन शुरू

पुणे | एलपीजी, कच्चे माल और पुर्जों की भारी कमी का असर पुणे के ऑटोहब पर भी पड़ने लगा है। यहां उत्पादन बंद करने की नौबत आ गई है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास पुर्जों का आमतौर पर एक हफ्ते का स्टॉक होता है। आपूर्ति बंद होने के कारण अब बड़ी कंपनियों को भी अपना उत्पादन घटाना पड़ रहा है। विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर स्थिति के मूल्यांकन के निर्देश दिए। वहीं, काम न होने से उत्तर भारतीय कामगारों ने भी अपने गांवों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है।

सत्र • वित्त मंत्री निर्मला का प्रस्ताव ध्वनिमत से पास

सदन में बहस के बाद कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक जेपीसी को भेजा

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

लोकसभा ने सोमवार को कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 को विस्तृत विश्लेषण और सिफारिशों के लिए दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। यह निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सुझाव पर ध्वनि मत से लिया गया। विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने विरोध जताया। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ने आरोप लगाया कि यह विधेयक कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे का 2% सीएसआर पर अनिवार्य रूप से खर्च करने के प्रावधान को कमजोर करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि केवल 'शुद्ध लाभ' की गणना के मानकों में बदलाव किया गया है। उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला से विधेयक को जेपीसी को भेजने का सुझाव दिया।

विदेशी बेनामी संपत्ति पर 4,009 करोड़ टैक्स लगाया

नई दिल्ली | आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती नौ महीनों विदेशी अघोषित आय और संपत्ति पर 4,009 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया है। यह कार्रवाई ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत की गई है। पिछले पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 4,556.64 करोड़ रुपए था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पनामा, पैराडाइज और पैंडोरा पेपर लीक से जुड़े मामलों में सरकार ने अब तक कुल 14,636 करोड़ रुपए की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति का टैक्स असेसमेंट किया है।

एंट्री • भारत के एनर्जी सेक्टर में एलन की बड़ी तैयारी

मस्क की अंबानी, अदाणी व टाटा से टक्कर, एनर्जी सेक्टर में उतरेंगे

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला अब इलेक्ट्रिक कारों के साथ भारत के एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी की वेबसाइट पर 'बिजनेस डेवलपमेंट लीड' की वैकेंसी से इसकी पुष्टि हुई है। टेस्ला यहां ग्रिड-लेवल पर उद्योगों के लिए और घरेलू उपयोग के लिए छोटे बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाएगी। कंपनी इलेक्ट्रिक कारों पर निर्भरता घटाकर स्टोरेज कारोबार बढ़ाना चाहती है। हालांकि, मस्क को रिलायंस, टाटा और अदाणी ग्रुप से कड़ी चुनौती मिलेगी, जो पहले ही इस क्षेत्र में बड़ा निवेश कर चुके हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लीन

अदाणीः 1 लाख करोड़ लगाकर 18 गीगावॉट क्षमता हासिल की

अदाणी ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में 1 लाख करोड़ निवेश कर चुकी है। गुजरात के खावड़ा में नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने से कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता 18 गीगावॉट है। लक्ष्य 2030 तक इसे 50 गीगावॉट करना है। आगामी वर्षों में 2.5-3 लाख करोड़ अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।

एनर्जी इकोसिस्टम के लिए 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया है। फोकस जामनगर में 5 'गीगा फैक्ट्री' बनाने पर है। लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावॉट सौर क्षमता हासिल करना है। टाटा पावर ने क्लीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश कर रही है। कंपनी का जोर रूफटॉप सोलर और ईवी चार्जिंग नेटवर्क पर भी है।

मौसम की मार • वाशी मंडी में आवक 60% घटी, पर विदेशों से भारी मांग

अल्फांसो आम की 80% फसल तबाह, 10 हजार रुपए तक बिक रही है पेटी

सुशील मिश्र | सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)

कोंकण के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्र में इस साल अल्फांसो (हापुस) आम की फसल पर प्रकृति का कहर टूटा है। बदलते मौसम और बेमौसम बारिश के कारण 80% फसल बर्बाद हो गई। वाशी एपीएमसी मंडी के आंकड़ों के अनुसार, इस साल गुड़ी पड़वा पर केवल 10,000 बॉक्सेस पहुंचे, जबकि पिछले साल यह संख्या 25,000 थी।

मंडी संचालक पानसरे के अनुसार, उत्पादन कम होने से दाम आसमान छू रहे हैं। वर्तमान में छोटे आमों की एक पेटी 5,000 रुपए और बड़े आमों की पेटी 10,000 रुपए तक बिक रही है। कम आवक के बावजूद यूरोप, अमेरिका और दुबई के एक्सपोर्टर्स में इसकी भारी मांग है।

कृषि विभाग और कोंकण कृषि विद्यापीठ की रिपोर्ट के अनुसार, सिंधुदुर्ग में उत्पादन इतना घटा है कि जहां पहले रोजाना 50-60 ट्रक मुंबई जाते थे, अब केवल 2-3 ट्रक ही पहुंच रहे हैं। साल 2025 में 5.19 लाख टन कुल उत्पादन में से रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग का योगदान 250,845 टन था, जिसमें अल्फांसो का हिस्सा 225,756 टन था। इस साल 1 लाख हेक्टेयर के बाग प्रभावित हुए हैं।

किसानों की 5 हजार रुपए प्रति पेड़ मुआवजे की मांग

50-60 वर्षों में पहली बार आए इस संकट को देखते हुए किसान इसे 'प्राकृतिक आपदा' घोषित करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने 5,000 रु./पेड़ या 5 लाख रु/हेक्टेयर मुआवजे के साथ मांग की है। साथ ही, पुराने कर्ज की माफ करने की गुहार लगाई है। नई कर्ज सीमा 6 लाख करने की मांग है।

मेगा प्रोजेक्ट • आर्सेलर मित्तल के मेगा स्टील प्लांट की नींव

आंध्र में मित्तल का 70 हजार करोड़ का स्टील प्लांट, 82 लाख टन क्षमता

बिजनेस संवाददाता | विशाखापत्तनम

दिग्गज स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के भारत में अपना ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने के दो दशक पुराने सपने को सोमवार को नई दिशा मिली। आंध्र में विशाखापत्तनम से 60 किमी दूर राजय्यपेटा में 82 लाख टन क्षमता वाले मेगा स्टील प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इसका भूमि पूजन किया। मित्तल समूह पहले चरण में 70 हजार करोड़ रुपए निवेश करेगा। पुराना अनुभव नए स्टील ऑपरेशंस को सफल बनाने में काम आएगा। इस प्लांट से 2029 तक उत्पादन शुरू होगा। लक्ष्मी मित्तल ने इसे 'आत्मनिर्भर भारत' विजन की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस मेगा प्रोजेक्ट से इलाके के करीब 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्टील नीति के 30 करोड़ टन उत्पादन लक्ष्य को पाने में मददगार होगा।

आरबीआई 8 माह बाद डॉलर का शुद्ध खरीदार

मुंबई | आरबीआई ने जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा बाजार में 2.52 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की है। मई 2025 के बाद यह पहला मौका है जब केंद्रीय बैंक शुद्ध खरीदार के रूप में उभरा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में 27.99 अरब डॉलर खरीदे गए, जबकि 25.47 अरब डॉलर की बिक्री हुई। इससे पहले दिसंबर में बैंक ने 10 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की थी। जारी डेटा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक हाजिर बाजार में कुल 51 अरब डॉलर की बिक्री दर्ज की गई है। फॉरवर्ड मार्केट में नेट शॉर्ट डॉलर पोजीशन जनवरी के अंत तक बढ़कर 67.7 अरब डॉलर हो गई।

इतिहास में आज का दिन

रिपोर्ट • दो साल चुनौतीपूर्ण, कमजोर घरेलू मांग और वैश्विक संघर्ष बड़ी बाधा

ईरान युद्ध, महंगाई और टैरिफ से घिरी भारतीय अर्थव्यवस्था, 6.2% रह सकती विकास दर

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत और पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी की है। 'सीट बेल्ट कस लो' नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 अनुमान से कहीं ज्यादा कठिन साल साबित हो सकता है। मूडीज के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 के 7.8% से घटकर 2026 में 7.5% और 2027 में 6.2% रह सकती है। तीन प्रमुख कारण हैं। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष, कमजोर घरेलू मांग और ... म 3.6% रह सकता है।

महंगाईः ब्याज दरों में कटौती पर ब्रेक लगेगा

भारत की सीपीआई महंगाई अभी 3% है। ये आरबीआई के लिए राहत की बात है। लेकिन पश्चिम एशिया संकट से कमोडिटी कीमतें बढ़ीं तो महंगाई 2026 में 3.7% और 2027 में 4.1% तक पहुंच सकती है। इससे ब्याज दरों में कटौती पर ब्रेक लग सकता है। होम लोन, ईएमआई और क्रेडिट महंगे होने का संकेत है।

ट्रम्पः अमेरिकी टैरिफ का संकट अभी टला नहीं

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 10% और फिर 15 फीसदी वैश्विक आयात शुल्क लगा दिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि अमेरिकी आयात शुल्क 2028 तक इसी स्तर पर बना रहेगा, जो देश के आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स के लिए सीधा खतरा है।

... में सुस्ती आई तो डॉटकॉम जैसा दौर आ सकता है

...टर व इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ रही है। आईटी को ...कन शेयरों का मूल्यांकन 1990 के दशक के डॉटकॉम बुलबुल जैसे स्तर पर है। यदि तेजी थमी तो बाजार पर मार पड़ेगी।

~~खास : परमाणु हथियारों का लेखा-जोखा रखने वाले समूह के मुताबिक- पाक दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा परमाणु हथियार देश बनने राह पर है।~~

भास्कर खास • 30 सितंबर को मानसून विदा हो जाएगा ...

मानसून के 13 दिन और ...

भास्कर खास अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी आम लोगों से दूर रही वर्चुअल दुनिया...

मेटावर्स को 'भविष्य' बता रहे थे जकरबर्ग, अब 'अतीत'; 7.5 लाख करोड़ रु. गंवाए, कर्मचारी भी हटाने पड़े, अब सुपर इंटेलिजेंस पर दांव

© The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

न्यूयॉर्क | फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने 2021 में जब कंपनी का नाम बदलकर 'मेटा' किया था, तब उन्होंने एक ऐसी आभासी दुनिया (मेटावर्स- वर्चुअल रियलिटी) का सपना दिखाया था, जहां लोग अवतार बनकर रहेंगे, काम करेंगे और खेलेंगे। आज वह विजन खत्म होने की कगार पर है। मेटा ने हाल ही में 'मेटावर्स' पर काम कर रहे 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर दी।

कंपनी ने घोषणा की है कि 15 जून से लोग वीआर हेडसेट (आंखों पर पहनने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस) के जरिए होराइजन वर्ल्ड्स जैसे इमर्सिव प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जिस प्रोजेक्ट पर कंपनी ने करीब 80 बिलियन डॉलर (लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए) गंवाए, वह अब सिमट रहा है। जकरबर्ग की यह महत्वाकांक्षी योजना टेक दुनिया की सबसे महंगी विफलताओं में से एक मानी जा रही है, क्योंकि अब कंपनी का पूरा ध्यान एआई पर टिक गया है। जुकरबर्ग ने 2014 में कंपनी 'ऑक्युलस' को करीब 16,600 करोड़ रुपए में खरीदकर इस सफर की शुरुआत की थी। उन्हें भरोसा था कि वर्चुअल रियलिटी स्मार्टफोन की जगह ले लेगी। इसके लिए उन्होंने गेमिंग स्टूडियो खरीदे और डेवलपर्स पर करोड़ों लुटाए। कोविड लॉकडाउन के वक्त ये आइडिया क्रांतिकारी लगा, लेकिन बाद में वास्तविकता इससे अलग रही। मेटावर्स के शुरुआती वर्जन तकनीकी खामियों से भरे थे, जिसका सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ा। करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आम जनता ने इसे पूरी तरह नकार दिया।

एपल के महंगे हेडसेट और बाजार की बेरुखी ने बिगाड़ा मेटा का खेलः मेटा ही नहीं, इस रेस में उतरी दिग्गज कंपनी 'एपल' को भी तगड़ा झटका लगा है। 2024 में लॉन्च हुए एपल विजन प्रो की कीमत लगभग करीब 3 लाख रुपए थी, जो एक आम आदमी के बजट से कोसों दूर थी। विश्लेषकों का मानना है कि वीआर तकनीक को एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करना उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन और समय लेने वाला काम है। डिज्नी जैसी कंपनियों ने भी अपने 'चीफ मेटावर्स ऑफिसर्स' के पद खत्म कर दिए हैं। अब मेटा ने अपने फ्लैगशिप एप होराइजन वर्ल्ड्स का रुख वीआर से हटाकर मोबाइल फोन की ओर कर दिया है, जो इस प्रोजेक्ट की हार की औपचारिक स्वीकारोक्ति है।

मेटा अपनी हार स्वीकार कर चुका है। पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में जकरबर्ग ने 'मेटावर्स' शब्द का जिक्र सिर्फ दो बार किया, जबकि 'एआई' का नाम 23 बार लिया। कंपनी अब 'सुपर इंटेलिजेंस' एआई बनाने के लिए इस साल 10.81 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। जकरबर्ग का नया लक्ष्य ऐसा डिजिटल साथी बनाना है, जो इंसान जैसा बुद्धिमान हो। जिस भविष्य को जकरबर्ग ने 'मेटा' नाम दिया था, वह अब एआई के डेटा सेंटर्स और कोडिंग की परतों के नीचे कहीं दब गया है।

यही समय है जब माता-पिता अपने बच्चों को यह सिखाएं कि विविधता में सौंदर्य और विविधता में ही शक्ति है।

- माया एंजिलो

संकट के सामने

किसी भी युद्ध में भले ही दो देश या पक्ष शामिल होते हैं, लेकिन संभव है कि उसके नतीजों का दायरा इतना बड़ा हो कि अन्य कई देशों के लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएं। मसलन, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद न केवल पश्चिम एशिया में, बल्कि समूची दुनिया में कई स्तर पर मुश्किलें बढ़ती देखी जा सकती हैं। यह छिपा नहीं है कि ऊर्जा या तेल और गैस के लिए बहुत सारे देश अपनी जरूरतों के ज्यादातर हिस्से के लिए मध्यपूर्व पर निर्भर हैं। मगर इस युद्ध की शुरुआत के बाद अब धीरे-धीरे स्थितियां बिगड़नी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि भारत सहित कई देश साफतौर पर किसी भी मसले का हल युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए निकालने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जंग में शामिल देश कई बार इस सबसे जरूरी तकाजे को समझने में देर कर देते हैं। दोतरफा व्यापक हमलों और उसमें जानमाल के भारी नुकसान के बीच ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति भी सीमित या बहुत कम हो गई है। यह ऐसी मुश्किल है, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे।

समस्या यह है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचा, तो आम लोगों के सामने बहुस्तरीय संकट खड़े होंगे और सरकार के सामने चुनौतियां गहराएंगी। आने वाले दिनों में युद्ध के स्वरूप के बिगड़ने और इसका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने 'अप्रत्याशित चुनौतियां' हैं। जाहिर है, अब जो हालात हैं, उसमें इनका सामना करना ही विकल्प है। ऐसे में सरकार को जहां रोजमर्रा की अनिवार्य जरूरतों की आपूर्ति को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखने के लिए हर उपाय करना होगा, वहीं विपरीत स्थितियों में भी भरोसे को बनाए रखना होगा। शायद इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला का संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप पड़ने की वजह से भारत में भी तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में व्यापक पैमाने पर बाधा पहुंची है और देश को कच्चे तेल एवं गैस की खरीद के लिए रूस तथा अन्य देशों के विकल्प की ओर देखना पड़ा है।

इतना तय है कि विनाशक हथियारों के हमले से होने वाले नुकसान के समांतर ही दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस स्तर पर ऊर्जा से लेकर खाद्यान्न संकट तक की स्थितियां खड़ी हो रही हैं, उसके असर दीर्घकालिक होंगे। युद्ध की शुरुआत के जो भी कारण बताए जाते हों, मगर उसका समाधान आखिरी तौर पर कूटनीतिक पहलकदमी, संवाद और समझौते के जरिए ही संभव होता है। मगर कई बार संवाद के जरिए समाधान तक पहुंचने में जितना वक्त लगाया जाता है, उसमें न जाने कितने ऐसे निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं होता और कितने संसाधनों का नाश हो चुका होता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने ईरान और इजराइल-अमेरिका की जंग में भी बातचीत तथा कूटनीति का रास्ता अख्तियार करने पर जोर दिया। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती देश में तेल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को सामान्य बनाने की है, ताकि महंगाई नियंत्रण में रहे और आम लोगों का जीवन बाधित न हो। किसी भी विपरीत हालात में आम लोगों की उम्मीद सरकार और उसके रुख पर टिकी होती है।

लापरवाही की हद

वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए देश भर में चिड़ियाघर और अभयारण्य बनाए गए हैं। मगर संरक्षित स्थलों पर भी सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त का अभाव कुछ वन्यजीवों की जान पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक पशु बचाव केंद्र में आवारा कुत्तों के हमले में पंद्रह हिरणों की मौत की घटना ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरत की बात है कि हिरणों को शिकार से बचाने के लिए जिस सुरक्षित स्थल पर रखा गया है, वहां आवारा कुत्तों ने ही सेंध लगाकर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि कुत्तों का झुंड बाड़े को तोड़कर अंदर घुस गया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी। दूसरे, इस घटना ने संबंधित पशु बचाव केंद्र में तैनात कर्मियों की लापरवाही को भी उजागर किया है। सवाल है कि आवारा कुत्ते बाड़े को तोड़कर एक के बाद एक हिरण पर हमला करते रहे, तो वहां निगरानी का जिम्मा संभाले वनकर्मियों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई।

यह बात छिपी नहीं है कि विभिन्न राज्यों में कई जगह चिड़ियाघर और वन्यजीव संरक्षण केंद्र तो स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन वहां न तो पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की गई है और न ही पुख्ता सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बाड़ों के बाहर निगरानी के लिए सीसीटीवी और अन्य तकनीकी प्रबंधों का भी अभाव देखा जाता है। जंगली जानवरों के बाड़े से बाहर निकलकर खुले जंगल में गायब हो जाने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि बाड़ों की सुरक्षा की नियमित निगरानी नहीं हो पाती है। छत्तीसगढ़ की घटना भी इसी व्यवस्थागत खामी और लापरवाही की वजह से हुई है। वन विभाग ने संबंधित डिप्टी रेंजर और तीन वन रक्षकों को निलंबित कर दिया है, लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? अक्सर यह देखा जाता है कि इस तरह की लापरवाही में निचले कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई करके मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में जब तक उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

कृत्रिम मेधा से बदलती खेलों की दुनिया

खेलों के बारे में आम धारणा बदल रही है। यह महज मनोरंजन या शौक नहीं, बल्कि विभिन्न देशों की खेल रणनीति भी है। कृत्रिम मेधा यानी एआइ के विस्तार के बाद बहुत कम समय में खेल की दुनिया में बदलाव देखा जा रहा है।

अखिलेश आर्येंदु

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए संस्कृति, कला और साहित्य जैसे तमाम क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। यहां तक कि खेल और खिलाड़ी की दुनिया भी बदलने लगी है। यह बदलाव कई मायने में बेहद दिलचस्प है। कैसा बदलाव आ रहा है, इसे जानना और समझना चाहिए। खेलों के बारे में आम धारणा बदल रही है। यह महज मनोरंजन या शौक नहीं, बल्कि दुनिया के देशों की खेल रणनीति भी है। कृत्रिम मेधा यानी एआइ के विस्तार के बाद बहुत कम समय में खेलों की दुनिया में बदलाव देखा जा रहा है। एआइ की उपयोगिता जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे तमाम क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता की संभावनाएं भी दिख रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से खेलों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि एआइ से प्रतियोगी खेलों में फायदे के साथ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खेलों में तमाम तरह की सुविधाएं और पारदर्शिता बढ़ती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में खेल की दुनिया में बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इस पर भारत सहित दुनिया के तमाम देश प्रयोग कर रहे हैं।

दो दशक पहले खिलाड़ी केवल अपनी बुद्धि, अनुभव और अभ्यास पर निर्भर रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी खेल हैं जिसमें एआइ का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद पाया गया है। इनमें शतरंज, क्रिकेट, टेबल टेनिस और हाकी प्रमुख हैं। इनमें एआइ के इस्तेमाल को इन खेलों की रणनीति और निर्णय क्षमता के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम देखे जा रहे हैं। खिलाड़ियों को रणनीति तैयार करने, विश्लेषण करने, प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के खेलने की शैली को बेहतर तरीके से समझने, गलतियों से सीखने और अपनी क्षमता को बढ़ाने में एआइ का इस्तेमाल शुरू हो गया है। खिलाड़ियों की सेहत बनाए रखने के लिए एआइ का बेहतर इस्तेमाल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकता है। इससे खिलाड़ियों को बीमारियों से बचाने में भी मदद ली जाने लगी है।

एआइ का खेलों में सबसे अधिक उपयोग खिलाड़ियों के त्वरित निर्णय और डेटा आधारित विश्लेषण में किया जा रहा है। इससे विश्लेषण में पारदर्शिता और विश्वसनीयता आई है। शतरंज के खेल में प्रतिद्वंद्वी की चालों का अनुमान लगाने और खिलाड़ियों को नई रणनीतियां सुझाने में एआइ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह वीडियो गेम में एआइ खेल के तौर-तरीके तैयार करती है। यह गलतियों की पहचान करती है और अभ्यास के लिए मार्गदर्शन देती है। इस नए साधन की मदद से खिलाड़ी तेजी से सुधार करते हैं। इससे खिलाड़ियों की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे-जैसे एआइ का उपयोग बढ़ रहा है। खिलाड़ी इसके जरिए अपनी सफलता पर अधिक आश्वस्त होने लगे हैं।

खिलाड़ी एआइ के जरिए अपने प्रदर्शन का बेहतर विश्लेषण बहुत कम समय में कर सकता है। इसमें कैमरे और सेंसर के माध्यम से खिलाड़ियों की गतिविधियों और गति के वास्तविक समय का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। इसी तरह खिलाड़ियों की जरूरतों के मुताबिक अनुकूलित प्रशिक्षण और आहार योजनाएं तैयार करने में भी एआइ की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। यह

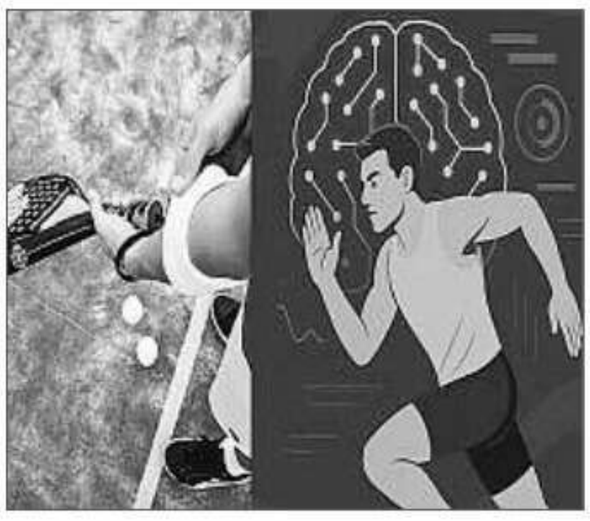

बीमारी को जल्दी समझने और स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। कृत्रिम मेधा शारीरिक डेटा की निगरानी कर खिलाड़ियों में थकान या चोट के जोखिम के बारे में पहले से ही बता सकती है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। यह खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित प्रशिक्षण और अन्य योजनाएं तैयार करने में मदद करती है। खासकर हर तरह का सुधार लाने में मददगार साबित होती है। रेफरी और अंपायर के लिए सटीक निर्णय लेने में एआइ बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। पिछले मैचों के दृश्य और आंकड़ों का गहन विश्लेषण कर प्रतिद्वंद्वी की ताकत और कमजोरी का पता इसके जरिए लगाया जाता है। यह नई प्रतिभाओं की खोज में भी बेहद सहायक है। इससे खेल की दुनिया में तमाम प्रतिभावान बच्चों को अधिक अवसर हासिल हो रहा है।

> दो दशक पहले खिलाड़ी केवल अपनी बुद्धि, अनुभव और अभ्यास पर निर्भर रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी खेल हैं, जिनमें एआइ का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद पाया गया है। इसके बेहतर परिणाम देखे जा रहे हैं। खिलाड़ियों को रणनीति तैयार करने, विश्लेषण करने, प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के खेलने की शैली को बेहतर तरीके से समझने, गलतियों से सीखने और अपनी क्षमता को बढ़ाने में एआइ का इस्तेमाल शुरू हो गया है। एआइ का बेहतर इस्तेमाल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दुरुस्त रखने में मददगार साबित हो सकता है। इससे खिलाड़ियों को बीमारियों से बचाने में भी मदद ली जाने लगी है।

एआइ भले ही बुद्धिमत्ता का अब तक का सबसे बेहतर विकल्प मानी जा रही हो, लेकिन मानव के निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जाहिर तौर पर खिलाड़ी की असली क्षमता इस बात से तय होती है कि यह एआइ को एक साधन के रूप में कैसे उपयोग करता है और वह अपने अनुभव का सही उपयोग और स्वतंत्र निर्णय लेने की कितनी क्षमता रखता है। एआइ केवल गति नाप सकती है और विश्लेषण कर सकती है, जबकि मानव खेल को भावना और रचनात्मकता देता है। खेल भावना से जुड़ी संवेदनाओं को एआइ नहीं समझ सकती। इसलिए कई कमियां भी एआइ में बताई जा रही हैं। भारत में 'खेलो इंडिया' के तहत नौ से 18 साल के बच्चों की प्रतिभा पहचानने और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में छह हजार से अधिक खिलाड़ियों के 'बायोमैकेनिकल प्रोफाइलिंग' के लिए एआइ का उपयोग किया जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करने के मद्देनजर उनको वैज्ञानिक तरीके से निखारने और डेटा-आधारित दिशा देने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इससे खिलाड़ियों में नई ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का संचार होना लाजिमी है।

खेल प्राधिकरण यूनिवर्सिटी आफ एक्सेटर की मदद से खेल प्रौद्योगिकी के द्वारा अभ्यास और डेटा एनालिटिक्स पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। यह देश में खेल विज्ञान और तकनीक के समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह प्रशिक्षण खासतौर पर खेल विशेषज्ञों, कोच, फिजियो फिटनेस विशेषज्ञों और खेल उद्यमियों के लिए तैयार किया गया है। एआइ का इस्तेमाल खेल और खिलाड़ियों के जरिए करने से भारत खेल की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। पिछले एक दशक में शतरंज, क्रिकेट, बास्केटबाल, तेज दौड़, तैराकी और तीरंदाजी सहित तमाम खेलों में एआइ के इस्तेमाल के मामले में हम आगे बढ़ गए हैं। आने वाला वक्त खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तर पर कम समय में कामयाबी हासिल करने में एआइ की भूमिका कहीं ज्यादा हो सकेगी। ऐसा एआइ के जानकार मानते हैं।

हालांकि यह भी मानना है कि कृत्रिम मेधा का अधिक उपयोग खिलाड़ियों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इस पर निर्भरता से खिलाड़ी की स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता में धीरे-धीरे कमी आने लगती है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह बहुत जरूरी होने पर यदि एआइ की उपलब्धता नहीं हो पाई, तो ऐसे में खिलाड़ी असहज महसूस करता है, जिससे खिलाड़ी की रणनीति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यों एआइ में स्वतः स्फूर्ति-भावनाएं, प्रतिस्पर्धा और त्वरित निर्णय की क्षमता नहीं होती है। ऐसे में इसका उपयोग खिलाड़ी के लिए उल्टा परिणाम दे सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझ कर करने की जरूरत होगी। यह भी देखना होगा कि यह समाधान के बजाय समस्या न बन जाए। एआइ के जरिए सकारात्मक परिणामों के लिए नए-नए प्रयोग और शोध हो रहे हैं। इससे खेल की दुनिया में भारत चीन, अमेरिका, ब्राजील, जापान, रूस, कोरिया और फ्रांस जैसे देशों की कतार में आ सकता है।

भूलने का फलसफा

सरस्वती रमेश

अक्सर हम कोई जरूरी काम करना भूल जाते हैं। मौके पर कोई जरूरी बात कहना भूल जाते हैं। अगर उस भूलने से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आमतौर पर हम बेफिक्र आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ भूल जाने की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है, कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें भूलने पर अफसोस होता है। कई बार यह अफसोस अपराध बोध जैसा भी महसूस होने लगता है और हम खुद की लानत-मलामत करते हैं। नौबत आने पर कभी सफाई देकर अपनी गलती को हल्का करने की भी कोशिश करते हैं। फिर दंड भुगतकर दोबारा ऐसी गलती न करने की सीख गांठ बांध लेते हैं। मगर क्या हर बार भूलना अपराध करने के बराबर ही ग्लानिपूर्ण है? क्या हर बार भूल जाने की सजा मिलनी चाहिए? शायद नहीं! भूलना हमारे जीवन की एक जरूरी क्रिया है। सिर्फ जीवन की ही नहीं, इस प्रकृति की भी। मसलन, जिस वसंत को लेकर सभी आह्लादित होते हैं, उसमें पेड़ अपने पुराने, जीर्ण, पीले पत्तों को गिरा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नई पत्तियां उनका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद नए पत्तों से सजे पेड़ अपने पुराने बिछड़े पत्तों के शोक में डूबे रहते हैं क्या? सच यह है कि वे उन्हें बिसारकर नए के स्वागत-सत्कार में तल्लीनता से लीन हो चुके होते हैं।

इसी तरह सभ्यताएं अपने ऊपर जबरन थोपे गए युद्ध, विनाश को भूलकर आगे बढ़ती गई हैं। हालांकि युद्ध के दंश से पार पाना एक चुनौती होती है, लेकिन मनुष्यता समय-समय पर अपने साथ हुई ज्यादतियों को बिसार कर एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रयास में लगी हुई है। मतलब जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए हमें भूलने पर ही निर्भर होना पड़ता है। कई बार भूल जाना याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितनी जल्दी हम अपने साथ हुए हादसे, डर, अपमान, परेशानी को भूल जाते हैं, उतनी जल्दी एक नई शुरुआत के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर मनुष्य अपनी हर पीड़ा को उसी तरह ढोता रहे, जैसे वह आज ही घटित हुई हो, तो उसका जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने, कुछ करने की तो बात ही छोड़ दी जाए।

हमारा जीवन नदी की धारा की तरह प्रवाहमान है। जीवन के संघर्ष, हादसे, दुख-दर्द उन धाराओं के मार्ग के नुकीले पत्थर हैं। इन्हें पार कर बहते जाना ही नदी का स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण वह अपने वेग में बह पाती है। इसलिए भूल जाना किसी मनुष्य की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति है। बाधाओं को पार करने की शक्ति। अपने प्रवाह को बनाए रखने की शक्ति। और सबसे बड़ी बात यह कि नए सपनों को देखने की शक्ति इंसान को पुराने कटु अनुभवों को भूलकर ही मिलती है। जब किसी का अतीत उसके मन-मुताबिक न घटा हो, तो उसकी स्मृतियां बोझ सरीखी लगती हैं। वे जब-तब स्मृति में आकर अंतर्मन को लहूलुहान कर देती हैं। इन रिसते घावों पर विस्मृति का मरहम लगा कर हम अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं। वर्तमान की घटनाओं को कटु होने से बचा लेते हैं। यानी वर्तमान के सुख को जीते हैं और सुखद स्मृतियों को जीवन के पृष्ठ में दर्ज करते हैं।

भूलने के बारे में मनोवैज्ञानिकों के अलग सिद्धांत रहे हैं। उन्हीं में से एक ट्रेस डिके सिद्धांत कहता है कि भूलना स्मरण शक्ति के अपने आप खत्म होने या बोझिल पड़ने की वजह से होता है। यह सिद्धांत कम अवधि की स्मृति के सीमित समय पर केंद्रित है। इसमें हमारी याददाश्त सिर्फ कुछ पलों के लिए किसी घटना पर केंद्रित होती है। अगर उस घटना को फिर से स्मरण के कोष में दोहराया न जाए, तो वह घटना स्मृति से हमेशा के लिए मिट जाती है। जैसे चलती ट्रेन में बैठकर देखे गए अधिकांश दृश्य हम आगे बढ़ते ही भूल जाते हैं। भूलने की लघु अवधि स्मरण सिद्धांत के अनुसार, जब यह लघु अवधि स्मृति 'पूर्ण' होती है, तो नई जानकारी पुरानी जानकारी को विस्थापित कर देती है या 'बाहर धकेल देती है' और उसका स्थान घेर लेती है। ऐसे में लघु अवधि स्मरण में विस्थापित स्मृतियां या घटनाएं मिट जाती हैं। भूलने के इंटरफेस सिद्धांत के अनुसार नई स्मृतियां पुरानी स्मृतियों से टकराकर उन्हें कमजोर कर देती हैं। धीरे धीरे वे मिट जाती हैं।

वैज्ञानिक सिद्धांत तो भूलने की व्याख्या करते ही हैं, हमारे अनुभव भी यही कहते हैं कि सहज स्वाभाविक तरीके से कुछ भूलना बीमारी नहीं। उल्टे यह हमारे मस्तिष्क को रोग मुक्त और संतुलित रखने में सहायक है। भूलने पर किए गए अनेक शोध बताते हैं कि भूलना सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मस्तिष्क में चल रही तमाम ऊल-जलूल बातें और त्रुटियों को भूल जाते हैं। एक तरह से भूलना दिमाग को छान कर फिर से ताजा करने की प्रक्रिया है। यह 'डिलीट करने' यानी मिटाने के बटन का काम करता है। पुरानी या बेकार की यादों को हटाता है और मस्तिष्क में नई चीजों के लिए जगह बनाता है। तो इस भाग-दौड़ से भरी जिंदगी में अगली बार अगर हम कुछ भूल जाएं तो खुद को कोसने के बजाय माफ कर देना चाहिए।

दुनिया मेरे आगे

> जब किसी का अतीत उसके मन-मुताबिक न रहा हो, तो उसकी स्मृतियां बोझ सरीखी लगती हैं। वे जब-तब स्मृति में आकर अंतर्मन को लहूलुहान कर देती हैं। इन रिसते घावों पर विस्मृति का मरहम लगा कर हम अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं। वर्तमान की घटनाओं को कटु होने से बचा लेते हैं।

विसंगति के बीच

देश का हर राजनीतिक दल किसी भी तरह सत्ता में आना चाहता है। भले ही उन साधनों से देश अथवा जनता का अहित क्यों न हो। यह विसंगतियों की राजनीति है। इसे स्वस्थ परंपरा नहीं कहा जा सकता। किसानों का ऋण माफ करना, बिजली-पानी मुफ्त कर देना, साइकिल आदि बांटना यहां तक कि अब चुनावों से पहले खाते में राशि डाल देने का भी चलन दिखने लगा है, जो साफ तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। इन सब अनैतिक साधनों में किसानों का ऋण माफ करना भी अनुचित है। उन्हें यह आभास कराया जाता है कि वे सरकार के कृपा पात्र हैं। जबकि उस ऋण की भरपाई भी पिछले दरवाजे से उसी किसान और जनता से ही की जाती है। देखने में आता है कि पार्टियां ऋण माफी के वादे तो कर लेती हैं, लेकिन सत्ता में आने पर उन्हें पूरा नहीं कर पातीं। इसके अलावा यदि सरकार उन किसानों का ऋण माफ भी कर देती है जो ऋण चुकाते नहीं या चुका पाने में असमर्थ होते हैं, तो यह उन किसानों के साथ अन्याय होता है जो समय पर ऋण चुका देते हैं।

- नरेंद्र टोंक, मेरठ

जीत में हार

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान कि हम जीत रहे हैं और ईरान को नष्ट किया जा रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि किसी भी युद्ध में इंसानियत की हमेशा हार ही होती है। आज जहां-जहां भी युद्ध हो रहा है, वहां विद्यालयों, अस्पतालों और निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं सहित हजारों नागरिक भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में कोई यह कैसे कह सकता है कि हम युद्ध जीत रहे हैं। इजराइल ने गाजा में फिलीस्तीन के लोगों को खाद्य वस्तुओं से दूर कर दिया। वहां के लोगों को भूखे-प्यासे मरने की नौबत आ गई। अमेरिका द्वारा भेजे गए हथियारों से इजराइल ने गाजा में तबाही मचा दी। मासूम बच्चों और मरीजों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमला कर वहां सैकड़ों लोगों को मार डाला। आज के हालात ऐसे हैं कि युद्ध को किसी की हार या जीत नहीं कहा जा सकता।

- चरनजीत, नरेला, दिल्ली

समानता का तकाजा

भारत एक संप्रभु देश है, जहां हर धर्म, समुदाय और जाति के लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी आड़ में असल समस्याओं की अनदेखी हो रही है। चुनाव के दौरान जाति के आधार पर समर्थन जुटाने की प्रवृत्ति समाज में विभाजन की भावना को उत्पन्न कर सकती है। इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती हैं। विभिन्न राज्यों के चुनाव को देखते हुए सरकार को शिक्षा, विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और लोक निर्माण जैसे मुद्दों को महत्त्व देना चाहिए। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए नियम चर्चा का विषय बना, जिससे नाहक विवाद हुआ। गौरतलब है कि इस साल पश्चिम बंगाल और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आम नागरिकों को ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ता है, जब समानता और भाईचारा हो।

- प्रियंका साव, जम्मू

जोखिम के वाहन

हाल ही में इंदौर से आई एक खबर के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के दौरान धमाके के बाद उठी आग की लपटों ने पलभर में आठ जिंदगियां लील लीं। इससे पहले पांच मार्च को दिल्ली में चलती इलेक्ट्रिक बस धधक उठी। किसी तरह एक बड़ा हादसा टला। इसी के साथ यह सवाल अब और गहरा हो गया है कि क्या हमारे इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षित हैं? हालांकि इन वाहनों को अपनाना समय की जरूरत है। प्रदूषण घटाने और ईंधन बचाने का यह ठोस उपाय है। मगर अभी इसमें कई खामियां दिखाई दे रही हैं। बैटरी का बेहद गर्म हो जाना, खराब चार्जिंग पाइंट और रखरखाव में लापरवाही, ये सभी आग को न्योता दे रहे हैं। हाल के वर्षों में बढ़ती घटनाएं और तकनीकी रपटें इसी खतरे की पुष्टि करती हैं। समस्या को टालने और समाधान ढूंढ़ने में देरी से जोखिम बना रहेगा।

- आरके जैन 'अरिजीत', बड़वानी

बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा

विकास परियोजनाओं में रोड़े न अटकाएं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना के एक गलियारे के निर्माण में बाधाएं पैदा करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आम जनता के हित वाली विकास परियोजना का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट को परियोजना की निगरानी करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, 'हाई कोर्ट ने आपके (राज्य सरकार के) प्रति काफी उदारता दिखाई है। यह ऐसा मामला था, जिसमें आपके मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।' प्रधान न्यायाधीश ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, 'यह आपके संवैधानिक कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी को दर्शाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।

पीठ ने कहा, 'हाई कोर्ट ने आपके (राज्य सरकार के) प्रति काफी उदारता दिखाई है। यह ऐसा मामला था, जिसमें आपके मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।' प्रधान न्यायाधीश ने बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, 'यह आपके संवैधानिक कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी को दर्शाता है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यह एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश है, जहां कोई मुद्दा ही नहीं है।

यह एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश है, जहां कोई मुद्दा ही नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि राज्य सरकार किसी विकास के मुद्दे का राजनीतिकरण करे, जो कि आम आदमी के लिए फायदेमंद है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'हमें हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यह विकास से जुड़ा मुद्दा है।

यह आम जनता की सुविधा के लिए है। इसमें बाधाएं पैदा नहीं करें।' जब राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि आगामी चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है और बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश 23 दिसंबर 2025 का है और पूछा कि राज्य सरकार ने तब से अब तक निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस परियोजना पर आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि यह पहले से चल रही है और हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है।

उन्होंने कहा, 'आपके लिए त्योहार विकास से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। यह आपकी इच्छा नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य है। क्या त्योहार परिवहन परियोजना के निर्माण से ज्यादा जरूरी हैं? उन्होंने कहा, 'यह परियोजना आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू की गई थी।

हम राज्य को इसे फिर से विकास में बाधा डालने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सड़कें बंद करनी पड़ेंगी, जिससे एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने मई तक का समय मांगा, लेकिन शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया और 23 दिसंबर 2025 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करने की बात कही।

पीठ ने कहा, 'यह अधिकारियों के हठी रवैये को दर्शाता है, जो कोलकाता मेट्रो परियोजना को टालने और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं है और हमें विश्वास है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को साल्ट लेक के सेक्टर-5 स्थित आइटी हब को दक्षिण कोलकाता के बड़े इलाकों से जोड़ने वाली परियोजना के पूरा होने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की, जिसमें देरी पुलिस द्वारा नाकाबंदी की अनुमति को लेकर गतिरोध के कारण हो रही है। अदालत ने निर्देश दिया था कि काम 15 फरवरी, 2026 तक पूरा किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, डीजीपी से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

हरियाणा में बच्ची से बलात्कार के मामले की जांच को लेकर पुलिस के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया को चौकाने वाला तथा असंवेदनशील बताया। याचिका पर पीठ ने हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

गुरुग्राम में बच्ची से बलात्कार का मामला।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 25 मार्च को पूरे रिकार्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस शिकायत पर भी गंभीर चिंता जताई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्ची का बयान आरोपियों की मौजूदगी में दर्ज किया। पीठ ने गुरुग्राम की सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करे।

इस पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा-यह बेहद चौकाने वाला है कि पुलिस इस तरह असंवेदनशील व्यवहार कर रही है, खासकर एक महानगर में, जहां एक आघात झेल रही बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि पुलिस अधिकारी माता-पिता से पूछ रहे थे कि वे क्या करना चाहते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है और उन्हें कानून की बुनियादी समझ होनी चाहिए।

यह याचिका बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर की गई थी। इसमें हरियाणा पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए मामले की जांच सीबीआइ या विशेष जांच दल से कराने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जांच अधिकारी माता-पिता पर प्राथमिकी वापस लेने का दबाव बना रही थी। उन्होंने बताया कि बच्ची का बयान ऐसे समय लिया गया जब आरोपी पास में मौजूद थे।

सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के बाद अस्थायी उत्तर कुंजी जारी करेगा यूपीएससी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

राज्यसभा में सरकार ने सोमवार को बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद अपनी वेबसाइट पर अस्थायी उत्तर कुंजी जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं। यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) आदि के लिए अधिकारियों के चयन के लिए प्रतिवर्ष तीन चरणों – प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार – में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न में लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में, यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अस्थायी उत्तर कुंजी जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं। सिंह ने कहा कि यह प्रक्रिया, जो 2026 की सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा से लागू होगी, यूपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू होगी। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विषयों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यूपीएससी अंतर-विषय 'माडरेशन' लागू करता है। सिंह ने कहा कि पारंपरिक/वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं के माडरेशन/मूल्यांकन में शामिल प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्री से वैकल्पिक विषयों तथा 'सिविल सेवा एप्टीट्यूट टेस्ट' में आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रक्रिया का मानकीकरण किए जाने के बारे में प्रश्न किया गया था।

बजट सत्र

नई दिल्ली में सोमवार को संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, इमरान मसूद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य।

शीत भंडार ढहने से चार मजदूरों की मौत

प्रयागराज जिले का मामला; 12 मजदूरों की हालत नाजुक, गैस रिसाव से मची अफरा-तफरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

प्रयागराज जिले में गंगा नगर के फाफामऊ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक शीत भंडार के अचानक ढह जाने से चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 12 श्रमिक घायल हो गए। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि शीत भंडार ढहने की घटना में अभी तक चार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 12 श्रमिक घायल हैं जिनका इलाज एसआरएन अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल से मलबा हटाकर लोगों की तलाश रही है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-गंगा नगर) कुलदीप गुनावत ने बताया कि फाफामऊ थाना क्षेत्र में एक शीत भंडार सोमवार दोपहर अचानक भर भराकर ढह गया और उससे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है तथा अग्निशमन विभाग की टीम भी सक्रिय है जो गैस रिसाव रोकने की दिशा में काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 'एक्स' पर प्रधानमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा

प्रधानमंत्री ने अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नियंत्रण में हैं। इसी कारण सोमवार को संसद में अपने 25 मिनट के भाषण में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध पर प्रधानमंत्री ने संसद में भाषण दिया, लेकिन वह इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ बहस में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि वे 'काम्प्रोमाइज्ड' हैं। राहुल गांधी गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि के दरवाजे किसी दूसरे देश के लिए खोले हैं।

उन्होंने कहा कि पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि के दरवाजे किसी दूसरे देश के लिए खोले हैं। छोटे किसान अमेरिका की मशीनीकृत खेती के सामने टिक नहीं पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। देश का पूरा आंकड़ा अमेरिका को सौंप दिया गया है। इसके अलावा भारत अगले पांच साल हर वर्ष लगभग नौ लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदेगा, इससे भारत के लघु और मध्यम उद्योग तबाह हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस या ईरान से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की अनुमति लेने की बात स्वीकार कर ली है। उनके मुताबिक व्यापार समझौते से अमेरिका के लिए तो टैरिफ कम हो गया है, लेकिन बदले में भारत को कुछ लाभ नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और भाजपा का पूरा वित्तीय ढांचा अडाणी से जुड़ा है। नरेंद्र मोदी ने देशभर के बंदरगाह, हवाई अड्डे, सीमेंट कंपनी, सौर ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्र अड़ाणी को सौंप दिए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा-आरएसएस जानबूझकर 'वनवासी' शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सके।

एनआइए ने जम्मू कश्मीर में नौ स्थानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआइए) ने पिछले साल लाल किला के पास कार में हुए बम धमाके के मामले सोमवार को जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। एनआइए ने छह जिलों श्रीनगर, बारामूला, जम्मू, कुलगाम, गांदरबल और हंदवाड़ा में नौ स्थानों पर तलाशी ली। एनआइए के एक बयान में कहा गया कि छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और उन्हें फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया।

लाल किला के पास बम विस्फोट का मामला।

गौरतलब हो कि पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला के पास एक कार में बम विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह विस्फोट आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने अंजाम दिया था। उसने लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार में खुद को उड़ा लिया था।

नबी हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में चिकित्सक और सहायक प्रोफेसर था। एनआइए ने जांच के दौरान पाया कि नबी ने गिरफ्तार सह-आरोपियों और अन्य के साथ समन्वय में विस्फोट की साजिश रची थी। एजंसी ने कहा कि वह आतंकी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा करने और देश में अराजकता फैलाने तथा अस्थिरता पैदा करने की साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

पेज 1 का बाकी

ईरान से वार्ता, बिजली संयंत्रों पर पांच दिनों तक हमले नहीं : ट्रंप

हुआ, तो वह 'पूरे फारस की खाड़ी' में समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। रक्षा परिषद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब तेहरान में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी मरीन नौसैनिक क्षेत्र में तैनात किए जा सकते हैं।

युद्ध के बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव दिखा है। उन्होंने घोषणा की कि ईरान को होर्मुज फिर से खोलने के लिए दी गई समय सीमा सोमवार को बढ़ा दी गई है। अमेरिका पांच दिन के लिए बिजली संयंत्रों पर हमले नहीं करेगा। इसके ठीक बाद ईरानी सरकारी टेलीविजन की स्क्रीन पर एक ग्राफिक में कहा गया, 'ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे हटे।'

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच 'बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत' हुई है, जिससे युद्ध का 'पूर्ण और निर्णायक समाधान' निकल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत 'पूरे सप्ताह' जारी रहेगी। ट्रंप ने राजनयिक वार्ताओं के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है, तो अमेरिका उसके संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए कदम उठाएगा, जो परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण है। ईरान ने ट्रंप के बातचीत के दावे को गलत बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय एवं अर्द्धसैन्य बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले से दो समाचार एजंसियों ने दावा किया कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।

इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उन्होंने तुर्किये के अपने समकक्ष हाकान फिदान से फोन पर बात की। ईरान की फार्स न्यूज एजंसी ने एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप के तेहरान के साथ 'सार्थक' वार्ता के बारे में हालिया बयान के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचार नहीं है। फार्स ने कहा कि ईरान द्वारा क्षेत्र के सभी बिजली संयंत्रों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करने की बात सुनने के बाद ट्रंप पीछे हट गए थे।

सूचकांक और रुपए में गिरावट जारी, निवेशकों के 14 लाख करोड़ डूबे

94.03 (अस्थायी) पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 50 पैसे की गिरावट है। शुक्रवार को भी रुपया 64 पैसे टूटकर 93.53 प्रति डालर पर बंद हुआ था, जिससे यह 93 के स्तर के पार चला गया था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.14 फीसद बढ़कर 99.78 पर कारोबार कर रहा था।

वहीं, स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को भारी गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 1,837 अंक का गोता लगा गया, जबकि एनएसई निफ्टी 602 अंक लुढ़क गया। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त होने के कोई संकेत नहीं होने के साथ वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख से घरेलू बाजार में गिरावट रही। बीएसई पर पंजीकृत करीब 5000 कंपनियों के कुल बाजार पूंजी में शुक्रवार की तुलना में सोमवार को हुई गिरावट की वजह से करीब 14 लाख करोड़ की गिरावट हुई है। शुक्रवार को कुल बाजार पूंजी 42876298.38 करोड़ रुपए था, जो घटकर 41503895.21 करोड़ रुपए रहा। इस तरह एक सत्र में 13.72 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। युद्ध के चौथे सप्ताह में पहुंचने के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर पूंजी निकासी और रुपए की विनिमय दर में गिरावट को देखते हुए निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,836.57 अंक यानी 2.46 फीसद टूटकर 72,696.39 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान एक समय यह 1,974.52 अंक का गोता लगाकर 72,558.44 अंक पर आ गया था। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 601.85 अंक यानी 2.60 फीसद लुढ़ककर 22,512.65 अंक पर बंद हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 48.29 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज हुई और यह 415 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संभावित कमी को लेकर चिंताओं के बीच एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के साथ घरेलू बाजारों में भारी गिरावट आई।

वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) ने 5,706.23 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से 88,180 करोड़ रुपए (लगभग 9.6 अरब अमेरिकी डालर) निकाले हैं। सेंसेक्स शुक्रवार को 325.72 अंक चढ़कर 74,532.96 अंक पर बंद हुआ था। निफ्टी 112.35 अंक की तेजी के साथ 23,114.50 अंक पर रहा था।

'भ्रष्टाचार ले चुका अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, संपत्ति की वसूली जरूरी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक वैश्विक सम्मेलन में कहा कि संपत्ति की वसूली कोई बाद की प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रवर्तन की सफलता का सबसे सटीक मापदंड है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इसी कार्यक्रम में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशक ने इस बात पर बल दिया कि आज भ्रष्टाचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है, परिष्कृत हो चुका है और प्रौद्योगिकी द्वारा तेजी से इसे मदद मिल रही है।

भारत में 23 से 25 मार्च तक आयोजित हो रही ग्लोब-ई नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ईडी निदेशक ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 'अपराध की आय का पता लगाने, उसे रोकने, जब्त करने और वापस लौटाने' के एजंसी के दायित्व का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन में निहित आधुनिक भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के तहत, संपत्ति की वसूली प्रवर्तन परिणामों के लिए केंद्रीय है और प्रवर्तन सफलता का सबसे सच्चा मापदंड है।

भारत के प्रदर्शन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों सहित लगभग 5.6 अरब अमेरिकी डालर की संपत्ति वापस दिलाई है, जिसमें से एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हाल के वर्षों में हासिल किया गया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डालते हुए एक ऐसे मामले में स्पेन द्वारा दी गई सहायता का उदाहरण दिया, जहां (ग्लोबई) नेटवर्क के माध्यम से साझा की गई जानकारी के कारण औपचारिक चैनलों के माध्यम से संपत्तियों को जब्त करने में सीधे तौर पर मदद मिली।

इस अवसर पर सीबीआइ के निदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि आधुनिक भ्रष्टाचार से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग विकल्प का मामला, नहीं बल्कि एक परम आवश्यकता है।

पंजाब के पूर्व मंत्री भुल्लर गिरफ्तार

351 (3) (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (सामान्य इरादा) के तहत एक मामला दर्ज किया था। सोमवार को दिन में रंधावा के परिवार ने पंजाब सरकार को भुल्लर को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे की चेतावनी दी थी।

रंधावा की पत्नी एवं विज्ञान की शिक्षिका उपिंदर कौर ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर कुछ नहीं किया गया, तो वह अपने बच्चों (दो बेटियों और एक बेटे) के साथ सड़क पर उतर जाएंगी। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक कथित सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें रंधावा जहरीला पदार्थ खाते दिखे थे। विपक्षी दलों ने पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वहीं, भुल्लर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वे मंडी गोबिंदगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने भागने की अफवाहों को भी खारिज किया।

उन्होंने कहा कि मेरे भागने की अफवाहें फैलाई जा रही थीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं कभी सच्चाई से नहीं भागूंगा। भुल्लर ने कहा कि मुझे देश के कानून पर पूरा भरोसा है और न्याय व्यवस्था पर भी मेरा अटूट विश्वास है। मैं कहीं भागा नहीं हूं, मैं अपने पंजाब में ही हूं। सत्य और न्याय में विश्वास रखते हुए, मैं मंडी गोबिंदगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहा हूं।

होर्मुज में रुकावट स्वीकार्य नहीं, कूटनीति ही समाधान

से जुड़ी सभी एजंसियों को सतर्क रखा गया है। उन्होंने कहा, 'हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है।

धीरज, संयम और शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार है, वहीं 65 लाख टन से अधिक भंडारण पर काम किया जा रहा है।प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के हालात ने भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, 'युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग एक हजार भारतीय सुरक्षित वापस आए हैं। इनमें मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 700 से अधिक युवा हैं।'

मोदी ने कहा, 'मैंने स्वयं पश्चिम एशिया के संबंधित नेताओं से बात की है। उनसे तनाव कम करने और संघर्ष खत्म करने का आग्रह किया है। भारत इस हालात में युद्ध के माहौल में कूटनीति के जरिए भारतीय जहाजों के निरंतर आवागमन के लिए प्रयासरत है। मैं फिर कहूंगा कि इस समस्या का समाधान कूटनीति और बातचीत से ही संभव है। मोदी ने कहा कि तटीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है।

महिला आरक्षण के लिए दो विधेयक की तैयारी

31 मार्च, 2029 को लागू हो जाएंगे और लोकसभा के अलावा ओड़ीशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में सीट के आरक्षण में मदद करेंगे। सूत्रों ने बताया कि परिसीमन या सीमा आयोग एक निष्पक्ष निकाय है जिसे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

इसके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसे अखिल भारतीय परिसीमन प्रक्रिया संचालित करने का दायित्व नहीं दिया जा सकता। एक सरकारी पदाधिकारी ने बताया, 'अधिक से अधिक, यह एक या कुछ राज्यों का परिसीमन कर सकता है, जैसा कि इसने हाल ही में असम में परिसीमन किया था। परिसीमन प्रक्रिया के अलावा, इसके द्वारा उन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकता है जिन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

अंधश्रद्धा निर्मूलनाची वाट खडतर !

‘बाईबळीवर बोळवण ?’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी शेकडो प्रकरणे दाखल झालेली आहेत आणि अनेक प्रकरणांत भोंदू बुवांना शिक्षादेखील ठोठावण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे अशा बऱ्याच प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र अंनिसचे कार्यकर्ते बुवा-बाबांच्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या लोकांना गुन्हा दाखल करण्यासाठी मदत, मार्गदर्शन करतात आणि प्रकरणांचा पाठपुरावा करतात.

अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार (कोणत्याही पक्षाचे असो) किती उदासीन आहे याची प्रचीती पुढील बाबींवरून लक्षात येते:

■ डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर हा कायदा पारित झाल्यावर कायद्याअंतर्गत नियम करणे आवश्यक आहे. परंतु सरकार याबाबत काहीही पावले उचलत नसल्याने या नियमांचा मसुदा अंनिसने ‘बार्टी’ आणि ‘यशवंतराव चव्हाण सेंटर’ येथील विशेषज्ञांच्या मदतीने तयार करून सरकारकडे काही वर्षांपूर्वी सादर केला आहे. याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही हे नियम अद्याप जारी करण्यात आलेले नाहीत.

■ या कायद्यानुसार पोलीस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलनविषयक विशेष कक्ष स्थापन करून एक दक्षता अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे, ज्या योगे अंधश्रद्धा प्रकरणांवर विशेष लक्ष देता येईल, परंतु किती पोलीस ठाण्यांनी असे कक्ष स्थापून दक्षता अधिकारी नेमले हा संशोधनाचा विषय आहे. या कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अंनिसतर्फे पोलिसांसाठी प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात. या कायद्याअंतर्गत स्थापित विशेष समितीची बैठकच कित्येक वर्षांत झालेली नाही, असे या समितीचे सदस्य सांगतात.

प्रबोधन करणाऱ्या अंनिस कार्यकर्त्यांना सनातनी प्रवृत्ती व्यक्तींकडून प्रखर विरोधाचा सामना करावा लागतो. बदनाम केले जाते. काही काळापूर्वी सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदारांनी अंनिस कार्यकर्त्यांना नवीन जनसुरक्षा कायदा लावण्याची मागणी केली होती. सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते. एसआयटी वगैरे नेमली असली तरी या प्रकरणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे अनेक नेते गुंतलेले असल्याने, पुढे राम रहीम किंवा आसाराम प्रकरणांत जे झाले ते या प्रकरणातदेखील होईल अशी भीती वाटते. अंधश्रद्धा निर्मूलन किती अवघड झाले आहे हे यावरून लक्षात येईल.

■ **उत्तम जोगदंड** (कल्याण)

गर्जेल तो बरसेल काय ?

‘बाईबळीवर बोळवण ?’ हा अग्रलेख वाचला. भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पट्टशिष्य राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या केवळ राजीनाम्याने भागणार नाही. भोंदूबाबांशी ज्यांची तथाकथित वलयांकितांची नावे जोडली गेली आहेत त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाणे गरजेचे आहे. रुपाली चाकणकरांसारख्या अनेकांची ऊठबस या भोंदूबाबांकडे असल्यामुळेच सामान्यही त्याच्याकडे ओढले गेले. आता मुख्यमंत्र्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेतला आहे, पण तपास यंत्रणांनी कसा तपास करायचा, याचे अप्रत्यक्ष निर्देशच राज्याचे कारभारी देत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, गय करणार नाही, सोडणार नाही अशा गर्जना केल्या जातात, मात्र काही काळाने त्या हवेत विरलेल्या दिसतात. त्यामुळे गर्जेल तो बरसेल काय, असा प्रश्न पडतो.

■ **श्रीकांत जाधव,** अतीत (सातारा)

अंधश्रद्धांच्या गर्तेत नेणारे राजकारण

‘बाईबळीवर बोळवण ?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ मार्च) वाचला. भक्तांची व जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या, ‘चमत्कार हेच आपले ओळखपत्र’ असा दावा करणाऱ्या एका तथाकथित गुरूची पाद्यपूजा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यावर यापूर्वी झाली आहे. नंतरच्या काळात हा गुरुमहिमा उत्तरोत्तर वाढत गेला. अगदी धार्मिक विद्वेष, अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांबाबत ‘आमचे वंदनीय गुरू’, असे भर विधानसभेत म्हणण्यापर्यंत सत्ताधाऱ्यांची मजल गेली. वादग्रस्त धार्मिक गुरूंचा जथा मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या मंचावरही जमवला गेला. त्यातून धर्म आणि राजकारणाची अभद्र युती भद्र करून घेण्यात आल्याचा स्पष्ट संदेश महाराष्ट्राला मिळाला. धार्मिक प्रवचनांना होणाऱ्या लाखोंच्या गर्दीचा राजकारणासाठी वापर होऊ लागला. अनैतिक, संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या राजकारण्यांचे भक्कम पाठबळ बाबा-बुवांना मिळत गेले. त्यामुळे सामान्य जनतेची अगतिकता, अज्ञान अशा पोषक वातावरणात बुवाबाजीचे पीक फोफावले नसते तरच नवल. ‘श्रद्धा दुखवल्या जातील’ या सबबीखाली प्रश्न विचारणे खुंटले. महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असूनही भोंदूगिरीचे असे प्रकार घडतात, कारण समाजाला अंधश्रद्धांच्या गर्तेत नेणारे राजकारण, हे आहे.

■ **राजेंद्र फेगडे,** नाशिक

सर्व संबंधितांचे राजीनामे घ्या !

‘बाईबळीवर बोळवण ?’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. सध्या बुवा-बापू यांची चलती आहे, कारण देशातील व राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते भोंदूबाबांच्या मागे लागले आहेत. त्यांच्यावर राजकारण्यांचा वरदहस्त असल्याने त्यांनी आपले हातपाय पसरले आहेत. ज्या राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यावर भोंदूबाबांची असे कारनामे करण्याची हिंमत होते, त्या सर्व राजकीय नेत्यांची ही काळी बाजू लोकांपर्यंत आली पाहिजे. त्यांचे वास्तव अंधभक्तांनाही कळले पाहिजे. नेत्यांनाही अद्दल घडवली पाहिजे. चाकणकर यांचा राजीनामा ही केवळ मलमपट्टी आहे. भोंदू खरातने अनेक सरकारी अधिकारी व राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून जी काळी माया जमवली आहे, त्याच्या पापाच्या वाटेकऱ्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात शाहू, फुले, आंबेडकर यांची नावे घेऊन राजकारण करायचे आणि अशा भोंदूबाबांच्या पायावर डोके ठेवायचे, हा दुटप्पीपणा आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सर्व संबंधितांचे राजीनामे घ्यावेत, तरच पीडित महिलांना खरा न्याय मिळेल. त्यासाठी या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्षपाती चौकशी करावी.

■ **प्रा. जयवंत पाटील,** भांडुप (मुंबई)

श्रद्धा हे प्रतिमानिर्मितीचे साधन ?

नेतेच बाबांकडे जात असतील तर जनता तेथे जाणारच, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजकाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करून, जनतेत मी किती श्रद्धाळू आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न सर्वपक्षीय व सर्वधर्मीय नेते करताना दिसतात. यातून ते जनतेत लोकप्रिय होण्याचा मार्ग शोधत असतात, पण आपले आचार, विचार शुद्ध असतील व त्यात प्रामाणिकपणा असेल तर आपणास आपोआप लोकप्रिय होता येईल, त्यासाठी बाबा-बापूंचा आधार घेण्याची गरजच राहणार नाही, हे शाहू, फुले, आंबेडकरांनी सांगितलेले त्रिकालाबाधित सत्य, नेत्यांना जेव्हा समजेल, तो सुदिन ठरावा.

■ **प्रदीप करमरकर,** ठाणे

खेळात राजकारण न आणणेच योग्य

‘गावस्करांचा अनाठायी तळतळाट’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ मार्च) वाचला. सुनील गावस्कर यांनी आणि आपल्या सरकारनेही खेळात राजकारण आणणे पटत नाही. क्रिकेटच्या खेळात पाकिस्तानी खेळाडूंशी आपले खेळाडू हस्तांदोलन करत नाहीत. बांगलादेशी खेळाडूंना आपल्या देशात होणाऱ्या आयपीएलमध्ये सहभागी होता येत नाही. हे सर्व काय चालले आहे ? या दोन देशांशी आपले राजकीय संबंध बरे नाहीत म्हणून ? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा हे आयसीसीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. निदान त्यांनी तरी हे टाळले पाहिजे. यामुळे दोन देशांतील तेढ वाढतच जाणार आहे. राजकारण आणि खेळ हे एकमेकांपासून दूर ठेवणेच योग्य आहे. खेळात भावनिक मुद्दे आणि राजकारण नकोच !

■ **प्रभाकर कदम,** मुलुंड

गावस्कर यांची भूमिका दुटप्पी !

‘गावस्करांचा अनाठायी तळतळाट’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. गावस्कर हे रमीज राजा, वसीम आक्रम यांच्याबरोबर समालोचन करतात त्यावेळी रमीज आणि आक्रम यांना जे काही मानधन मिळते त्यावरील टॅक्सही पाक सरकारलाच मिळतो हे गावस्करांना माहीत नाही काय ? गावस्करांना ते खुपत नाही ? हा निव्वळ दुटप्पीपणा नव्हे का ? सूर्यकुमार यादवसारख्याने काहीतरी बरळणे आणि गावस्करसुद्धा आता तसेच काही बोलू लागणे हा ‘नवीन भारत’ आहे.

■ **शेखर कारेकर,** कोल्हापूर

वैद्यकीय क्षेत्राला नवी दिशा...

‘पल्स-२०२६’ ही परिषद महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय क्षेत्रासाठी केवळ एक कार्यक्रम नसून भविष्यातील वैद्यकीय व्यवस्थेची दिशा ठरविणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, तंत्रज्ञान, उद्योग आणि शासन यांचा समन्वय घडवून वैद्यकीय क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडविण्याचा प्रयत्न या परिषदेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

वर्षा फडके - आंधळे
उपसंचालक (वृत्त)

पहिली बाजू

महाराष्ट्राने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांप्रमाणेच वैद्यकीय सेवेतही आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण, अत्याधुनिक रुग्णालये, संशोधन संस्था आणि कुशल डॉक्टर यांच्या बळावर राज्य देशाच्या वैद्यकीय व्यवस्थेत अग्रस्थानी आहे. या क्षमतेला जागतिक स्तरावर अधोरेखित करण्यासाठी २७ व २८ मार्च २०२६ रोजी ‘पल्स-२०२६’ पल्स (PULSE) प्लॅटफॉर्म फॉर युनिफाइड लर्निंग, स्किल्स, हेल्थ अँड एज्युकेशन ही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे होणार असून राज्यात वैद्यकीय क्षेत्राचा विस्तार होण्याच्या दृष्टीने ती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील वैद्यकीय व्यवस्था सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित केल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. राज्याची वैद्यकीय व्यवस्था अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानसज्ज, संशोधनप्रधान आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. परिषदेत वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्रातील विद्यार्थी, अधिष्ठाता, विशेषज्ञ, खासगी शैक्षणिक संस्था तसेच आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक कंपन्या सहभागी होणार आहेत. राज्याच्या आरोग्य पर्यटनाचा आणि ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी या परिषदेची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.

राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या पुढाकारातून आयोजित होणारी ही परिषद वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय सेवा व्यवस्थापन आणि वैद्यकीय पर्यटन यांना एकत्र आणणारा व्यापक मंच आहे. या परिषदेत देश-विदेशातील नामवंत डॉक्टर, संशोधक, वैद्यकीय शिक्षणतज्ज्ञ, वैद्यकीय क्षेत्रातील धोरणनिर्माते तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. आधुनिक वैद्यकीय व्यवस्थेतील आव्हाने आणि त्यावरील उपाय यावर सखोल चर्चा होण्यासाठी हे एक व्यासपीठ ठरेल.

महाराष्ट्राचा जागतिक लौकिक

वैद्यकीय सेवा ही केवळ उपचारांपुरती मर्यादित नसून ती आर्थिक प्रगतीची मोठी संधीही ठरू शकते. जागतिक स्तरावर ‘मेडिकल टुरिझम’ म्हणजेच वैद्यकीय पर्यटनाचा वेगाने विस्तार होत आहे. कमी खर्चात दर्जेदार उपचार मिळण्याच्या दृष्टीने भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्राकडे अनेक देशांचे लक्ष वेधले जात आहे. ‘पल्स-२०२६’ परिषद ही संधी अधिक प्रभावीपणे मांडण्याचे काम करणार आहे. महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण संस्था, सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालये आणि संशोधन केंद्रांची मोठी संख्या आहे. या क्षमतेचा उपयोग करून राज्याला जागतिक वैद्यकीय सेवेत एक प्रभावी केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. परिषदेकरिता जगभरातून २९०० पेक्षा जास्त तज्ज्ञ, जवळपास १३० नामांकित डॉक्टर्स, वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील अभ्यासक संशोधक येणार आहेत. या परिषदेत वेगेवेगळी २० सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.

राज्य वैद्यकीय क्षेत्रात अग्रगण्य असून देश-विदेशातील तज्ज्ञ, संशोधक, उद्योगपती आणि धोरणकर्ते या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या सहभागामुळे नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक उपचारपद्धती आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक राज्यात येण्यास मदत होईल. याचा थेट फायदा रुग्णांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्यात, डॉक्टरांना नवीन संधी उपलब्ध होण्यात आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण व संशोधनाचा अनुभव मिळण्यात होणार आहे. विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांची माहिती प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळणे, आयुष क्षेत्रात आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी यांच्यात समन्वय साधून एकात्मिक वैद्यकीय व्यवस्था निर्माण करणे, फार्मसी क्षेत्रातील नवीन संशोधन, डॉक्टरांचे संशोधन पेपर आणि नवकल्पना यांचे सादरीकरणही परिषदेत होणार आहे.

वैद्यकीय वेलनेस पर्यटन

‘पल्स - २०२६’ परिषदेमार्फत महाराष्ट्राला वैद्यकीय वेलनेस पर्यटनाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. ‘महाराष्ट्र ब्रँड’ म्हणून वैद्यकीय पर्यटनाची ओळख निर्माण करण्यासाठी राज्यातील रुग्णालये, वेलनेस केंद्रे, संशोधन संस्था आणि पर्यटन क्षेत्र यांच्यात समन्वय निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे राज्यात वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढणार आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय उपकरणे, जैवतंत्रज्ञान, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांना नवी चालना मिळणार आहे. याचा थेट परिणाम रोजगारनिर्मितीवरही होईल.

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनाला चालना

‘पल्स-२०२६’ परिषदेत वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणा आणि संशोधनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ, रोबोटिक सर्जरी, टेलीमेडिसिन यांसारख्या नव्या संकल्पना वैद्यकीय शिक्षणात कशा समाविष्ट करता येतील यावर या परिषदेत सखोल चर्चा होणार आहे. आज वैद्यकीय क्षेत्र अत्यंत वेगाने बदलत आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे निदान आणि उपचार पद्धती अधिक अचूक आणि परिणामकारक होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक ज्ञान व कौशल्ये उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘पल्स-२०२६’ ही परिषद त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. ‘डिजि होम’ आणि ‘टेक टॉक’ या विशेष संकल्पनासुद्धा या परिषदेत असतील. ३६० डिग्री डोममध्ये रोबोटिक सर्जरी, व्हर्च्युअल रिॲलिटीमध्ये मेडिकल प्रशिक्षण, डिजिटल हॉस्पिटल व्यवस्थापन यासारख्या तंत्रज्ञानाचे लाईव्ह आणि इमर्सिव्ह प्रेझेंटेशन सादर केले जाणार आहे.

ग्रामीण भागांतही दर्जेदार सेवा

वैद्यकीय क्षेत्रातील विकास हा केवळ शहरांपुरता मर्यादित राहून चालणार नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा पोहोचविणे ही मोठी गरज आहे. ‘पल्स-२०२६’ परिषदेमुळे ग्रामीण वैद्यकीय सेवेसाठी नव्या संकल्पना आणि उपाययोजना समोर येतील. टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ युनिट्स, डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्स आणि आधुनिक निदान तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने ग्रामीण भागातही दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देता येऊ शकते. या तंत्रज्ञानांचा वापर कसा वाढवता येईल यावर परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे.

नवकल्पनांचा संगम

‘पल्स-२०२६’ परिषद ही केवळ वैद्यकीय चर्चांपुरती मर्यादित नसून वैद्यकीय क्षेत्रातील नवकल्पनांचा संगम घडविणारा मंच ठरणार आहे. या परिषदेत स्टार्ट-अप्स, संशोधन संस्था, औषधनिर्मिती उद्योग, वैद्यकीय उपकरण उत्पादक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या सहभागी होणार आहेत. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील नव्या कल्पना आणि संशोधनाला प्रत्यक्ष उद्योगाशी जोडण्याची संधी मिळेल. वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील नवकल्पना समाजापर्यंत अधिक वेगाने पोहोचण्यासाठी अशा प्रकारच्या मंचांची आवश्यकता असते.

भविष्याचा आराखडा

आजच्या काळात वैद्यकीय व्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. नवीन रोगांचा उद्भव, वाढते वैद्यकीय खर्च, तंत्रज्ञानाचा वेगाने होणारा विकास आणि लोकसंख्येच्या वैद्यकीय गरजा, या सर्वांचा विचार करून भविष्यातील वैद्यकीय व्यवस्थेचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.

या परिषदेत विविध देशांतील अनुभव, संशोधन आणि तंत्रज्ञान यांचे आदानप्रदान होऊन वैद्यकीय व्यवस्थेत अधिक प्रभावी धोरणे तयार करण्यास मदत होईल. ‘पल्स-२०२६’ ही परिषद महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय क्षेत्रासाठी केवळ एक कार्यक्रम नसून भविष्यातील वैद्यकीय व्यवस्थेची दिशा ठरविणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, तंत्रज्ञान, उद्योग आणि शासन यांचा समन्वय घडवून वैद्यकीय क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडविण्याचा प्रयत्न या परिषदेमार्फत केला जाणार आहे.

डिजिटल हेल्थ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वैद्यकीय व्यवस्थेत महाराष्ट्राला देशात अग्रस्थानी नेणे, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनात जागतिक दर्जाचे केंद्र निर्माण करणे, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात मजबूत प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उभारणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा वैद्यकीय क्षेत्रातील जागतिक लौकिक अधिक दृढ होईल, तसेच राज्याला वैद्यकीय पर्यटन आणि सेवांच्या क्षेत्रात नवे स्थान मिळेल. ‘पल्स-२०२६’ ही परिषद महाराष्ट्राला जागतिक वैद्यकीय नकाशावर अधिक ठळकपणे अधोरेखित करेल, यात शंका नाही.

कुतूहल

साध्या ताटलीची फ्रिस्बी होऊ शकते ?

फ्रिस्बी म्हणजे बशीसदृश एक प्लास्टिकची थाळी एकमेकांकडे फेकून ती पकडण्याचा खेळ अनेक लहान मुलं खेळतात. पण खेळताना फ्रिस्बीऐवजी घरातली साधी ताटली वापरली तर काय होईल ? तीही फ्रिस्बीसारखी तरंगेल का ? खरं तर फ्रिस्बीच्या तरंगण्यात आणि फिरण्यात तिच्या आकाराला फार महत्त्व आहे. फ्रिस्बीचा आकार आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे वर्तुळाकार, कडेने गोलाकार, खालून पोकळ व सपाट असतो.

फ्रिस्बी टाकताना तिच्या उडण्याच्या दिशेने तिरपी करून फिरवून टाकली की ती लांबपर्यंत जाते. फ्रिस्बी हातातून उडवल्यावर ती स्वतःच्या वजनाएवढी हवा थोडी खाली आणि थोडी पुढच्या दिशेने ढकलते. या क्रियेची प्रतिक्रिया म्हणून फ्रिस्बी वर ढकलली जाते व तिरपी तरंगते.

स्थिर हवेत जेव्हा आपण फ्रिस्बी हवेत फेकतो, त्या वेळी हवेचे दोन प्रवाह तयार होतात. एक फ्रिस्बीच्या खालच्या बाजूला, जो फ्रिस्बी तिच्या वजनाइतकी हवा खालच्या बाजूला ढकलल्यामुळे होतो. दुसरा जरा गतिमान प्रवाह तिच्या वरच्या बाजूला तयार होतो.

जिथे गतिमानता असते तिथे दाब कमी पडतो, म्हणून फ्रिस्बीच्या वर असलेल्या हवेच्या प्रवाहात दाब कमी असून तिच्या खाली असलेल्या प्रवाहात दाब जास्त असतो. त्यामुळे फ्रिस्बी तरंगण्यास मदत होते.

फ्रिस्बीला तरंगण्यासाठी लागणारं खालच्या दिशेचं बल, हे खालच्या दिशेने प्रत्येक सेकंदाला हवा बाजूला सरकवणाऱ्या बलाइतकं असतं. ज्यावेळी फ्रिस्बी तरंगत असते, त्यावेळी ती तिच्या उभ्या आसाभोवतीही फिरत असते. फ्रिस्बीच्या आसाभोवती फिरण्यामुळे तिचा एकदिशीय वेग स्थिर राहतो व त्यामुळे तिची पातळी एकसमान राहू शकते. जर फेकताना फ्रिस्बी फिरवली नाही तर ती तरंगत लांबवर न जाता लगेच खाली पडते. म्हणजेच फ्रिस्बी लांब अंतरापर्यंत तरंगत जाताना स्वतःच्या उभ्या आसाभोवती फिरत राहते.

आता आपण पाहू की साधी ताटली फ्रिस्बीप्रमाणेच उडवली तरीही ती हवेत का तरंगत नाही ?

साध्या ताटलीला फ्रिस्बीप्रमाणे विशिष्ट आकार नसतो. वर्तुळाकार ताटलीची कडा गोलाकार नसते आणि तिचा खालचा भाग सपाट नसतो. त्यामुळे अशी ताटली हवेत फेकली की कमी दाबाचा प्रवाह ताटलीच्या वर व जास्त दाबाचा प्रवाह ताटलीखाली असे वेगवेगळ्या दाबाचे दोन हवेचे प्रवाह तयार होत नाहीत. त्यामुळे ताटली तरंगू शकत नाही. तसंच साध्या ताटलीचं वजन तिच्या उभ्या आसाभोवती एकसमानपणे विभागले नसल्यामुळे ताटली डुगडुगते आणि लगेच उलटी होऊन खाली पडते. म्हणूनच साधी ताटली घेऊन फ्रिस्बीचा खेळ खेळता येत नाही.

- डॉ. मुग्धा पत्की
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

धन्यवाद हृतिक, आदित्य !

*‘**राहुल गांधींना** बघताच आम्हा महिलांना असुरक्षित वाटते. ते टपोरीसारखे वागतात’ या वक्तव्याने देशभर खळबळ उडाल्याने कंगणा खुशीत होती. पक्षाने दिलेली जबाबदारी योग्यप्रकारे पार पाडल्याचे समाधानही तिच्या चेहऱ्यावर होते. चला, आपली खासदारकी आता सार्थकी लागली. त्या स्मृतीताईची जागा आपल्याला मिळण्यापासून आता कोणी रोखू शकत नाही असा विचार करत ती बंगल्यावर परतली तेव्हा सायंकाळ झाली होती. हा पप्पू संसदेच्या आवारात टीशर्टवर फिरून वाहिन्यांचे फुटेज वाया घालवत असतो. आपल्या वक्तव्याने याची चांगलीच कोंडी होईल आता. खास ठेवणीतले महिलास्त्र काढल्यामुळे गप्प बसण्याशिवाय पर्यायच नाही त्याच्याकडे, असा विचार करत तिने टीव्ही सुरू केला.*

आता मस्तपैकी एखादा सिनेमा बघायचा असे ठरवत तिने एक चॅनल लावले तर त्यावर ‘अग्निपथ’ सुरू. त्यात हृतिक रोशनला बघताक्षणी तिला दरदरून घाम फुटला. लगेच टीव्ही बंद करत ती बंगल्याच्या बाहेर आली. नको त्या जुन्या आठवणी, असुरक्षित करणाऱ्या असे स्वतःला समजावत कंगणाने हिरवळीवर शतपावली सुरू केली. सहज म्हणून तिची नजर कुंपणभिंतीकडे गेली तर पलीकडून हृतिक डोकावून बघत असल्याचा भास तिला झाला. त्यामुळे तिचे अंग थरथरू लागले. चालता चालता दोनदा तिने भिंतीकडे बघितले तर पुन्हा हृतिकच. नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. मला घाबरवण्यासाठी या पप्पूने हृतिकला बोलावले तर नसेल अशी शंका मनात येताच ती पुन्हा बंगल्यात शिरली. तिने थेट पक्ष मुख्यालयात फोन केला. पलीकडून उत्तर आले. ‘काळजी करू नका. आता यापुढचे काही दिवस तुम्हाला राहुलपासूनच असुरक्षित वाटायला हवे हे लक्षात असू द्या. तरीही तपासणीसाठी आम्ही पोलीस पाठवतो.’ मग पोलीस आले, त्यांनी सभोवताल पाहणी केली पण काहीच संशयास्पद आढळले नाही. थोडे हायसे वाटल्याने कंगणा शयनकक्षात गेली. विचार करता करता तिचा डोळा लागला.

पहाटे अचानक आवाज झाल्याने जाग आली तेव्हा तिला दोन घारे डोळे खिडकीतून बघत असल्याचे जाणवले. मांजर तर आपल्या बंगल्यावर नाही मग हे डोळे नेमके कुणाचे, या प्रश्नासरशी तिला आदित्य पांचोली आठवला. हो, हे त्याचेच डोळे, हा इथे काय करतो, यालाही त्या पप्पूने पाठवले काय ? तिने लगेच डोक्यावरून पांघरूण घेतले, हे डोळे आदित्यचे की अरमानचे यावरून तिचा गोंधळ उडाला. जवळच असलेला फोन वापरून तिने ‘स्टाफ’ला आत बोलावले. निरोप मिळताच सगळेच धावत आले. पुन्हा एकदा खिडक्यांची आतून बाहेरून तपासणी करण्यात आली. त्यावरचे पडदे नीट करण्यात आले. डोकावण्यासाठी कुणी येऊन गेल्याच्या पाऊलखुणासुद्धा बंगल्याच्या आवारात आढळल्या नाहीत. मॅडमना भुताने तर झपाटले नसेल अशी शंका नोकरांना आली पण ती बोलून दाखवण्याचे धाडस कुणाला झाले नाही.

सकाळी ती उठली तेव्हाही तिचे अंग थरथरत होते. त्याच अवस्थेत तिने पुन्हा पक्ष मुख्यालयात फोन लावला. माझ्याविरुद्ध कट शिजतोय अशी तक्रार केली. पलीकडून उत्तर आले. ‘मॅडम, तुम्ही भूतकाळ विसरा, वर्तमानकाळात जगायला शिका. तुमचा खरा शत्रू राहुल गांधीच आहे. इतरांमुळे असुरक्षित होऊ नका.’ घडलेला हा किस्सा नोकरांकरवी सर्वच खासदारांच्या वर्तुळात चर्चिला जाऊ लागला. राहुलच्या कानावर तो जाताच ते खळखळून हसले व साहाय्यकांना स्वतःचा फोन देत म्हणाले. ‘त्या हृतिक व आदित्यला धन्यवादाचे संदेश तातडीने पाठवा.’

राजवाडे विचारविश्व

साधनांच्या शोधमोहिमेची रूपरेषा

बखरींमधील मजकूर विश्वासार्ह नसेल, तर मग इतिहासाच्या अभ्यासकाने करायचे तरी काय, हा प्रश्न स्वाभाविकपणेच उद्भवणार, याची जाणीव असल्यामुळे राजवाड्यांनी त्या चिकित्सेनंतर लगेच या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते. तोपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या ‘काव्येतिहाससंग्रहा’तील ऐतिहासिक पत्रांची संख्या चांगली ५०० होती. ‘त्या पत्रांच्या साहाय्यानेच बखरींमधील मजकुराच्या खरेखोटेपणाचा निर्णय करावा लागेल; बखरींतील कालविपर्यासाचा परिहार हीच पत्रे करतील आणि बखरींत जी माहिती दिलेली नाही, तीसुद्धा हीच पत्रे देतील’, असा निर्वाळा राजवाड्यांनी आपल्या प्रस्तावनेत दिला. पुढे ती पत्रे कुणाकुणाच्या कारकीर्दीशी संबंधित आहेत, याबद्दलची आकडेवारीही त्यांनी दिली, त्याचप्रमाणे ‘भारतवर्ष’ या नियतकालिकातून पारसनीसांनी प्रसिद्ध केलेल्या ४९ ऐतिहासिक पत्रांमध्ये मोडीवाचनाच्या अतोनात चुका झाल्याचे तसेच पत्रांना जोडलेल्या टिपांमध्ये दिलेली माहिती इतिहासाला धरून नसल्याचे निरीक्षणही राजवाड्यांनी नोंदवले होते.

प्रस्तावनेतील विवेचनाचा पुढचा महत्त्वाचा वैशिष्ट्यपूर्ण टप्पा म्हणजे इतिहासाच्या जिज्ञासूंसाठी आगामी दहा-वीस वर्षांमध्ये करायच्या कामाबद्दल त्यांनी केलेली तपशीलवार मांडणी. ‘अशा व्यक्तींसाठी पहिले काम म्हणजे अस्सल कागदपत्रे शोधून काढून ती छापण्याचे आहे’, असे सांगून राजवाडे थांबले नाहीत, तर आपल्या त्या आवाहनाची सुस्पष्ट रूपरेषादेखील त्यांनी मांडली.

‘ऐतिहासिक कागदपत्रे महाराष्ट्रात शेकडो ठिकाणी आहेत, हिंदुस्थानातही पुष्कळ ठिकाणी आहेत. हिंदुस्थानच्या बाहेर अफगाणिस्तान, इराण इत्यादी देशांत व लिस्बन, पॅरिस, लंडन व ॲम्स्टरडॅम इत्यादी शहरांतही मराठ्यांच्या संबंधी कागदपत्रे सापडण्यासारखी आहेत. ब्रिक्स, ग्रांटडफ, म्याकेंझी इत्यादी गृहस्थांनी विलायतेत नेलेली कागदपत्रे लंडन येथे जाऊन शोधली पाहिजेत... शिवाजी, संभाजी, राजाराम व बाळाजी विश्वनाथ यांच्या कारकीर्दीसंबंधी अजून काहीच उपलब्ध झाले नाही. मुख्यतः शिवाजी महाराजांसंबंधी पत्रे सापडली पाहिजेत. महाराजांना जाऊन काही फार काळ झालेला नाही, सव्वाशे वर्षे अद्यापि व्हावयाची आहेत. शिवाजी महाराज व त्यांचे सरदार व मुत्सद्दी यांनी लिहिलेली पत्रे लक्षावधी असली पाहिजेत. महाराजांचा पसारा केवढा ! त्यांचा पराक्रम कसला अकटोविकट आणि त्यांचे धोरण किती लांबवर ! तेव्हा त्यांच्या अद्भुत चरित्रपटाच्या लाखो धाग्यांचा यथास्थित उलगडा करण्यासाठी त्यांचा व त्यांच्या मुत्सद्यांचा पत्रव्यवहार सापडला पाहिजे !’

कागदपत्रांबाबत कसली उणीव जाणवते आहे, ते स्पष्ट करताना राजवाड्यांनी लिहिले होते, ‘पहिल्या बाजीरावासंबंधी व बाळाजी बाजीरावाच्या १७५० पर्यंतच्या कारकीर्दीसंबंधी म्हणजेच शाहू महाराजांच्या संपूर्ण कारकीर्दीसंबंधीदेखील अद्याप जवळजवळ काहीच सापडलेले नाही, असेच म्हणणे भाग पडते. तसेच मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे, रघोजी भोसले, फत्तेसिंग भोसले, गोविंद हरी पटवर्धन, मुरारराव घोरपडे, संभाजी राजे कोल्हापूरकर, दमाजी गायकवाड, दाभाडे, यशवंतराव पवार, यमाजी शिवदेव, गमाजी यमाजी, बाबूजी नाईक बारामतीकर, आंग्रे, अंताजी माणकेश्वर, नारो शंकर, विठ्ठल शिवदेव इत्यादी पुरुषांचे पत्रव्यवहार सापडल्यावाचून इतिहासाची गुंतागुंत नीट उलगडावयाची नाही.’

राजवाड्यांनी समस्या मांडली तर खरी, पण तेवढ्यावर थांबून कार्यभाग कसा काय साधला जाणार होता ? त्यांनी त्या समस्येच्या निराकरणाचा मार्ग कोणता, याचा आराखडाही तयार केला होता. महाराष्ट्राच्या इतिहासाबद्दलच्या कागदपत्रांचा धांडोळा घ्यायचा झाला, तर तो कोणकोणत्या ठिकाणी घ्यावा लागेल, याची लांबलचक यादीच राजवाड्यांनी समोर ठेवली होती. थोडीथोडकी नव्हेत, तर ११३ स्थळांची नावे त्यांच्या त्या यादीत होती. अयोध्या-काशी-अलीगड-पानिपतपासून सुरू झालेली ती यादी इचलकरंजी-भोर-बारामती-कऱ्हाड-मलकापूर-धावडशी-पेण-बावधन-सुपे इथपर्यंतच्या अनेक लहानमोठ्या स्थळांना सामावून घेणारी होती. दिल्ली-मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपासून भोपाळ-ग्वाल्हेर-जयपूर-जोधपूर-इंदूर-देवास-धार-सातारा-कोल्हापूर-सावंतवाडी-श्रीरंगपट्टण-म्हैसूर-तंजावर-कित्तूर-जिंजीसारख्या संस्थानांपर्यंतचाही त्या यादीत समावेश होता. या आणि अशाच इतरही ठिकाणी जिज्ञासूंनी शोध घेतल्यास कागदपत्रे हटकून सापडतील, असा राजवाड्यांना विश्वास वाटत होता.

- आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

विकसिततेची ‘वाट’!

‘‘यूएपीएचा गैरवापर हे विकसित भारताचे प्रारूप असू(च) शकत नाही’’, हे न्या. भुयान यांचे विधान महत्त्वाचेच; पण त्या अनुषंगाने न्याययंत्रणेबाबत त्यांचे भाष्य लक्षात घेण्याजोगे...

अमेरिका प्रामाणिक लोकशाहीवादी झाली आणि मग तिचा विकसिततेच्या मार्गावरचा प्रवास सुकर झाला. आज अमेरिकी अध्यक्ष चुकला असे म्हणण्याची मुभा त्या देशातील नागरिकांस आहे. अध्यक्षास असे बोल लावले म्हणून सरकारी यंत्रणा सत्ताधीशांस दूषणे देणाऱ्यांमागे हात धुऊन लागत नाही. इंग्लंड भले अमेरिकेइतकी महासत्ता नसेल. पण हा देश प्रामाणिक लोकशाहीवादी आणि विकसितही आहे. म्हणून एक बारमालक साक्षात पंतप्रधानांस आपल्या बारमधून ‘चालते व्हा’ असे म्हणू शकतो आणि त्यानंतरही सुखेनैव व्यवसाय करू शकतो. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील एक कारकून महिला पंतप्रधानांच्या गैरकृत्याबाबत साक्ष देते आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यास कारणीभूत ठरल्यानंतरही सुरळीत सेवेत राहू शकते. फ्रान्स हा तर विचारस्वातंत्र्य आणि लोकशाही या तत्त्वांचा उद्गाता. त्या देशाच्या अध्यक्षास त्याची एकेकाळची शिक्षिका आणि विद्यमान अर्धांगी असलेल्या महिलेने आपल्या पतीच्या- म्हणजे विद्यमान अध्यक्षांच्या- श्रीमुखात ठेवून दिली असावी अशी शक्यता तेथील माध्यमे निर्धास्तपणे व्यक्त करतात. अशा माध्यमांना ना सत्ताधारी देशद्रोही ठरवतात ना त्यांच्या विचारकुलातील कोणी तसा प्रयत्न करते. विकसित आणि खरी लोकशाही असलेल्या अशा देशांतील अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्या सगळ्यांतून सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. उज्जल भुयान मांडत असलेल्या मुद्द्यांनाच पुष्टी मिळते. ‘विकसित भारतात न्यायालयाची भूमिका’ या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेतील न्या. भुयान यांचे भाषण सद्यःस्थितीत न्यायपालिकेची भूमिका नक्की काय असायला हवी याचा वस्तुपाठ तर ठरतेच; पण न्यायपालिकेने व्यवस्थेपासून अलिप्त राहून वस्तुनिष्ठ विचार कसा करावा याचे मार्गदर्शन करते.

न्या. भुयान यांचे कौतुक वाटते कारण मुळात न्यायपालिकेने विकसित भारत वगैरे घोषणायात्रेत सहभागी व्हावे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे धार्ष्ट्य ते दाखवतात म्हणून. ‘‘सत्ताधाऱ्यांस ‘विकसित भारत’सारखे ध्येय समोर ठेवण्याचा अधिकार निश्चितच आहे. त्यांनी (सत्ताधाऱ्यांनी) जे केले ते निश्चितच त्यांच्या कार्यकक्षेत राहूनच केले. न्यायपालिकाही सरकार या यंत्रणेचे अंग असली तरी अशा प्रकारच्या सरकारी ध्येययात्रेत न्यायपालिकेने सहभागी होणे किती योग्य याबाबत माझ्या मनात शंका आहे. सरकारने दिलेली ही हाक ही अखेर फक्त एक घोषणा आहे’’, असे सुस्पष्ट मत नोंदवत सरकारी घोषणांच्या तालावर न्यायपालिकेने नाचायचे नसते असा धडा न्या. भुयान घालून देतात. सरकारी वा राजकीय ध्येयधोरणांशी न्यायपालिकेने स्वतःला बांधून घ्यावयाचे नसते. मग भले ती घोषणा ‘विकसित भारत’ अशी का असेना हा न्या. भुयान यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ. ‘‘न्यायपालिका ही न्यायपालिका असते. ती ना विरोधी पक्षाची भूमिका बजावते ना ती सरकारची आनंददूत (चीअर लीडर) असते’’, हे त्यांचे मत खरोखरच प्रशंसनीय म्हणावे असे. ते फक्त व्यक्त करून न्या. भुयान थांबत नाहीत. एक पाऊल पुढे जात सरकारच्या २०४७ च्या विकसित ध्येयाशी बांधून घेण्यापेक्षा न्यायपालिकेने स्वतःसमोर इ.स. २०५० हे लक्ष्य ठेवावे, असे न्या. भुयान सुचवतात. इ.स. २०५० हे वर्ष का? तर त्या वर्षी देशाची घटना आणि सर्वोच्च न्यायालय आपल्या स्थापनेची शताब्दी पूर्ण करतील. ‘‘न्यायपालिकेसाठी हे औचित्य फार महत्त्वाचे आहे. आपण विकसित असू वा विकसनशील. न्यायपालिकेचे अस्तित्व असणारच आहे. शताब्दीच्या मुहूर्तावर घटनेच्या प्रकाशातील वाटचालीचे मूल्यमापन प्रसंगोचित ठरेल’’, असे मत त्यांनी २०४७ पेक्षा २०५० सालचे महत्त्व अधोरेखित करताना नोंदवले. त्याच्याशी असहमत होणे अवघड.

त्यानंतर न्या. भुयान सर्वोच्च न्यायालयाची नक्की जबाबदारी काय याबाबत देखील भाष्य करतात. तेही विचारार्ह. ‘‘सर्वोच्च न्यायालय ही केवळ न्याय करणारी व्यवस्था इतकेच नाही. सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या सांविधानिक संवेदनांचे अंतिम राखणदार असते. न्यायाधीशांच्या हाती ना तिजोरी असते ना तलवार. त्यांना सामर्थ्य मिळत असते ते संविधान आणि त्या संविधानाचे रक्षणकर्ते असा नागरिकांच्या मनातील विश्वास यांतून. नागरिकांच्या मनातील हा विश्वास ही न्यायपालिकेची खरी संपत्ती,’’ हे न्या. भुयान यांचे मत वंदनीय आणि म्हणून अनुकरणीय. ते व्यक्त केल्यावर न्या. भुयान आपल्या प्रतिपादनातील ही सात्त्विकता सोडून सत्यकथनाकडे वळतात. तसे करताना काही न्यायाधीशांचे ‘राजापेक्षा अधिक राजनिष्ठ’ असे वर्तन त्यांना खुपते आणि ते तसे बोलून दाखवण्यास कमी करत नाहीत. काही न्यायाधीशांना ‘अशा’ (म्हणजे राजापेक्षा राजनिष्ठ) वर्तनाची व्याधी जडली असावी अशी शंका ते व्यक्त करतात तेव्हा त्यास विचारी नागरिकांचेही अनुमोदन मिळावे. अत्यंत योग्य प्रकरणांतही मग असे व्याधिग्रस्त न्यायाधीश आरोपीस जामीन नाकारतात. अनेकांस त्यामुळे निष्कारण तुरुंगवास सहन करावा लागतो. ‘‘सार्वजनिक निदर्शने, समाजमाध्यमांतील काही लिखाणादी अभिव्यक्ती अथवा लघुप्रहसन (मीम्स) असल्या क्षुल्लक कारणांसाठीही अलीकडे गुन्हे दाखल करून घेतले जातात. ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येतात आणि तिथे मग विशेष चौकशी पथकाची वगैरे स्थापना करून चौकशीचा घाट घातला जातो. यात वेळेचा खूपच अपव्यय होतो’’, हे न्या. भुयान यांचे मत रखरखीत वाळवंटात एखाद्या हिरव्या तुकड्यासारखे आल्हाददायक वाटावे.

... काही ‘राजापेक्षा राजनिष्ठ’ न्यायाधीशांमुळे अनेकांना अनावश्यक तुरुंगवास घडला तर अनेकांस केवळ अटक झाली पण त्यानुसार आरोपपत्रही दाखल होत नाही. संविधानाचे राखणदार म्हणून असलेला विश्वास वरिष्ठ न्यायालयांनी टिकवला पाहिजे, ही त्यांची मते स्वागतार्ह...

याच अनुषंगाने न्या. भुयान अलीकडे सरसकट दहशतवाद्यांसाठीच्या ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’खाली (अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट- यूएपीए) होणाऱ्या कारवायांवरही भाष्य करतात तेव्हा ते अधिक आदरणीय वाटू लागतात. या भाषणात त्यांनी या संदर्भातील आकडेवारीच सादर केली. केंद्र सरकारच्या हाती असलेल्या या अधिकाराची निष्फळताच त्यातून समोर येते. ‘‘या यूएपीए कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्यांपैकी ९५ टक्के गुन्हे सिद्धच होत नाहीत. या गुन्ह्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण पाच टक्के वा त्यापेक्षाही कमी आहे’’, असे नोंदवून न्या. भुयान म्हणतात : यातील अनेकांचे तुरुंगवास अनावश्यक (प्रीमॅच्युअर) होते. अनेकांस केवळ अटक झाली पण त्यानुसार आरोपपत्रही दाखल होत नाही. असे असताना आरोपींस तुरुंगात तरी का ठेवायचे, हा त्यांचा प्रश्न. कोणाही किमान विवेक शाबूत असणाऱ्यास न्यायाधीश मांडत असलेला मुद्दा पूर्णांशाने पटेल. न्या. भुयान हे कौतुकास पात्र ठरतात ते केवळ हा मुद्दा प्रामाणिकपणे मांडतात म्हणून नाही. तर ते या सरकारी मानसिकतेचा संबंध थेट भारताच्या विकसिततेशी जोडतात. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.

कारण ज्या समाजात मतभिन्नता, मतांतरे यास वाव नसतो त्या समाजाची प्रगती खुंटते. असहिष्णूही आहे आणि तरीही प्रगती साध्य केलेले देश म्हणजे एकेकाळचा सोव्हिएत युनियन, एकेकाळचा जर्मनी आणि अलीकडचा चीन. यातील सोव्हिएत युनियन आणि चीन महासत्तापदाजवळ पोहोचलेही. त्यातील सोव्हिएत युनियनचे काय झाले हे दिसते आहे आणि चीनचे काय होणार आहे याची काळजी आहे. अन्य जे जे विकसितपदास पोहोचले ते लोकशाही समृद्ध असल्यामुळेच. म्हणून ‘‘यूएपीए कायद्याचा गैरवापर हे विकसित भारताचे प्रारूप असू(च) शकत नाही’’, हे न्या. भुयान यांचे विधान कमालीचे सुखकारक ठरते. ‘‘सर्वांस समान संधी देणाऱ्या, जातविरहित समाजनिर्मिती’’ची गरज न्या. भुयान आपल्या भाषणात व्यक्त करतात, ही बाबही महत्त्वाची. त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे केवळ काही मूठभरांनी विचार करण्यापुरतेच राहता नयेत. स्वतःच स्वतःला विकसित मानणे आणि खरोखर विकसित असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. हा फरक कळला नाही तर विकसिततेच्या वाटेवरच स्वप्नांची ‘वाट’ लागण्याचा धोका संभवतो.

पारलिंगी हक्क संरक्षण विधेयक प्रतिगामी!

लेख

प्रशांत भवरे
वकील, कायदा क्षेत्रातील संशोधक
bhawareprashant@gmail. com

पारलिंगी व्यक्तीच्या व्याख्येतून, लिंगबदल शस्त्रक्रियेसाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेतून ‘व्यक्तिस्वातंत्र्या’वर घाला घालणारे आणि विशिष्ट गुन्ह्यांची सांगड तृतीयपंथीयांशी घालून आधीचेच पूर्वग्रह जोपासणारे नवे ‘दुरुस्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने आणले आहे, त्याविषयी...

‘तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२६’ नुकतेच लोकसभेत मांडण्यात आले. त्याआधी ‘तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम २०१९’ लागू होता, पण त्यात आमूलाग्र बदल करू पाहणारे दुरुस्ती विधेयक १२ मार्च रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणमंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी मांडले. दुरुस्ती विधेयकामुळे कोणते महत्त्वाचे बदल होणार आहेत, हे पाहण्याआधी ट्रान्सजेंडर (पारलिंगी किंवा तृतीयपंथीय) व्यक्तींसाठी निराळा कायदा का हवा, याबद्दल. हा समाजातील उपेक्षित वर्ग असून त्याचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अधोरेखित केलेले आहे. निरंतर सामूहिक संघर्षातून ट्रान्सजेंडर समुदायाने आपले हक्क-अधिकार मिळवले आहेत. मागील दशकात प्रामुख्याने कायदेशीर सुधारणा आणि संरक्षण मिळवून घेण्यात समुदायाला यश आले. इतर सर्व व्यक्तींप्रमाणे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनासुद्धा प्रतिष्ठेने जगण्याचे स्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समानता, कायद्याचे समान संरक्षण, लैंगिक समानता, अभिव्यक्ती आणि गोपनीयतेचे स्वातंत्र्य असल्याची पुनरावृत्ती २०१९च्या कायद्यात करण्यात आली. परंतु लोकसभेतील नवे दुरुस्ती विधेयक हे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला आणणारे ठरेल की काय अशी शंका येते.

प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकाने २०१९च्या मूळ अधिनियमात सुचवलेले बदल मुख्य तीन घटकांशी संबंधित आहेत. पहिला घटक हा ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या व्याख्येशी निगडित आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या मूळ कायद्यामध्ये व्यापक असून ती स्व-ओळख (सेल्फ-पर्सीव्ह्ड जेंडर आयडेन्टिटी) सिद्धांताला अनुसरून आहे. म्हणजेच, व्यक्ती जन्माधारित दिलेल्या लिंगभाव ओळखीशी (असाइन्ड जेंडर आयडेन्टिटी) संलग्न नसल्यामुळे वेगळ्या लिंगभाव ओळखीशी जुळते आणि स्वतःची ओळख ट्रान्सजेंडर समजते अशा सर्व व्यक्तींचा समावेश या व्याख्येत होतो. परंतु दुरुस्ती विधेयक स्व-ओळखीचा सिद्धांत पूर्णपणे वगळून ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची व्याख्या संकुचित करते. दुरुस्ती विधेयकामध्ये विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक समाजवर्गांसह अन्य घटक आहेत, पण हे विधेयक, ‘किन्नर, हिजरा, अरवणी, जोगता व युनक, यासह द्विलिंगी व्यक्ती (इंटरसेक्स पर्सन्स) व जन्मजात लैंगिक गुणांमध्ये विसंगती असणाऱ्या व्यक्ती आणि ज्यांचा लिंगभाव बदल जबरदस्तीने करण्यात आला आहे अशा व्यक्ती’- यांचाच समावेश ट्रान्सजेंडर व्याख्येमध्ये करते. यामुळे स्व-समज व स्व-ओळख असणाऱ्या असंख्य ट्रान्सजेंडर महिला, ट्रान्सजेंडर पुरुष, नॉन बायनरी व्यक्ती, क्वीअर व्यक्ती हे या व्याख्येतून वगळले जातील. त्यामुळे ते कायदेशीर संरक्षण आणि अधिकारापासून वंचित होतील.

दुरुस्ती विधेयकातील दुसरा घटक वैद्यकीय आणि शासकीय यंत्रणांचे अनावश्यक नियंत्रण आणि हस्तक्षेपाबाबत आहे. मूळ कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सदर व्यक्तीच्या अर्जासह स्व-घोषणापत्र हे पुरेसे होते. परंतु दुरुस्ती अधिनियमानुसार ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळवण्यासाठी, आधी जिल्हाधिकाऱ्याला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र आवश्यक असेल. यासह, संबंधित वैद्यकीय संस्थेला लिंगभाव बदल शस्त्रक्रिया करणाऱ्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची माहिती विहित नमुन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर संबंधित ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना शस्त्रक्रियेनंतर लिंगभाव बदल प्रमाणपत्राकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक असेल.

दुरुस्ती विधेयकातील तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे सुचवलेले काही नवीन अपराध आणि त्यासाठीची आकारलेली कठोर दंड (शिक्षा) प्रणाली. सुचवलेले हे वाढीव गुन्हे हे अपहरणासह गंभीर शारीरिक इजा करणे (अंगच्छेदन, पौरुषत्वहरण, नपुंसकीकरण व इतर इजा) ज्यामुळे ट्रान्सजेंडर ओळख जबरदस्तीने लादली जाणे; प्रौढ व्यक्तींना किंवा बालकांना जबरदस्तीने ट्रान्सजेंडर ओळख देऊन भीक मागण्यास भाग पाडणे, त्यांच्यावर दास-अवस्था लादणे किंवा त्यांना वेठबिगारी करण्यास भाग पाडणे यास गुन्हेगारी कृत्य मानते. या विविध गुन्ह्यांसाठी निरनिराळ्या कठोर शिक्षा या विधेयकात सुचवल्या आहेत. या शिक्षा किमान दहा वर्षे ते आजन्म सश्रम कारावास, तसेच दोन लाख ते पाच लाख रुपये आर्थिक दंड अशा स्वरूपाच्या आहेत.

मूळ कायदा, म्हणजेच ट्रान्सजेंडर अधिनियम, हा ट्रान्सजेंडर समाजाच्या दीर्घकालीन न्यायिक आणि सामाजिक संघर्षाचे फलित आहे. हा कायदा ट्रान्सजेंडर समाजाला कायदेशीर संरक्षण आणि प्रतिष्ठेने जगण्याची हमी देतो. अशा समावेशक कायद्यामध्ये इतक्या आमूलाग्र रूपाचे बदल करू पाहण्यामागे काय उद्देश आणि प्रयोजन असावे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याकरिता दुरुस्ती विधेयकाची समीक्षा करणे गरजेचे ठरते.

हे दुरुस्ती विधेयक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची कायदेशीर व्याख्या संकुचित करून त्याला जैविक आणि वैद्यकीय गुणांच्या अनिवार्यतेमध्ये साचेबंद करते. ही व्याख्या व्यक्तीची स्व-समज व स्वओळखीचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेते. ट्रान्सजेंडर ओळखीला मानवी अभिव्यक्तीचे सामान्य प्रकटीकरण नाकारून ही व्याख्या तिला जैविक आणि वैद्यकीय गुणांच्या अनिवार्यतेची चौकट घालून विकृत दर्शवते. यामुळे ट्रान्सजेंडर समाजातील एक मोठा वर्ग जो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत आपली ओळख जन्माने नेमून दिलेल्या लिंगभाव चौकटीबाहेर पाहतो, त्या सर्व व्यक्ती यामुळे ट्रान्सजेंडर व्याख्येतून वगळल्या जातील. अशा असंख्य ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या शारीरिक स्वायत्तता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आळा घातला जाईल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा शासकीय आणि वैद्यकीय संस्थेचे सनियंत्रण (monitoring) आणि सनिरीक्षणाचा (surveillance) आहे. खरी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कोण हे ठरविण्याचा सर्व अधिकार त्या व्यक्तीकडे उरलेले नसून ते प्रशासकीय आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविले आहेत. या अंतर्गत ट्रान्सजेंडर प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकाऱ्याला वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा आणि आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञाचा अभिप्राय घेणे अनिवार्य करून प्रक्रियेला संपूर्ण वैद्यकीय रूप देण्यात आले आहे. दुरुस्ती विधेयकातील व्याख्येत समावेश असलेल्या सामाजिक व सांस्कृतिक ट्रान्सजेंडर ओळखी जसे किन्नर, हिजरा, अरवणी, जोगता, द्विलिंगी यांनादेखील विहित प्रक्रियेतून जाऊन आपली ओळख सिद्ध करावी लागेल. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती या प्रक्रियेमुळे आपल्या लिंगभावाची स्वायत्तता पूर्णपणे गमावून बसतील. सोबतच लिंगभाव बदल शस्त्रक्रियेवरील शासकीय नियंत्रण व त्यानंतर लिंगबदल प्रमाणपत्राच्या सक्तीची प्रक्रियादेखील कटकटीची आहे. ही प्रक्रिया व्यक्तींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे (राइट टू प्रायव्हसी) उल्लंघन आहे.

दुरुस्ती विधेयकामध्ये जे विशिष्ट गुन्हे समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे- उदाहरणार्थ अपहरण, पौरुषत्वहरण, नपुंसकीकरण आणि जबरदस्तीने ट्रान्सजेंडर ओळख लादणे इत्यादी- हे ट्रान्सजेंडर समुदायाबाबत समाजात असलेल्या पूर्वग्रहांतून आलेले आहेत हे स्पष्ट आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायाविरुद्ध समाजात पसरलेले गैरसमज, पूर्वग्रह व त्यांच्या विरुद्ध लावण्यात येणारे खोटे आरोप यामुळेच तर बहुतेकदा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची समाजात पिळवणूक होते व त्यांना भेदभाव सहन करावा लागतो. अशा प्रकारचे गुन्हे जे पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून मांडण्यात आले आहेत, तेच कायदा म्हणून मंजूर होऊन अमलात आल्यास ट्रान्सजेंडर समुदायाविरुद्ध समाजात दुर्भावना आणि गैरसमज आणखी वाढतील. आपल्या ट्रान्सजेंडर ओळखीमुळे असंख्य व्यक्तींना समाजातून बहिष्कार सोसावा लागतो, अशा परिस्थितीत पारंपरिक ट्रान्सजेंडर समुदाय त्या व्यक्तींना आपलेसे करतो. असे संगोपनाचे आणि सहकार्याचे प्रसंगदेखील प्रस्तावित विधेयकामुळे गुन्हेगारीच्या परिभाषेत येण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना यातून अपराधीच ठरवण्यात येणार की काय अशी शंका यामधून उपस्थित होते.

एकंदर या विधेयकाचा उद्देश ट्रान्सजेंडरच्या अभिव्यक्तीवर मर्यादा आणून त्यांना प्रशासकीय नियंत्रणाद्वारे मुख्य प्रवाहापासून विभक्त ठेवण्याचा आहे, असे स्पष्ट होते. प्रस्थापित समाज व्यवस्था जातीअंतर्गत विषमलिंगी (स्त्री-पुरुष) विवाह आणि प्रजननाला प्रमाण मानून तिला कुटुंब संस्थेचा गाभा समजते. या प्रस्थापित व्यवस्थेला, जी असमानतापूरक जातीय-वर्गीय आणि लैंगिक संरचनेवर आधारित आहे, तिला चौकटीबाहेरील लैंगिक आणि इतर अभिव्यक्ती धोकादायक वाटतात. यामुळेच, अशा चौकटीबाहेरील सर्व अभिव्यक्तींना बहिष्कृत करून त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रस्थापित समाजव्यवस्था करत असते. तर मुळात ट्रान्सजेंडर ओळख आणि अभिव्यक्ती रूढीवादी ‘स्त्री-पुरुष’ या लिंगभेदाच्या चौकटीला आणि जातीय-वर्गीय कुटुंब व्यवस्थेला आव्हान देते. ती प्रस्थापित समाजव्यवस्थेला असंतुलित करण्याची क्षमता बाळगते. या पार्श्वभूमीवर विधेयकाची समीक्षा केली असता लक्षात येते की प्रस्थापित रूढीवादी समाजव्यवस्थेला आहे तसे टिकवून ठेवण्यासाठी उचललेले हे कायदेशीर पाऊल आहे. अशा प्रतिगामी स्वरूपात हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत झाल्यास ते सामाजिक अन्यायाला मोकळीक देणारे ठरेल.

अन्वयार्थ

‘स्वच्छ कारभारा’चा फुगा फुटतो आहे...

इतर सर्व राजकीय पक्षांपेक्षा आम आदमी पार्टीचा कारभार वेगळा असेल व सत्तेत आल्यास भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराला थारा देणार नाही, अशी ग्वाही पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापनेच्या वेळी दिली होती. पक्षाला आतापर्यंत दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांमध्ये सत्ता मिळाली. यापैकी दिल्लीत स्वतः केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अशा पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वावरील गैरव्यवहाराचे आरोप केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) सिद्धच करता न आल्याने सुटका झाली असली तरी दिल्लीची सत्ता ‘आप’ला गमवावी लागली. तर पंजाबमधील ‘आप’च्या मंत्र्याच्या प्रतापामुळे पक्षाला बचावात्मक पवित्रा घेऊन मंत्र्याची हकालपट्टी करावी लागली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून घरी जावे लागलेले पंजाबमधील दुसरे मंत्री. यातून ‘आप’चा स्वच्छ कारभाराचा फुगा फुटला आहे. गोदाम महामंडळाच्या अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी पंजाब सरकारमधील परिवहनमंत्री लालजितसिंग भुल्लर यांना राजीनामा देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री भगवान मान यांनी दिला. या मंत्र्याने वडिलांच्या कंपनीला सरकारी निविदा मिळावी म्हणून अमृतसर जिल्हा गोदाम मंडळाच्या अधिकाऱ्यावर दबाव आणला होता. त्यास बळी पडला नाही म्हणून या अधिकाऱ्यास या मंत्र्याच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आले आणि मारहाण झाली, तेथेच ‘सरकारी निविदेसाठी १० लाखांची लाच स्वीकारल्या’ची कबुली देण्यास भाग पाडून त्याचे चित्रीकरण करण्यात आले, असे या अधिकाऱ्याच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘मंत्री लालजी भुल्लर यांच्या भीतीमुळेच मी विष प्राशन केले आहे’ अशी संबंधित अधिकाऱ्याची आत्महत्या करण्यापूर्वी तयार केलेली चित्रफीत समाजमाध्यमातून प्रसारित झाली. यावरून विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली. स्वच्छ व पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचाराला थारा नाही, असा दावा करणाऱ्या ‘आप’वर चोहोबाजूने टीका होऊ लागताच मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्र्याला राजीनामा देण्याचा आदेश दिला.

मात्र केवळ राजीनामा घेऊन ‘आप’ सरकार पळ काढू शकलेले नाही. मंत्र्याच्या राजीनाम्यानंतर भ्रष्टाचाराची टीका वाढल्यानेच हा माजी मंत्री व त्याच्या वडिलांवर अधिकाऱ्याला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी संबंधित माजी मंत्र्यास अटक करून कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे. त्याहीपेक्षा केजरीवाल, मान यांनी स्वच्छ कारभाराबाबत दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले, याचे उत्तर ‘आप’ला द्यावे लागेल. वडिलांना सरकारी निविदा मिळाली पाहिजे म्हणून पंजाबच्या आता राजीनामा द्यावा लागलेल्या मंत्र्याने दबाव आणला होता. अधिकाऱ्याने आत्महत्या करताना तयार केलेल्या चित्रफितीमुळे सारा प्रकार उघड झाला. अन्यथा निविदांमधील मंत्र्यांच्या दबावाची कितीतरी प्रकरणे दडपली जात असतील. पंजाबमधील आप सरकारमधील आरोग्यमंत्र्याची ठेकेदाराकडून पैसे उकळल्यावरून मागे हकालपट्टी झाली होती. आता सरकारी निविदेसाठी दबाव आणणाऱ्या मंत्र्याला घरी जावे लागले. पुढील वर्षी पंजाब विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यावर आरोपांची राळ भाजपने उडवल्यामुळे आम आदमी पार्टीला दिल्लीची सत्ता गमवावी लागली. या पार्श्वभूमीवर पंजाबची सत्ता कायम राखणे हे ‘आप’साठी जरुरीचे आहे. दिल्लीपाठोपाठ पंजाब राज्यही गमावल्यास ‘आप’साठी अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

कोणत्याही राज्यातले, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, मंत्र्यांना सरकारी निविदा, कामांमध्ये अधिक रस असतो. सरकारी कामे आपल्या घरच्यांना किंवा मर्जीतील ठेकेदारांना मिळाली पाहिजेत, असा मंत्र्यांचा प्रयत्न असतो. सुमारे १०० कोटींच्या निधीच्या अफरातफरप्रकरणी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमधील आदिवासी विकासमंत्री नागेंद्र यांना राजीनामा द्यावा लागला. बिहारमध्ये शिक्षणमंत्र्यांना नियुक्तीच्या तिसऱ्याच दिवशी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राजीनामा द्यावा लागला होता. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागला आहे. भाजप, काँग्रेस वा प्रादेशिक पक्षही यात मागे नाहीत. ‘झाडू’ निशाणी असलेल्या ‘अप’ने राजकारणात साफसफाई करण्याचा निर्धार केला होता, पण पंजाबमध्ये खंडणीखोरीचा आरोप झाल्यावर राजीनामा द्यावा लागलेले फौजासिंग सरारी यांच्यानंतर भुल्लरही गेल्यामुळे या पक्षाच्या स्वच्छ प्रतिमेचा फुगा फुटू लागला आहे.

खरात प्रकरणामुळे जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित?

विश्लेषण

तुषार धारकर
tushar.dharkar@expressindia.com

नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याची उपयुक्तता आणि मर्यादा या दोन्ही प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणले आहे...

जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा काय आहे?

महाराष्ट्रात जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा, २०१३ (महाराष्ट्र मानवी बळी व अन्य अमानवी, अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा) हा अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि अघोरी प्रथांच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषण, फसवणूक आणि अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आला आहे. याचा उद्देश केवळ गुन्हेगारी कृत्यांवर कारवाई करणे नसून, समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे हा आहे. या कायद्यांतर्गत मानवी बळी देणे किंवा देण्यासाठी प्रवृत्त करणे, भूतबाधा काढण्याच्या नावाखाली मारहाण किंवा छळ करणे, ‘चमत्कार’ किंवा अलौकिक शक्तींचा दावा करून फसवणूक करणे, महिलांना चेटकीण ठरवून छळणे, तसेच अघोरी व अमानवी विधी करणे यांसारखी कृत्ये स्पष्टपणे गुन्हा ठरवली आहेत. श्रद्धा किंवा धार्मिक आचरण यावर बंदी नसून, त्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणूक, हिंसा आणि अमानवी वागणुकीवर हा कायदा लक्ष केंद्रित करतो. या कायद्यानुसार नोंदवले जाणारे गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचे आहेत. दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीस किमान सहा महिने ते कमाल सात वर्षांपर्यंत कारावास, तसेच दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

ज्योतिष सांगणे हा गुन्हा आहे?

महाराष्ट्रातील जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यात ‘‘ज्योतिष’’ या प्रकारावर थेट बंदी घालण्यात आली नाही. पत्रिका पाहणे, भविष्य सांगणे वा ग्रह-नक्षत्रांवर आधारित सल्ला देणे हे गुन्हे मानले जात नाही, कारण ते वैयक्तिक श्रद्धा आणि विश्वासाच्या कक्षेत येते. मात्र, ज्योतिषाच्या नावाखाली फसवणूक, भीती निर्माण करून पैसे उकळणे किंवा अलौकिक शक्तींचा दावा करणे, अशा प्रकारची कृत्ये केल्यास हा कायदा लागू होतो. उदाहरणार्थ, ‘‘मी तुमचे सर्व ग्रहदोष दूर करतो’’, ‘‘हा विधी केला नाही तर अनर्थ होईल’’ असे सांगून मोठी रक्कम उकळणे, किंवा काही अघोरी उपाय करण्यास भाग पाडणे, हे कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा ठरू शकते. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीवर जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यासोबतच भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक किंवा धमकीसंबंधी कलमेही लागू होऊ शकतात.

खरातवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत?

नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात अशोक खरातवर लैंगिक अत्याचारासह महाराष्ट्र नरबळी आणि जादूटोणा प्रतिबंधक, अघोरी प्रथा कलमांर्गत तीन गुन्हे दाखल आहेत. पहिल्या गुन्ह्यात अशोक खरातविरोधात लैंगिक अत्याचार, जादूटोणा आणि जीवे मारण्याची धमकी अशा कलमान्वये गुन्हे दाखल आहेत. दुसऱ्या गुन्ह्यात लैंगिक अत्याचार, महाराष्ट्र नरबळी तसेच जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गर्भवतीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिसऱ्या गुन्ह्यात लग्नाचे आमिष दाखवत घटस्फोटितेवर तांत्रिक विधीच्या नावाखाली लैंगिक शोषण करण्यात आले असल्याची नोंद आहे. महिलेला भीती घालत मुलांचे बरेवाईट होईल असे सांगून वारंवार मी अवतारी पुरुष आहे, मला त्रिकालज्ञान आहे असे सांगून लैंगिक अत्याचार व गर्भपात केल्याचा आरोप आहे.

कर्नाटकचा कायदा प्रगत कसा?

महाराष्ट्रातील जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा अधिक कठोर करण्याची मागणी अलीकडे पुढे येत असताना, कर्नाटकच्या समांतर कायद्याशी तुलना केली असता काही ठळक उणिवा दिसून येतात. कर्नाटकच्या कायद्यात बंदी घालण्यात आलेल्या प्रथांची स्पष्ट आणि नावानिशी यादी दिली आहे, त्यामुळे कोणते कृत्य गुन्हा आहे हे थेट समजते. याउलट महाराष्ट्राच्या कायद्यात ‘अमानवी, अघोरी प्रथा’ अशा व्यापक संज्ञांचा वापर असून, प्रत्येक प्रकरणात त्याचा अर्थ लावावा लागतो. याशिवाय, कर्नाटकच्या कायद्यात अशा प्रथांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘विशेष दक्षता यंत्रणा’ किंवा अधिकाऱ्यांची तरतूद आहे; तर महाराष्ट्रात अंमलबजावणी मुख्यतः पोलिसांवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे तक्रार नोंदवणे, तपास करणे आणि वेळेत कारवाई करणे या प्रक्रियांत त्रुटी राहण्याची शक्यता वाढते. महाराष्ट्रात मात्र हानी किंवा अत्याचार सिद्ध झाल्यावरच कारवाई होते. कर्नाटक कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पीडित व्यक्तीची ‘संमती’ ही बचाव म्हणून ग्राह्य धरली जात नाही. महाराष्ट्राच्या कायद्यात ही बाब तितक्या स्पष्टतेने मांडलेली नसल्याने, काही प्रकरणांत आरोपींकडून ‘संमतीने विधी केले’ असा युक्तिवाद केला जातो. दोन्ही राज्यांमध्ये शिक्षेच्या तरतुदी जवळपास सारख्याच असल्या, तरी कर्नाटकचा कायदा अधिक स्पष्ट आणि अंमलबजावणीस सुलभ मानला जातो. महाराष्ट्रात त्यामुळे आता कायद्याला अधिक नेमके, स्पष्ट आणि प्रभावी बनवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

करिअर वृत्तांत

ज्ञानाविना स्वातंत्र्य नेहमीच धोक्यात असते आणि स्वातंत्र्याविना ज्ञान नेहमीच व्यर्थ ठरते.
- **जॉन एफ. केनेडी,** अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष

स्पर्धा परीक्षेच्या प्रांगणात
यूपीएससी
डॉ. सुशील बारी

पूर्व परीक्षेसाठी आधुनिक भारत

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण आधुनिक भारत या विषयातील २०२६ च्या यूपीएससी पूर्व परीक्षेसाठी अपेक्षित असलेले घटक बघणार आहोत. यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत दरवर्षी आधुनिक भारतावर आधारित सुमारे ८ ते १२ प्रश्न विचारले जातात. प्रश्नांचे स्वरूप बघता परीक्षेचा कल आता केवळ तथ्ये लक्षात ठेवण्याकडून संकल्पनात्मक आणि विधानांवर आधारित प्रश्नांकडे सरकला आहे.

आधुनिक भारतावर प्रश्न विचारताना राष्ट्रीय चळवळीचे टप्पे, ब्रिटीशकालीन कायदे आणि नेत्यांचा समावेश होतो. कालक्रम, जोड्या लावणे आणि सामाजिक-आर्थिक पैलूंशी असलेला संबंध यावर अधिक भर दिला जातो. ज्यासाठी केवळ पाठांतर न करता विषयाची एकात्मिक समज असणे आवश्यक आहे.

२०१३ ते २०२५ मध्ये यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत आधुनिक भारत या विषयातील वारंवार विचारलेले घटक आपण जाणून घेणार आहोत. २०२६ च्या पूर्व परीक्षेसाठी आपण या घटकांचा आधुनिक भारतातील सर्वाधिक अपेक्षित घटक म्हणून अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. हे घटक खालीलप्रमाणे आहेत -

१८५७ चा उठाव

- कारणे : राजकीय, आर्थिक, लष्करी, धार्मिक इ.
- नेते आणि केंद्रे (दिल्ली, कानपूर, झाशी, लखनौ)
- उठावाचे स्वरूप (वाद-विवादावर आधारित)
- अपयशाची कारणे

या घटकावर प्रश्न विचारण्याची शक्यता खूप अधिक आहे. यात प्रामुख्याने तथ्यात्मक व विश्लेषणात्मक प्रश्न वारंवार विचारलेले आपण बघू शकतो.

गव्हर्नर-जनरल आणि व्हाइसरॉय

- लॉर्ड डलहौसी (खालसा धोरण)
- लॉर्ड कर्झन (बंगालची फाळणी)
- लॉर्ड रिपन (स्थानिक स्वराज्य संस्था)
- लॉर्ड विल्यम बेंटिक (सुधारणा)

आयोगाद्वारे महत्त्वाचे गव्हर्नर-जनरल आणि व्हाइसरॉय व त्यांचे कार्य यावर प्रश्न विचारले जातात. अभ्यासताना ज्यांच्या कार्याचा मोठ्या प्रमाणात इतिहासात प्रभाव दिसून येतो त्यांच्यावर प्रश्न विचारण्याची शक्यता अधिक असते.

आधुनिक भारत विषयातील पूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाचे १५ घटक

- खालसा धोरण
- तैनाती फौज
- व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट
- इल्बर्ट बिल
- पुणे करार (१९३२)
- जातीय निवाडा
- होमरूल चळवळ
- ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन
- लाहोर अधिवेशन (१९२९ - पूर्ण स्वराज्य)
- गांधी-आयर्विन करार
- सायमन कमिशन
- रोलेट ॲक्ट
- जालियनवाला बाग
- मवाळ विरुद्ध जहाल
- स्वदेशी आणि बहिष्कार

कायदे आणि घटनात्मक विकास

- रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३
- पिट्स इंडिया ॲक्ट १७८४
- चार्टर ॲक्ट्स (१८१३, १८३३, १८५३)
- इंडियन कौन्सिल ॲक्ट (१९०९, १९१९)
- भारत सरकार कायदा १९३५ या कायद्यांमधील तरतुदी

नियमितपणे आयोगाद्वारे विचारल्या जातात. तसा हा घटक आपण पॉलिटी मध्येही अभ्यासतो.

भारतीय राष्ट्रीय चळवळ

- स्वदेशी चळवळ (१९०५)
- असहकार चळवळ (१९२०)
- सविनय कायदेभंग चळवळ (१९३०)
- छोडो भारत चळवळ (१९४२)

या चळवळींचा अभ्यास करताना त्यांची वैशिष्ट्ये, कारणे, परिणाम इ. चा अभ्यास करताना त्यांचे आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामातील महत्त्व समजून घ्या.

काँग्रेस अधिवेशने आणि नेते

- महत्त्वाची अधिवेशने (१८८५, १९०७, १९१६, १९२९)
- अध्यक्ष आणि महत्त्वाचे निर्णय
- सुरत फूट (१९०७)
- लखनौ करार (१९१६)

यावर आयोगाद्वारे थेट तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात तेव्हा रिव्हीजन वारंवार करून त्यावर प्रभूत्त्व मिळवा. यासाठी तुम्ही काँग्रेस अधिवेशनांचा तक्ता तयार करा. त्यात अधिवेशनाचे स्थळ, वर्ष, अध्यक्ष, अधिवेशनात पारित झालेले ठराव यांचा समावेश करा. प्रश्न विचारताना आयोग पुढे दिलेल्या अधिवेशनावर प्रश्न विचारण्याची शक्यता अधिक आहे. उदा. १९२४ चे बेळगाव काँग्रेस अधिवेशन हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे ३९ वे वार्षिक अधिवेशन होते. हे अधिवेशन डिसेंबर १९२४ मध्ये कर्नाटकातील बेळगाव येथे भरले होते आणि महात्मा गांधी यांनी अध्यक्षपद भूषवलेले हे काँग्रेसचे एकमेव अधिवेशन होते.

क्रांतिकारी चळवळी

- भगतसिंग आणि क्रांतिकारी संघटना
- गदर चळवळ
- क्रांतिकारी गट (बंगाल, पंजाब)

यावर प्रश्न विचारताना ते फसवे असण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे नीट वाचून समजून यावरील प्रश्न सोडवा.

सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणा चळवळी

- ब्राह्मो समाज
- आर्य समाज
- अलीगड चळवळ
- रामकृष्ण मिशन इ.

या सुधारणा चळवळींची विचारधारा समजून घ्या. त्यांचे संस्थापक व त्याच्याशी जोडलेल्या व्यक्ती अभ्यासा.

महत्त्वाची वर्तमानपत्रे आणि साहित्य

- केसरी, मराठा (लोकमान्य टिळक)
- यंग इंडिया, हरिजन (महात्मा गांधी)
- अमृत बाजार पत्रिका
- वर्तमानपत्रे, त्यांची स्थापना व संस्थापक अभ्यासा.

ब्रिटीश आर्थिक धोरणे

- संपत्तीच्या वहनाचा सिद्धांत - दादाभाई नौरोजी
- जमीन महसूल प्रणाली
- निरुद्योगीकरण
- शेतकरी चळवळी

स्वातंत्र्याच्या दिशेने

- क्रिप्स मिशन (१९४२)
- कॅबिनेट मिशन प्लॅन (१९४६)
- माउंटबॅटन प्लॅन (३ जून १९४७)
- भारतीय स्वातंत्र्य कायदा (१९४७)

यातील शिफारशी चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. त्यांना भारतीयांनी, राजकीय संघटनांनी दिलेला प्रतिसाद समजून घ्या. त्यात गोंधळ होता कामा नये.

आयोगाद्वारे गेल्या काही वर्षात विधान आधारित प्रश्न विचारण्याची वृत्ती वाढत आहे. कालानुक्रम हा इतिहासाचा आत्मा आहे तेव्हा रिव्हीजनद्वारे त्यावर प्रभूत्त्व मिळवा. मागील वर्षांच्या प्रश्नांचे विश्लेषण, ट्रेंड आणि आयोगाच्या पॅटर्नवर आधारित घटकांवर आपण काम केल्यास पूर्व परीक्षेत चांगले गुण या विषयात नक्कीच मिळवू शकतो.

sushilbari10@gmail.com

नोकरीची संधी
सुहास पाटील

बीएआरसीत ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप

भाभा अणू संशोधन केंद्र (BARC) फेलोशिपची एकूण संख्या - १०५. BARC, मुंबई या सेंटरकडे भारताच्या महत्त्वाकांक्षी अणुऊर्जा कार्यक्रमाला पाठिंबा देणाऱ्या शिस्तबद्ध संशोधनाकरिता ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप मिळविण्यासाठी स्वारस्य असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवित आहे.

● **सर्व निवड** झालेले उमेदवार होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिट्यूट (HBNI), अणूऊर्जा विभागाचे एक मानीव विद्यापीठ (Deemed University) येथे पीएच.डी. करिता नोंदणी करतील.

विज्ञान विद्याशाखेतील संशोधनाचे प्रकल्पांसाठी विषय असतील (१) फिजिकल सायन्सेस, (२) केमिकल सायन्सेस, (३) लाईफ सायन्सेस. BARC मुंबई सेंटर आपल्या प्रोग्राम्सच्या संबंधित उच्च दर्जाच्या इंटरडिसिप्लीनरी संशोधनासाठी प्रोत्साहीत करते.

पात्रता – (१) एम.एससी. (फिजिक्स) (बी.एस्सी. स्तरावर मॅथेमॅटिक्स विषय अभ्यासलेला असावा.)

(२) एम.एस्सी. (केमिस्ट्री - जनरल, ॲप्लाईड, ऑरगॅनिक, इनऑरगॅनिक फिजिकल आणि ॲनालिटिकल) (बी.एस्सी.ला फिजिक्स/१२ वीला मॅथेमॅटिक्स विषय अभ्यासलेले असावेत.)

(३) एम.एस्सी. (लाईफ सायन्सेस - ॲग्रिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्युलर बायोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, मरिन बायोलॉजी, बायोइन्फॉरमॅटिक्स, जेनेटिक्स, बॉटनी, झूऑलॉजी, प्लांट सायन्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पॅथॉलॉजी, एन्टोमोलॉजी, ॲनिमल सायन्स, फूड सायन्स, बायोमेडिकल सायन्सेस, फुड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आणि बायोसायन्सेस) (एम.एससी. पात्रता धारकांनी बी.एस्सी. स्तरावर यापैकी किमान एक विषय म्हणून अभ्यासलेला असावा - फिजिक्स/केमिस्ट्री/बायोकेमिस्ट्री/ ॲग्रिकल्चर केमिस्ट्री)

फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ॲग्रोनॉमी, ॲनिमल हजबंडरी, बायो ॲनालायटिकल सायन्सेस, पॉलिमर सायन्स, मेडिसिन/मेडिकल सायन्स, फार्मास्युटिकल सायन्स, होम सायन्सेस विषयातील एम.एससी./इंटिग्रेटेड एम.एससी. पात्रताधारक उमेदवार पात्र नाहीत.

उमेदवारांना बी.एस्सी.ला किमान सरासरी ६०% गुण आणि एम.एस्सी.ला किमान सरासरी ५५% गुण मिळालेले असावेत.

पात्रता परीक्षेच्या अंतिम वर्षाचे परीक्षेस बसलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

उमेदवार फिजिक्स/ केमिस्ट्री/ लाईफ सायन्सेस/बायोटेक्नॉलॉजी यापैकी एका विषयातील, पुढीलपैकी राष्ट्रीय स्तरावरील एका पात्रता परीक्षेला बसून उत्तीर्ण झालेला असावा.

(ए) UGC- CSIR- NET (Fellowship), (बी) JEST Score, (सी) ICMR- JRF Test, ICAR- JRF Test, (डी) DBT- JRB Biotechnology Eligibility Test, (इ) GATE Score, (एफ) JGEEBILS (या परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचा पुरावा इंटरव्ह्यूच्या वेळी सादर करावा लागेल.)

वयोमर्यादा – (१ ऑगस्ट २०२६ रोजी) २८ वर्षे (इमाव - ३१ वर्षे, अजा/अज - ३३ वर्षे, दिव्यांग - ३८ वर्षे).

निवड पद्धती – शैक्षणिक अर्हता आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षेतील कामगिरीवर आधारित (दि. १ जुलै २०२६ रोजीचा व्हॅलिड स्कोअर) उमेदवार मुलाखतीसाठी निवडले जातील. अंतिम निवड उमेदवारांच्या मुलाखतीमधील कामगिरीवर आधारित केली जाईल. ज्युनियर रिसर्च फेलोशिपसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी BARC च्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल. निवडलेल्या उमेदवारांना मेलद्वारे सूचित केले जाईल.

फेलोशिप आणि कार्यकाळ – सुरुवातीला निवडलेल्या उमेदवारांना ज्युनियर रिसर्च फेलोज (JRF) म्हणून घेतले जाईल व त्यांना २ वर्षांसाठी दरमहा रु. ३७,०००/- स्टायपेंड दिले जाईल. प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीस उमेदवारांची कामगिरी समाधानकारक असल्याचे पाहून फेलोशिप सुरू ठेवायची की नाही हे ठरविले जाईल.

तिसऱ्या वर्षापासून उमेदवारांना सिनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) म्हणून पुढील ३ वर्षांसाठी दरमहा रु. ४२,०००/- स्टायपेंड दिले जाईल. फेलोशिपचा कार्यकाळ ५ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही.

जे उमेदवार BARC च्या हॉस्टेलमध्ये राहणार नाहीत त्यांना स्टायपेंडच्या २७% रक्कम घरभाडे भत्ता म्हणून दिले जातील.

याशिवाय उमेदवारांना दरवर्षी रु. ६०,०००/- पुस्तके आणि आकस्मिक खर्चासाठी दिले जातील.

अर्जाचे शुल्क – रु. ५००/-

विस्तृत माहिती www.barc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. शंकासमाधानासाठी jrf@barc.gov.in या ई-मेलवर संपर्क साधा.

ऑनलाइन अर्ज https://www.barc.ocesexam.in/jrf या संकेतस्थळावर दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत करावेत.

रचना जगत
किरण सबनीस

डिझाइन शिक्षणाची सुरुवात शाळेपासूनच...

भारतामध्ये अलीकडेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सहाय्याने शालेय शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यास सुरुवात झाली आहे. या धोरणाचा मुख्य भर सृजनशील अभिकल्प (क्रिएटिव्ह डिझाइन) आणि नवकल्पनात्मक विचारसरणीवर (इनोव्हेटिव थिंकिंग) आहे. याचा आपल्या विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि समाजावर काय आणि कसा परिणाम होईल, हे या लेखात पाहणार आहोत.

पूर्वीच्या काही दशकात शिक्षण घेणे म्हणजे प्रामुख्याने केवळ माहिती पाठ, स्मरणात ठवणे यावर अधिक भर दिल जात होता, परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे हे चित्र बदलले जाणार आहे. आता विचार करण्याची क्षमता, समस्या सोडवण्याचे कौशल्य आणि सृजनशीलता यांना महत्त्व दिले जात आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये डिझाइनचे महत्त्व

नवीन शिक्षण धोरणामध्ये सृजनशील डिझाइन शिक्षणाला प्राथमिक (इयत्ता ६ ते ८) आणि माध्यमिक (इयत्ता ९ ते १२) या दोन्ही स्तरांवर महत्त्व दिले जाते. या दोन्ही स्तरांवर डिझाइन शिक्षणाचे स्वरूप कसे वेगळे असते हे पाहूया.

प्राथमिक स्तर (इयत्ता ६ ते ८)

या स्तरावर डिझाइन शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना डिझाइनच्या मूलभूत संकल्पनांची ओळख करून देणे आणि त्यांच्यामध्ये सर्जनशीलता, समस्या सोडवणे आणि सहकार्य यासारखे गुण विकसित करणे हा आहे.

- **अभिकल्पनात्मक विचार :** विद्यार्थ्यांना वापरकर्त्यांच्या समस्यांवर वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यासाठी आणि नवीन कल्पनांचा विचार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी शाळेतील कचरा कमी करण्यासाठी किंवा खेळाचे मैदान अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी डिझाइन विचार करू शकतात.
- **मॉडेल बनवणे :** विद्यार्थी त्यांच्या कल्पनांची रेखाचित्रे,

'एआय' निर्मित छायाचित्र

प्रोटोटाइप आणि इतर मॉडेलिंग तंत्रांचा वापर करून मूर्त स्वरूपात आणतात. यामुळे त्यांना त्यांच्या कल्पनांचा चाचणी घेता येतो आणि त्यामध्ये सुधारणा करता येते. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी एखाद्या नवीन खेळाच्या साधनाचे मॉडेल बनवू शकतात.

- **वापरकर्ता-केंद्रित डिझाइन:** विद्यार्थ्यांना इतरांच्या गरजा समजून घेण्यासाठी शिकवले जाते. यानंतर ते त्या गरजा पूर्ण करणारे डिझाइन तयार करतात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी वृद्धांसाठी वापरण्यास सोपा असा रिमोट कंट्रोल बनवू शकतात.
- **संवाद आणि सहकार्य :** डिझाइन प्रकल्प अनेकदा गटात केले जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना इतरांसोबत प्रभावीपणे संवाद साधणे आणि सहकार्य करणे शिकण्यास मदत होते. त्यांना त्यांच्या कल्पना इतरांसोबत सांगाव्या लागतात आणि इतरांच्या कल्पनांचा देखील विचार आणि आदर करावा लागतो.

माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ ते १२)

माध्यमिक स्तरावर डिझाइन शिक्षण अधिक आव्हानात्मक बनते. विद्यार्थ्यांना खालील गोष्टींचा अनुभव मिळतो -

- **अधिक सखोल डिझाइन प्रकल्प :** विद्यार्थी वास्तविक जगातील समस्यांवर आधारित डिझाइन प्रकल्प पूर्ण करतात. हे प्रकल्प अधिक गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यांच्यावर अधिक संशोधन आणि विश्लेषण करावे लागते.
- **डिझाइन-आधारित उपाय :** विद्यार्थी डिझाइन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधतात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थी ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी नवीन उपाय किंवा पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी एखादे घरगुती उपकरण बनवू शकतात.
- **विविध डिझाइन क्षेत्रांमध्ये अनुभव :** माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना ग्राफिक डिझाइन, प्रोडक्ट डिझाइन, इंटिरियर डिझाइन, यूजर एक्सपिरीयन्स (UX) डिझाइन, आणि ॲनिमेशन यासारख्या विविध डिझाइन क्षेत्रांमध्ये अनुभव घेण्याची संधी मिळते. यामुळे त्यांना त्यांच्या आवडीचे डिझाइन क्षेत्र ओळखता येते आणि त्यांचे करिअर मार्ग निश्चित करता येतात.

डिझाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि समाज कसा प्रभावित होईल ?

➢ **विद्यार्थी :** विद्यार्थ्यांसाठी शिकणे अधिक रंजक आणि मजेदार होईल. परीक्षांऐवजी ते प्रकल्प सादरीकरण आणि गट चर्चांची आतुरतेने वाट पाहतील आणि ते त्यांच्या शिक्षणात अधिक सक्रिय सहभागी होतील. डिझाइन शिक्षणामुळे त्यांची सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता विकसित होईल. यामुळे त्यांना भविष्यातील करिअरसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करता येईल.

➢ **पालक :** पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात अधिक सहभागी होण्याची संधी मिळेल. ते डिझाइन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊन आणि त्यांच्या मुलांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मुलांच्या सर्जनशीलतेला चालना देऊ शकतात.

➢ **शिक्षक :** शिक्षकांची भूमिका बदलून ते सुविधाकर्ते बनतील, हा नवीन दृष्टिकोन आव्हानात्मक पण संधीपूर्णही आहे. त्यांना आपल्या शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करून तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करावा लागेल, ज्ञान देण्यापेक्षा कुतूहल जागृत करणारे मार्गदर्शक व सहयोगी बनावे लागेल.

➢ **समाज :** नवीन शिक्षण धोरणावर आधारित डिझाइन शिक्षणामुळे समाजात अधिक सर्जनशील आणि नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन मिळेल. डिझाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थी अशा व्यक्ती बनतील ज्या समाजातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्याला अधिक चांगले बनवण्यासाठी नवीन कल्पना आणि उपाय विकसित करू शकतात. जसजसे हे विद्यार्थी मोठे होतील, त्यांच्यासोबत नवकल्पना आणि समस्या-निराकरणाची मानसिकता वाढेल. अशा समाजाची कल्पना करा जिथे लोक समस्यांबद्दल केवळ तक्रार करत नाहीत, तर त्यावर उपाय शोधण्यासाठी सक्रियपणे काम करतात.

डिझाइन शिक्षणाचे फायदे

डिझाइन प्रकल्पांवर काम करून विद्यार्थी स्वतःच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे धैर्य करतात. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. विद्यार्थ्यांची समस्या सोडवण्याची क्षमता विकसित होते. त्यांच्यात संघ भावना वाढते. सामाजिक जाणीव निर्माण होते.

नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्यातील डिझाइनवरील भर केवळ शिकवण्याची आणि शिकण्याची पद्धत बदलत नाही, तर शिक्षणाकडे पाहण्याचा संपूर्ण दृष्टिकोन आणि त्याद्वारे आपला समाज बदलत आहे. यामधूनच एक नवकल्पक आणि समस्या-निराकरण करणाऱ्यांची पिढी तयार होणार आहे.

kiran.sabnis123@gmail.com
(लेखक आयआयटी, मुंबईमधून डिझाइनमध्ये पदव्युत्तर पदवीधर असून त्यांना कॉर्पोरेट, शिक्षण क्षेत्रातील अनुभव आहे.)

शब्दकोडे- ३७२

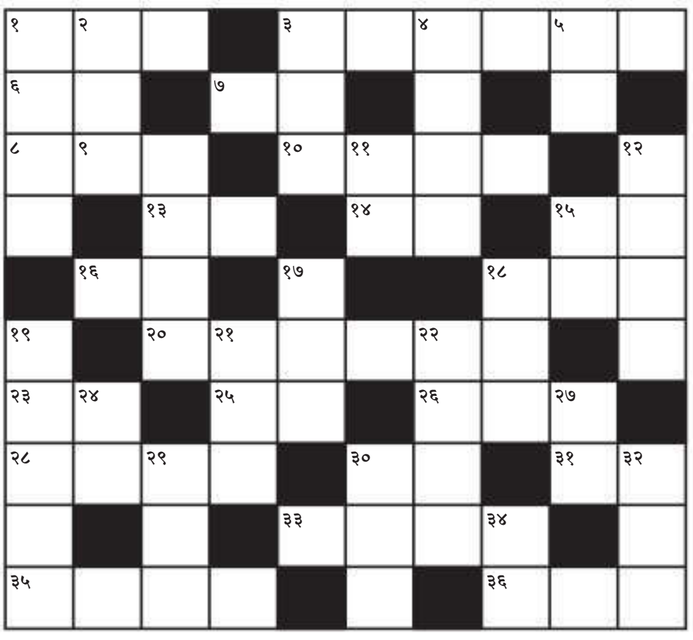

आडवी विधाने : (१) श्रीकृष्णाचे पालन - पोषण या गावात झाले (३) कायदे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची सभा (६) साठ मिनिटांचा काळ (७) आग लागली की हा निघतोच (८) काखेत कळसा गावाला XXX - एक म्हण (१०) सकस, सुपीक (१३) अद्दल, ठोकर (१४) शंकर, प्रत्येक (१५) रवी, भास्कर (१६) सिमेंट, चुना, खडी यांचे जमीन तयार करण्यासाठी केलेले मिश्रण (१८) शुक्र, रावा (२०) जगण्यासाठी करावी लागणारी धडपड (२३) एका हाताची ओंजळ (२५) 'बलुतं' या पुस्तकाचे लेखक (फक्त नाव) (२६) लग्नात वधू-वरांची काढलेली सवाद्य मिरवणूक (२८) मारून टाकता येईल अशा परिस्थितीत प्राण घेण्याऐवजी सोडून देणे (३०) संगतवार संदर्भासाठी केलेली यादी (३१) विश्व, सृष्टी (३३) पिरपिर, रेव, खडे दाताखाली येण्याचा आवाज (३५) कामात गुंतलेला (३६) देऊळ, मंदिर

उभी विधाने : (१) नातेवाईक, आप्तेष्ट (२) गवताचे किंवा धान्याचे बारीक टोक (३) करणारा, घडवून आणणारा (४) हिमालयात आढळणारा वृक्ष (५) झाकण असलेले, वस्तू ठेवायचे, वाटोळ्या किंवा चौकोनी आकाराचे भांडे (९) वस्तूंची कृत्रिम टंचाई (११) बरोबर, धरून (१२) सहल, यात्रा (१५) धान्य पाखडण्याचे साधन (१७) कन्या, मुलगी (१८) विहिरीतून पाणी काढण्याचे साधन (१९) चरितार्थ, पोट भरणे (२१) मुख, तोंड (२२) लवणारे, वाकणारे (२४) प्रतिष्ठित व पतदार मनुष्य (२७) दालचिनीचे झाड (२९) मध्य रेल्वेवरील एक स्थानक (३०) सभेत विचारार्थ मांडलेली कल्पना, इशारा (३२) हरवलेला, बेपत्ता (३४) ओरखडा

- चारू नानल

सुडोकू - ३७२

४					६	८		५
				७	२	३		
३	१				४			
२	५	१						
	८						५	
						४	८	७
			६				२	४
		१	७	४				
५		७	३					८

सुडोकू - ३७१ चे उत्तर

८	४	१	६	७	३	२	५	९
३	७	२	८	९	५	४	१	६
९	६	५	४	१	२	३	८	७
५	८	६	१	३	९	७	२	४
७	३	४	२	५	६	८	९	१
१	२	९	७	८	४	६	३	५
६	१	८	५	२	७	९	४	३
४	५	३	९	६	८	१	७	२
२	९	७	३	४	१	५	६	८

शब्दकोडे - ३७१ चे उत्तर

अ	क	स्मा	त		आ	जा	नु	बा	हू
क्ष		र्त		बे	रं	ग		ग	
ता	रा		कां		भ	र	णी		पु
	ख	ल	ब	त्ता		ण		रा	न
त	ण		ळी		तों		स	म	र
म	दा	र		ब	ड	त	र्फ		पी
	र	द	ब	द	ली		रा	ज	
वि		न	र	क		गु	ज	रा	ण
ठो	सा		का		क	ढी		सं	
बा	र	से		ह	ट्टी		अ	ध	र्म

बातचीत से ही रुकेगा युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से न खोलने पर ईरान को भीषण नतीजा भुगतने की धमकी दिये जाने के जवाब में तेहरान द्वारा होमुर्ज को पूरी तरह बंद कर देने की जवाबी धमकी बताती है कि यह युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान की सैन्य विंग आइआरजीसी ने चेताया है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो होर्मुज जलडमरुमध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा. अगर ऐसा होता है, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातोंरात आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक मंदी के खौफनाक दौर की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. आइइए, यानी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख भी कह रहे हैं कि युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत बड़े खतरे में है, और कोई भी देश इसके असर से बचा नहीं रहेगा. संकट को देखते हुए पिछले दिनों आइइए के सदस्य देश आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल निकालने पर सहमत हुए थे, जो एजेंसी के इतिहास में स्टॉक से की गयी सबसे बड़ी निकासी है. हालांकि अब ट्रंप ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की योजना फिलहाल टालने की बात कही है, जिससे मौजूदा संकट के हल होने की उम्मीद बनती है. दरअसल, कच्चे तेल की आपूर्ति की जीवनरेखा बताये जाने वाले होर्मुज जलडमरुमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इस कारण डीजल, जेट ईंधन और एलपीजी की कीमतों में भी भारी वृद्धि हुई है और इससे अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है. इस युद्ध में मारे गये लोगों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, ईरान और लेबनान में असंख्य लोग विस्थापित भी हुए हैं. इस संकट ने भारत के सामने भी अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. दबाव सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम के साथ मानवीय चिंताएं भी हैं. राहत की बात यह है कि इस संकट पर भारत की नजर है. प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि होर्मुज में आवाजाही बंद करना और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है. सिर्फ यही नहीं कि इस बीच उन्होंने ईरान और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के नेताओं से बातचीत की है, बल्कि उनका साफ कहना है कि बातचीत और संवाद से ही पश्चिम एशिया संकट का समाधान निकल सकता है.

होर्मुज पर ट्रंप की धमकी और ईरान की जवाबी धमकी बताती है कि युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ऐसे में, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी संवाद के जरिये इस संकट का हल निकालने की जो बात कही है, वह बेहद महत्वपूर्ण है.

चुनावी मुकाबला कठिन है पश्चिम बंगाल में

जयंत घोषाल
वरिष्ठ पत्रकार
redhat.jayanta@gmail.com

अपने पिछले अनुभवों से सबक लेकर भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी मुकाबले में कई रणनीतियों पर काम कर रही है. इस साल राज्य की सत्ता में तृणमूल कांग्रेस के पंद्रह साल हो जायेंगे, जिस कारण कुछ हद तक एंटी-इनकंबेंसी स्वाभाविक है. ममता बनर्जी इस बार भीषण राजनीतिक दबाव में भी हैं. लेकिन राज्य के हर जिले में तृणमूल की जो सांगठनिक क्षमता साफ दिखाई देती है, भाजपा के पास उसका अभाव है. इसके अलावा, नरेंद्र मोदी का संदेश भी राज्य के हर घर में अभी तक नहीं पहुंच पाया है.

चालीस साल के ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूं. लेकिन कभी मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा, जैसा इस बार दिख रहा है. पश्चिम बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी की सरकार के 15 साल पूरे हो रहे हैं. हर शासक दल के लिए एंटी इनकंबेंसी स्वाभाविक है. अलबत्ता पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने इस बार जो आक्रामक रणनीति अपनायी है, वह अभूतपूर्व है. वर्ष 2021 की तुलना में इस चुनाव में उसका रणकौशल पूरी तरह अलग है. पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा क्या होगा, यह बताना मेरा काम नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं. लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर यह कह सकता हूं कि ममता बनर्जी इस बार भीषण राजनीतिक दबाव में है. भाजपा की आक्रामक रणनीति को वह साजिश बता रही हैं, जबकि भाजपा साम, दाम, दंड, भेद की कौटिल्य नीति कहकर अपनी रणनीति का औचित्य ठहरा रही है.

पश्चिम बंगाल के बांग्ला मीडिया से लंबे समय से जुड़े होने के बावजूद मैं हमेशा दिल्ली में ही रहा और एक पत्रकार के तौर पर मेरा प्रमुख बीट भाजपा रहा. वाजपेयी-आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक दिल्ली में भाजपा के रूपांतरण का मैं गवाह हूं. पश्चिम बंगाल के आम लोग ही नहीं, राजनेता भी कहते हैं कि भाजपा बंगाली अस्मिता, बांग्ला डीएनए को नहीं समझती. राष्ट्रीय स्तर पर वह हिंदुत्व की जो राजनीति करती है, वही मॉडल वह पश्चिम बंगाल में भी अपना रही है. बंगाल में ध्रुवीकरण के जरिये लाभ उठाने की कोशिश उसकी इसी सोच के बारे में बताती है. पश्चिम बंगाल के राजनेता यह भी मानते हैं कि बंगाल की अस्मिता को न समझ पाने के कारण ही भाजपा अभी तक वहां विफल रही है. एक हद तक यह सही भी है. पश्चिम बंगाल में जीत के लिए भाजपा को पैन इंडियन मॉडल के बजाय बांग्ला मॉडल अपनाना चाहिए. लेकिन अपने सतत परिश्रम के बल पर भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर आज जो ताकत हासिल की है, उसे भी समझना होगा. भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जो हारने के बाद भी लगातार काम करती है. ऐसा मैंने पहले भी देखा था, आज भी देख रहा हूं. फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आखिरकार अटल-आडवाणी युग के ही प्रोडक्ट हैं. पश्चिम बंगाल में 2021 और 2024 में अपनी विफलता से भाजपा ने बहुत कुछ सीखा है. इसी कारण इस बार के चुनाव में भाजपा की जीत की संभावना ज्यादा है.

आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के 77 विधायक हैं. राज्य में कांग्रेस की जगह तृणमूल ने ले ली है, कांग्रेस का वोट बैंक वहां महज पांच फीसदी है. वाम मोर्चा वहां उभर नहीं पा रहा. पिछली बार लेफ्ट का वोट बैंक भाजपा के पास चला गया. क्योंकि माकपा को लग रहा था कि 'पहले राम, फिर वाम'. लेकिन इस बार लेफ्ट की रणनीति बदल रही है. युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया पर जोर देकर वह खुद को रिवाइव करना चाह रही है. विधानसभा में लेफ्ट भी शून्य है और कांग्रेस भी. लेकिन इस बार के चुनाव में दोनों अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं. इस बार भाजपा ने 'जय श्रीराम' के नारे को नेपथ्य में रखा है और परिवर्तन को सामने रखकर काम कर रही है. मोदी-शाह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले भी नहीं कर रहे. इसके बजाय भाजपा ममता बनर्जी के कथित कुशासन, लोगों के क्षोभ और जन सुविधाओं के अभाव को आधार बनाकर आक्रामक अभियान चला रही है. वह कह रही है कि पश्चिम बंगाल में पुनर्जागरण फैला था, अतीत के उसी गौरव को वापस लाना है. उत्तर और दक्षिण बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम से भी भाजपा को बल मिला है. उत्तर बंगाल में तृणमूल से निकले हुमायूं कबीर ने नयी पार्टी बनायी है, हालांकि पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही. ऐसे ही, दक्षिण बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में इंडियन सेक्युलर फ्रंट चुनाव लड़ रहा है. इन दोनों ही पार्टियों द्वारा ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी आशंका है. चुनाव में एसआइआर एक बड़ी रणनीति है. अगर इसके जरिये घुसपैठियों, मुस्लिम मतदाताओं तथा तृणमूल मतदाताओं की बड़ी संख्या बाहर हुई, तो ममता बनर्जी को मुश्किल होगी. इस बार नौकरशाही में व्यापक फेरबदल से भी हड़कंप है. अधिकारियों को लग रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आ गयी, तो उनका करियर बर्बाद हो जायेगा. अधिकारियों का स्थानांतरण तो पूर्व चुनाव आयुक्त दिवंगत टीएन शेषन ने भी किया था. लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने व्यापक कदम उठाये हैं. ऐसे ही, राज्यपाल बदलकर भाजपा ने बदली हुई रणनीति का परिचय दिया है. जगदीप धनखड़ और आनंद बोस जैसे पहले के राज्यपाल बोलते ज्यादा थे. लेकिन खुफिया विभाग से आये नये राज्यपाल आरएन रवि कम बोलते हैं, लेकिन तमाम चीजों का आकलन कर रहे हैं. मतदान के दौरान अर्धसैनिक बलों की तैनाती कहां होगी, इस बारे में चुनाव आयोग और प्रशासन को मिलाकर एक कमेटी गठित हुई है, जो एक बड़ी रणनीति है.

इन सबके बावजूद तथ्य यह है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सांगठनिक क्षमता कमजोर है. ममता बनर्जी की जो सांगठनिक क्षमता हर जिले में दिखती है, वह भाजपा के पास नहीं है. चूंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में नहीं रही है, इस कारण उसकी प्रशासनिक योग्यता-क्षमता के बारे में भी बंगाल के लोग आश्वस्त नहीं हैं. लिहाजा, प्रधानमंत्री मोदी परिवर्तन के नारे और मोदी की गारंटी के साथ बार-बार पश्चिम बंगाल में जा तो रहे हैं, लेकिन उनका संदेश पश्चिम बंगाल के घर-घर में नहीं पहंच पाया है. इस लिहाज से भाजपा का यह अभियान अभी अधूरा ही है. दूसरी तरफ सत्ता में होने के बावजूद ममता बनर्जी विपक्षी नेता की तरह व्यवहार कर रही हैं और मोदी-अमित शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं. यानी केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई की छवि बन रही है. वर्ष 2021 में ममता बनर्जी की यह रणनीति कारगर साबित हुई थी. पिछले चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव आयोग को सामने रखकर हिंदुत्ववाद के सामने बंगाली अस्मिता की रणनीति ममता दीदी बुन रही हैं. इस बार बंगाल की जनता क्या करेगी, क्या वह ममता बनर्जी को और भी ज्यादा वोट देकर सत्ता में लायेगी या खामोशी से भाजपा को मौका देगी, यह देखने के लिए हमें और कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

बैंकों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते गोल्ड लोन

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार
satish5249@gmail.com

गोल्ड लोन बैंकों के कारोबार में वृद्धि और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पर इसकी स्थिरता काफी हद तक सोने की कीमत पर निर्भर है. यदि कीमत गिरती है, तो इससे एनपीए के स्तर, कर्ज की रफ्तार और बैंकों की आय सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है.

पिछले दो वर्षों में सोने की कीमत में हुई बढ़ोतरी और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों में बदलाव के कारण गोल्ड लोन में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गयी है. अब ये नियम अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गये हैं. स्वर्ण ऋण मूल्य (एलटीवी) की संरचना को स्तरीकृत किया गया है, सोने की मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और कड़ी कर दी गयी है. गोल्ड मेटल लोन की अवधि 180 दिनों से बढ़ाकर 270 दिनों की कर दी गयी है. ये बदलाव गोल्ड लोन को अधिक आसान और सुरक्षित बनाते हैं, जिससे गोल्ड लोन वितरण में तेज वृद्धि दर्ज हो रही है. गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का विस्तार इतना बढ़ गया है कि यदि इसे अन्य ऋण पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाये, तो कई बैंकों की वास्तविक ऋण वृद्धि 100 से 400 आधार अंकों तक कम हो सकती है.

गोल्ड लोन ने बीते वर्षों में बैंकों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया है. इससे लोन पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ ही ब्याज आय में भारी वृद्धि हुई है. साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिली है. इसके अतिरिक्त, गोल्ड लोन के बढ़ते पोर्टफोलियो से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत कुल ऋण में कम हुआ है. गोल्ड लोन एक सुरक्षित ऋण है, जो 18 से 24 कैरेट सोने के बदले दिया जाता है. इसमें सोने के आभूषणों को गिरवी रखा जाता है. जब तक ऋण की पूरी राशि नहीं चुकायी जाती, तब तक बैंक सोने के आभूषणों को मुक्त नहीं करता. आम तौर पर यह ऋण चुकौती एकमुश्त की जाती है. अप्रैल, 2026 से गोल्ड लोन को और सुरक्षित बनाने के लिए ऋण राशि के आधार पर नया लोन टू वैल्यू (एलटीवी) तय किया जायेगा. उदाहरण के लिए, 2.5 लाख रुपये तक एलटीवी 85 होगा, यानी मार्जिन 15 प्रतिशत. वहीं, 2.5 से पांच लाख रुपये तक एलटीवी 80 प्रतिशत रहेगा और पांच लाख से ऊपर यह 75 प्रतिशत होगा. ऋण राशि को एलटीवी से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि यदि सोने की कीमत गिरती है, तो एलटीवी इसे कवर कर सके और बैंक को नुकसान न हो. हाल के वर्षों में करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक जैसे बैंकों में गोल्ड लोन का हिस्सा काफी बढ़ गया है. आज इन बैंकों के कुल कर्जे में से एक बड़ा हिस्सा केवल गोल्ड लोन से जुड़ा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में दिये बयान के अनुसार, मई, 2025 तक गोल्ड लोन की कुल राशि बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जो मई, 2024 में 1.16 लाख करोड़ रुपये थी.

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर, 2025 तक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 15.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, क्योंकि इसकी कीमत में वृद्धि ने बैंकों को इस सुरक्षित क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया है. नवंबर, 2025 में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 42 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी. इन्वेस्टमेंट इनफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (इक्रा) ने भी अनुमान लगाया है कि मार्च, 2026 तक संगठित गोल्ड लोन बाजार 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. सोने की कीमत में वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक की असुरक्षित ऋणों पर सख्ती के कारण गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है. बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष गोल्ड लोन का वितरण 91 प्रतिशत तक बढ़ गया है. वर्ष 2026 की शुरुआत में सोने की कीमतें बढ़ीं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद मुनाफावसूली और वैश्विक घटनाओं के कारण इसमें गिरावट आयी. वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि 2025 में मजबूत वृद्धि के बाद, 2026 में सोने का रिटर्न मध्यम हो सकता है. हालांकि, अनिश्चितता के कारण इसकी कीमत उच्च स्तर पर स्थिर रह सकती है. गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 के अंत तक सोने की कीमत लगभग 5,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है, जिससे भारत में इसकी कीमत 1.7 लाख से 1.9 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है.

अमेरिका-ईरान संघर्ष, फेडरल रिजर्व की नीति, भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की सोने की निरंतर खरीदारी समग्र सोने की कीमतों को उच्च स्तर पर बनाये रख सकती है. गौरतलब है कि सोने की कीमत में गिरावट बैंक के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि, इससे बैंकों के सोने की गारंटी वाले ऋण प्रभावित हो सकते हैं. बैंक मार्जिन मनी के आधार पर गोल्ड लोन देते हैं, और यदि सोने की कीमत मार्जिन मनी से नीचे गिर जाती है, तो बैंक को नुकसान उठाना पड़ेगा. इससे ऋण प्रक्रिया धीमी हो सकती है, एनपीए बढ़ेगा, और लाभ पर दबाव आयेगा. फिलहाल, कर्ज के मुकाबले सोने की कीमत या मार्जिन मनी अधिक होने के कारण बैंक का लोन सुरक्षित है. अंत में, गोल्ड लोन बैंकों के कारोबार में वृद्धि और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पर इसकी स्थिरता काफी हद तक सोने की कीमत पर निर्भर है. यदि कीमत गिरती है, तो इससे एनपीए के स्तर, कर्ज की रफ्तार और बैंकों की आय सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है. बहरहाल, वर्तमान परिदृश्य में सोने की कीमतों में गिरावट आने लगी है. बैंकों को संभावित नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

खाड़ी देश में अस्थिरता का प्रभाव पूरे अफ्रीकी क्षेत्र पर पड़ेगा

ईरान और इस्राइल, अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध में कुछ ही सप्ताह में हजारों लोग मारे गये हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. गाजा से लेकर लेबनान और अब ईरान तक, आम नागरिक साम्राज्यवाद की कीमत चुका रहा है. अफ्रीका के लिए हजारों किलोमीटर दूर घट रहा यह संकट कोई दूर की भू-राजनीतिक आपदा नहीं है. खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का पूरे महाद्वीप में ईंधन की कीमतों में तीव्र वृद्धि से गहरा संबंध है. इसका परिणाम बढ़ती मुद्रास्फीति और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें हैं. हालांकि, इस संघर्ष में अफ्रीका का हित केवल आर्थिक नहीं है. यह एक कानूनी और राजनीतिक प्रश्न भी है. अफ्रीकी सरकारों के सामने मुद्दा यह नहीं है कि वे ईरान या अमेरिका की प्रशंसा करते हैं या नहीं. प्रश्न यह है कि क्या देशों के बीच बल प्रयोग को नियंत्रित करने वाले नियम अब भी लागू होते हैं? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग करने से रोकता है, ऐसा केवल आत्मरक्षा या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद ही हो सकता है. यह सिद्धांत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का केंद्रीय आधार माना जाता रहा है. पर ईरान पर हुए हमलों के मामले में इनमें से कोई भी कानूनी अपरिहार्यता पूरी नहीं हुई. अफ्रीकी देशों ने पहले भी देखा है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार या मानवीय सुरक्षा के नाम पर शुरू किये गये पश्चिमी सैन्य अभियान कितनी जल्दी अपने घोषित उद्देश्य से कहीं अधिक व्यापक हो गये थे. लीबिया इसका जीता-जागता उदाहरण है. एक दशक से अधिक समय बाद भी लीबिया राजनीतिक रूप से खंडित है. लीबिया के पतन ने व्यापक साहेल क्षेत्र को भी अस्थिर कर दिया. इराक और अफगानिस्तान की तरह, लीबिया भी इस बात का उदाहरण है कि बाहरी शक्तियों द्वारा बलपूर्वक किसी राज्य का पुनर्गठन करने के क्या परिणाम हो सकते हैं.

ALJAZEERA

-ताफी म्हाका

बोधि वृक्ष

बदलाव का एक कदम

नवीनता किसे प्रिय नहीं है. छोटे बच्चे नये खिलौने-नये कपड़ों की ओर आकर्षित होते हैं. पेड़-पौधे पतझड़ के सहारे अपने को नया कर लेते हैं. सांप केंचुल छोड़कर नया हो लेता है. छोटे-छोटे पक्षी तक नवीनता की खोज में एक छोर से दूसरी छोर तक भटकते हैं. स्थूल से लेकर सूक्ष्म पदार्थ तक प्रतिपल अपना रूप बदल कर नवीनता ही तो धारण करते हैं. पुराने को छोड़कर नया हो जाना ही परिवर्तन है. परिवर्तन और नवीनता प्रकृति के विशिष्ट गुण हैं, यही इसकी जीवंतता भी है. इसलिए, जो नवीन नहीं हो पाता, उसके बासीपन को प्रकृति तोड़कर उसे भी नया कर लेती है. वास्तव में, इस नयेपन व परिवर्तन में ही आकर्षण, सुंदरता, मधुरता, चुंबकत्व व खिंचाव है. इसलिए, मानव जीवन के लिए भी नवीनता आवश्यक है. मानव का जन्म ही नित नवीनता के लिए हुआ है. स्वयं के जीवन में नवीनता, अपने आस-पास के वातावरण में नवीनता, घर-परिवार के परिवेश से लेकर समाज, देश-विश्व स्तर पर नवीनता स्थापित करना ही उसकी पहचान है. परंतु इस सकारात्मक नवीन बदलाव के लिए व्यक्ति को अपने भीतर भी नवीनता व आकर्षण लाने की आवश्यकता होती है. इसके लिए अपनी सोच, खान-पान, रहन-सहन व संवेदना में नवीनता लाना, अपनी परंपराओं, संकल्पों, अहसासों में नवीनता लाना आवश्यक है. इससे व्यक्ति के भीतर तक परिवर्तन होगा, फिर आगे का मार्ग सहज प्रशस्त हो जायेगा.

नवीनता से ही जीवन में प्रसन्नता उतरती है. हमारा वेद कहता है- 'आ नो भद्राः क्रतवो यंतु विश्वतः.' अर्थात, विचारों की खिड़कियां खुली रखें और शुभ-उपयोगी-श्रेष्ठ विचारों को चारों ओर से आने दें. जीवन में नवीनता स्थापित हो, इसके लिए केवल नया बनने के विचार ही न लायें, अपितु महसूस करें कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं, हमारी भावनाएं पवित्र, शुद्ध सकारात्मक हो रही हैं. अंतःकरण से उठने वाले नवीनता के इस संकल्प और अहसास के सहारे शरीर एवं मन के हर कोश में परिवर्तन शुरू होगा और फिर जीवनशैली से लेकर भाग्य, प्रारब्ध, सौभाग्य, समृद्धि, प्रतिष्ठा तक सब कुछ परिवर्तित हो उठेगा.

-श्री सुधांशु जी महाराज

कुछ अलग

आपदा के समय गायब होती मानवता

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

कुछ दिन बाद घर से बाहर निकली थी. घर के बाहर की सड़क बहुत व्यस्त रहती है. पैदल चलते, तरह-तरह के वाहनों में भागते लोग. कार्यालय और गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी. पटरियों पर दोनों तरफ पोहा, छोले-कुलचे, पराठे, चाय, पान, सब्जी-फल आदि के ठेले खड़े रहते हैं. सबसे अधिक भीड़ डोसे, इडली, वड़े, सांभर बनाने वाले ठेलों पर होती है.

चलते हुए डोसे वाले के पास पहुंची, तो देखा कि आज वहां कोई ग्राहक नहीं था. डोसा बनाने वाला भी पटरी पर एक तरफ बैठा था. जबकि इस समय वह बहुत व्यस्त रहता है. समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ होगा. उसके पास पहुंचकर रुक गयी. सामने ही गैस का सिलेंडर नजर आया. मैंने उससे पूछा कि तुम्हें भी गैस मिलने में कोई दिक्कत हो रही है. उसने कहा, हां. फिर पूछा कि क्या. वह बोला कि तीन हजार में मिला है. एक ही वाक्य में उसने जैसे सब कुछ कह दिया. लेकिन आज तुम कुछ बना भी नहीं रहे हो. बना रहा हूं, जब कोई आता है. मगर तुम्हारे यहां से तो मैं भी कई बार डोसा, इडली ले जाती हूं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीस मिनट से कम इंतजार करना पड़ा हो. आज क्यों. बोला, मैडम जी क्या करें, जब तीन हजार का सिलेंडर लाये हैं, तो डोसा पुरानी कीमत पर तो बेचेंगे नहीं. अब दाम बढ़ गये हैं, तो लोग भी कम आ रहे हैं. मैंने पूछा कितने दाम. उसने कहा, डोसा अब सौ रुपये का है और इडली पचास की दो. इतनी कीमत सुनकर कुछ आश्चर्य भी हुआ. क्योंकि डोसा सत्तर और दो इडलियां तीस रुपये में मिलती थीं. तो तुमने एक साथ इतने दाम बढ़ा ही क्यों दिये. क्या करें मैडम, पड़ता नहीं पड़ रहा था. हमें कुछ बचेगा नहीं, तो खायेंगे क्या.

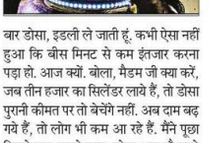

आगे बढ़ते हुए मैं सोचने लगी कि किसी भी आपदा में लोगों को दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ती है. एक तो चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं. मिलती भी हैं, तो कीमत बहुत बढ़ जाती है. अगर एक डोसे वाले ने इतनी कीमत बढ़ा दी है, तो और चीजों पर न जाने कितने दाम बढ़े होंगे. आपदा में अवसर की तलाश इसे ही कहते हैं. एक खबर भी देख रही थी कि अमेरिका, इस्राइल और ईरान युद्ध के कारण दुबई से चलने वाली अधिकांश उड़ानें बंद हो गयी हैं. दुबई से लंदन जाने वाला टिकट सत्रह लाख रुपये का है. पहलगाम त्रासदी के बाद भी हमने एयरलाइंस की मनमानी देखी थी. कोरोना के समय भी ऐसा ही हुआ था. सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा रखा है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है. विपदा या आपत्ति कभी भी, कहीं भी, किसी पर भी आ सकती है. ऐसे में जिस मानवता का राग अलापा जाता है, वह भला कहां गायब हो जाती है, यह समझ से परे है.

आपके पत्र

मासूमों की जान पर भारी भू-राजनीति

दुनिया जहां एक ओर एआइ और अंतरिक्ष अनुसंधान में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर युद्ध की आग मानवता को झकझोर रही है. पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव और काबुल के अस्पताल पर हमले ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की विफलता को उजागर किया है. जिनेवा कन्वेंशन के बावजूद अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले आम होते जा रहे हैं. यह केवल सैन्य चूक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर प्रहार है. संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था प्रभावहीन हो गयी है. युद्ध से शरणार्थी संकट और बुनियादी सुविधाओं का अभाव बढ़ रहा है.

प्रसिद्ध यादव, पटना

बच्चों में बढ़ रहा मोटापा चिंताजनक

विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार भारत बाल मोटापे में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है. पांच से 19 वर्ष के चार करोड़ 10 लाख बच्चों का बीएमआइ सामान्य सीमा से बाहर है, जिनमें एक रोड़ चार लाख बच्चे मोटापे की श्रेणी में हैं. यदि ऐसा ही रहा तो 2040 तक पांच-19 वर्ष के 56 मिलियन और 5-9 वर्ष के 20 मिलियन बच्चे मोटापे के शिकार हो सकते हैं. इससे कम उम्र में डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, फैटी लीवर और हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है. इसलिए स्कूलों जंक फूड पर रोक जरूरी है.

राजकुमार सिंह, कटिहार

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013 ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

सिटी बाइट्स

10 साल बाद चोरी के दो हाथी पश्चिम बंगाल रवाना

सीवान. बड़हरिया थाने के पुरैना से बरामद चोरी के दो हाथी सोमवार को संभागीय वन अधिकारी मेघा यादव के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गये. ये हाथी 2017 में चोरी-छिपे पश्चिम बंगाल से गोपालगंज जिले के सिधवलिया आश्रम लाये गये थे. हाथी सुमन और भोला को मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपा जायेगा. हाल ही में एक हाथी की 22 फरवरी को मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया. 21 मार्च को महावत ईद पर घर आये थे, तब वन विभाग ने छापेमारी कर दोनों हाथियों को बरामद किया. इन्हें पहले मठों में रखा जाता था. अब इन्हें घोड़मारा नेशनल पार्क में पहुंचा कर सौंपा जायेगा.

25 हजार का इनामी अपराधी गिरफ्तार

कटिहार. एसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने 25 हजार के इनामी अपराधी मन्नु उर्फ हसीफ अंसारी को गिरफ्तार किया. आरोपित ने भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह से व्हाट्सएप कॉल कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

नौ लाख की हेरोइन के साथ तीन तस्कर धराये

बरौनी (बेगूसराय). बरौनी जीआरपी ने स्टेशन पर चेकिंग अभियान के दौरान 45.3 ग्राम हेरोइन के साथ दो महिला और एक पुरुष तस्कर गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपितों में पप्पू साह (राघोपुर, वैशाली), प्रमिला देवी (सहदेई, वैशाली) और गणिता देवी (नयागांव दरियापुर, सारण) शामिल हैं. उनसे बरामद नशीले पदार्थ की कीमत लगभग नौ लाख रुपये आंकी गयी है.

रजौली में बिछड़े जंगली हाथी ने मचाया उत्पात

रजौली (नवादा). बिहार-झारखंड के सीमावर्ती रजौली क्षेत्र में झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने तीन दिनों से भारी उत्पात मचा रखा है. दिवौर से शुरू हुआ इसका मूवमेंट हरदिया और पड़रिया जैसे घनी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गया, जिससे लोगों में दहशत है. रविवार रात हाथी ने महसई मुहल्ले में घुसकर दो घरों के दरवाजे तोड़ दिया और एक दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया. दुकानदार कृष्णा साव को करीब 30 हजार रुपये का नुकसान हुआ, जबकि लहसुन की फसल भी बर्बाद हुई. वन विभाग की टीम रातभर मशाल और आवाज के सहारे हाथी को खदेड़ने में जुटी रही.

छोटू सिंह ने सीएम को भेंट किया सुसज्जित चित्र

पटना. बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को सुसज्जित तैल चित्र भेंट किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की.

किडनी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

पटना. किडनी रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ हेमंत कुमार ने कहा है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित जांच से किडनी की बीमारी से बचा जा सकेगा.पाटलिपुत्र नेशनल किडनी फाउंडेशन एवं दूरदर्शन केंद्र, पटना के संयुक्त तत्वावधान में दूरदर्शन केंद्र पटना परिसर में निःशुल्क किडनी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में डॉ हेमंत कुमार के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया.

अगुवानी घाट पथ का 9 किमी निर्माण पूरा

पटना.अगुवानी घाट एवं सुल्तानगंज की तरफ जाने वाली पहुंच पथ में लगभग नौ किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है. वहीं, पसराहा इंटरचेंज का प्रस्ताव संवेदक की ओर से समर्पित कर दिया गया है. इसकी समीक्षा प्राधिकारण के अभियंता द्वारा की जा रही है. प्राधिकरण के अभियंता से अनुमोदन के बाद प्रस्ताव पीआइयू बेगूसराय को एनओसी के लिए समर्पित किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने विधायक की मां को दी श्रद्धांजलि

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोहिउद्दीननगर के विधायक राजेश कुमार सिंह की मां के श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित की. मुख्यमंत्री विधायक श्री सिंह के तीन एम स्ट्रैड रोड जाकर उनकी मां के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की.

राष्ट्र का भविष्य युवाओं पर निर्भर : प्रेम कुमार

पटना. स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने नागपुर के महर्षि व्यास सभागार में आयोजित इंडियन यूथ पार्लियामेंट के 29वें राष्ट्रीय सत्र के समापन समारोह में कहा कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, सोच और नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है. 20 से 23 मार्च तक चले आयोजन में देशभर से हजारों युवाओं ने भाग लिया.

मयूख के आवास पर सत्ताद ने खाया खरना का प्रसाद

पटना. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी विधान पार्षद संजय मयूख के आवास पर पहुंचकर चैती छठ के खरना का प्रसाद ग्रहण किया. श्री मयूख के आवास पर बड़ी संख्या में लोगों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया.

...पहले पेज से

मां कात्यायनी ध्यान मंत्र...

शक्तिमान से शक्ति अलग होने पर भी अलग नहीं समझी जाती . जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है , यह सारा संसार शक्ति और शक्तिमान से परिपूर्ण है और उसी से इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं .

इस आद्याशक्ति की उपासना लोग नाना प्रकार से करते हैं . कोई तो इस महेश्वरी को ईश्वर से भिन्न समझते हैं और कोई अभिन्न मानते हैं . श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि शास्त्रों में इस गुणमयी विद्या-अविद्यारूपा मायाशक्ति को प्रकृति, मूल-प्रकृति, महामाया, योगमाया आदि अनेक नामों से कहा है . उस मायाशक्ति की व्यक्त और अव्यक्त अर्थात साम्यावस्था तथा विकृतावस्था- दो अवस्थाएं हैं. उसे कार्य, कारण एवं व्याकृत, अव्याकृत भी कहते हैं . 23 तत्वों के विस्तारवाला यह सारा संसार तो उसका व्यक्त स्वरूप है, जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह लीन हो जाता है .

(क्रमशः)

प्रस्तुति : डॉ एनके बेरा

दुखद. दो हादसों में सात श्रमिकों की गयी जान, पीएम ने जताया शोक

प्रयागराज में 'कोल्ड स्टोरेज' ढहा सहरसा के तीन मजदूरों की मौत

एक मृतक यूपी निवासी, दो-दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा

प्रतिनिधि, सहरसा/प्रयागराज

प्रयागराज जिले में गंगा नगर के फाफामऊ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक 'कोल्ड स्टोरेज' के अचानक ढह जाने से चार मजदूरों की मौत हो गयी, जबकि 12 श्रमिक घायल हो गये. घायल मजदूरों का इलाज एसआरएन अस्पताल में चल रहा है. इनमें से चार मजदूरों की पहचान सलखुआ निवासी के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही परिजन एक-दूसरे से जानकारी लेने में जुट गये. प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदर्श कोल्ड स्टोरेज में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि अधिकतर मजदूर सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के विभिन्न गांवों के रहने वाले थे. स्थानीय स्तर से

प्रयागराज में मजदूरों की मौत के बाद सहरसा में रोते-बिलखते परिजन.

मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में विद्यानंद चौधरी के पुत्र बिलट चौधरी (35), सक्कों सदा के पुत्र मिसिंद सदा (उम्र 25 वर्ष), नुनुलाल सदा के पुत्र ज्योतिष कुमार (उम्र 21 वर्ष) व जगदीश कुमार (42) निवासी चंदापुर, फाफामऊ शामिल हैं. घायलों में पप्पू यादव, शिंकू यादव, अंकित कुमार, शिवू यादव, साहुल चौधरी, अमित चौधरी, आशू चौधरी सभी सलखुआ प्रखंड के विभिन्न गांवों के निवासी हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 'एक्स' पर किये गये पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्ति करते हुए कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के साथ मेरी सहानुभूति है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जायेगी.

चौसा पावर प्लांट के तीन श्रमिकों की ट्रेन की चपेट में आकर गयी जान

चौसा (बक्सर). चौसा-गहमर रेलवे स्टेशन के बीच यूपी के बारा कलां के पास ट्रेन की चपेट में आने से चौसा पावर प्लांट के तीन श्रमिकों की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कैरमाडीह निवासी जयनाथ साहनी (32 वर्ष), मुजफ्फरपुर के गुलशन राम (35 वर्ष) व वैशाली के पप्पू सिंह (35 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में इनशुल्ट कंपनी में काम करते थे . रविवार की शाम तीनों कि यूपी के गहमर से पैदल रेलवे ट्रैक के रास्ते वापस कंपनी लौट रहे थे. तीनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए डाउन लाइन पर चल रहे थे और सामने से आप लाइन पर गुजर रही ट्रेन पर बैठे यात्रियों की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे .

बेगूसराय में पुलिस की गाड़ी से कुचलने से दंपती की मौत

मृतक दंपती (फाइल फोटो)

बेगूसराय. साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के एनएच 333बी पर सोमवार की अहले सुबह लखीसराय पुलिस की गाड़ी से कुचलने से मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे पति-पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. मृतकों की पहचान रघुनाथपुर बरारी पंचायत के श्रीनगर वार्ड-10 निवासी नथुनी यादव (60 वर्ष) और उसकी पत्नी इंदु देवी (55 वर्ष) के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद भाग रही पुलिस गाड़ी ट्रक से टकराने से पंचर होकर वहीं पर रुक गयी. इसके बाद आसपास के लोगों ने उक्त गाड़ी के चालक और उस पर सवार एक पुलिसकर्मी को पकड़ लिया. बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया. लखीसराय की एसपी प्रेरणा कुमारी ने बताया कि बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल में जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई वह गाड़ी लखीसराय पुलिस की थी. उस गाड़ी में चालक और एक पुलिसकर्मी सवार थे.

दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की गयी जान

गया जी. गया-पंचानपुर मुख्य मार्ग पर केवाली गांव के समीप बीपी आजाद बीएड कॉलेज के पास सोमवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में दोनों बाइक चालकों की मौत हो गयी और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों की पहचान धरमपुर गांव के 22 वर्षीय अक्षय कुमार उर्फ कारू चौधरी और बेलमा गांव के 25 वर्षीय सुभाष कुमार के रूप में हुई. घायल युवक चुन्नु कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

छपरा के दो युवकों की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत

छपरा. मांझी नगर पंचायत क्षेत्र के मियां पट्टी और अलियापुर गांव के राघामोहन राम के पुत्र शंभू राम और स्व. मंगल राम के पुत्र अशोक कुमार राम की दिल्ली-रोहतक रोड बहादुरगढ़ में सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी. दोनों छत के खरना के लिए लकड़ी ला रहे थे, तभी तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मारी. चालक फरार हो गया.

बेटे के प्रेम प्रसंग से आहत पिता ने खुद को लगायी आग, मौत

इस्लामपुर (नालंदा). बेटे के गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग ने पिता को इतना आहत कर दिया कि उसने स्वयं को आग के हवाले कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. खोदागंज थाना क्षेत्र की महमूदा पंचायत के वनबाग गांव में रविवार की देर रात हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है. मृतक की पहचान गांव के ही दिनेश प्रसाद (45 वर्ष) के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश प्रसाद के पुत्र का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. कुछ दिन पहले वह युवती को लेकर घर से फरार हो गया. इस मामले में पुत्र के साथ-साथ दिनेश प्रसाद और अन्य लोगों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था. वहीं, युवती के परिजन दिनेश प्रसाद पर लगातार दबाव बना रहे थे. इसे लेकर पंचायती कर दंड लगाने की बात भी बतायी जा रही है. इसी बात को लेकर दिनेश प्रसाद तनावग्रस्त हो गये थे. रविवार की रात उन्होंने अपने घर में गैस सिलिंडर के पाइप को निकाल दिया और गैस फैलने के बाद आग लगा दी. इस घटना में दिनेश प्रसाद जिंदा जल गये.

दुकानदार को गोलियों से भूना, गयी जान

गोपालगंज. मीरगंज थाने के हथुआ-कुसौधी मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम बाइक सवार एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी, इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. मृतक की पहचान नेरुई गांव के निवासी नारद सिंह के 45 वर्षीय पुत्र कृष्णा सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, कृष्णा सिंह मीरगंज स्थित अपनी दुकान से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान मुड़ा गांव के समीप पहले से घात लगाये अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी.

पिता का आरोप : व्हाट्सएप पर क्लासमेट ने किया था प्रताड़ित, परेशान होकर बेटी ने कर ली खुदकुशी

- अररिया के ही युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप

संवाददाता, भागलपुर

खंजरपुर के झौवाकोठी स्थित मां विंध्यवासिनी छात्रावास में नीट की तैयारी कर रही छात्रा सृष्टि उर्फ लाडो की आत्महत्या के मामले में पिता मनीष सिंह ने अररिया के ही एक युवक को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. आरोपित युवक अररिया निवासी किसलय कुमार सिंह है. पिता का आरोप है कि युवक ने व्हाट्सएप मैसेंजर पर सृष्टि को भद्दी-भद्दी बात कह कर प्रताड़ित किया था. इसी प्रताड़ना के कारण सृष्टि ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली. आरोपित युवक छात्रा का क्लासमेट बताया जा रहा है. हालांकि परिजनों ने सृष्टि और किसलय के बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारी देने से मना किया. लेकिन, परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द युवक पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि उनलोगों को न्याय मिल सके. इधर बरारी थाने की पुलिस ने सृष्टि के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

नानी घर पीरपैंती से माता-पिता और मौसरे भाई के साथ छात्रावास आयी थी सृष्टि : जानकारी मिली है कि दो दिन पहले सृष्टि अररिया में थी. वहां से वह अपने माता-पिता के साथ पीरपैंती स्थित अपने ननिहाल आयी थी. ननिहाल में एक दिन रहने के बाद उसके माता पिता, मौसेरे भाई के मां विंध्यवासिनी छात्रावास में रविवार को शिफ्ट कराने पहुंचे थे. शिफ्ट करने के वक्त हॉस्टल में विभिन्न तरह की प्रक्रिया को पूरी करते सृष्टि और उसके माता पिता को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है.

बिल्डर परियोजनाओं के पूरे कागजात दें, जल्द होगा रजिस्ट्रेशन: विवेक सिंह

कार्यशाला की अध्यक्षता करते रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह .

संवाददाता, पटना

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बिल्डरों से आग्रह किया है कि वे अपने परियोजनाओं के निबंधन हेतु सभी जरूरी दस्तावेज एवं सूचनाएं अपने आवेदन के साथ जमा करें, ताकि उनके परियोजनाओं को कम से कम समय में निबंधित किया जा सके. उन्होंने इस बिंदु को प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही. कार्यशाला में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, रेरा बिहार के वरिष्ठ अधिकारी सहित बिल्डरों ने भारी संख्या में भाग लिया.इस अवसर पर रेरा अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बिहार में निबंधित होने वाली परियोजनाओं की संख्या काफी कम है. प्राधिकरण द्वारा अनेक मौका दिये जाने की बावजूद पिछले कुछ महीनों में जरूरी कागजात के अभाव में करीब एक सौ आवेदन रद करने पड़े.इस समस्या के समाधान हेतु प्राधिकरण ने अब फ्रिल्टर सिस्टम लागू किया है, ताकि बिल्डरों को आवेदन भरते समय ही कमियों का पता चल जाये और सभी दस्तवेज एवं सूचनाएं उलपब्ध होने पर ही वे आवेदन भर सकें. कार्यशाला में बिल्डरों को नये आवेदन प्रक्रिया के विषय में भी काफी विस्तार से बताया गया.साथ ही पीछे के अनुभवों के आधार पर उन्हें उन प्रमुख कमियों के विषय से भी अवगत कराया गया, जिनके कारण आवेदन रद हुए. श्री सिंह ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिल्डरों को रेरा बिहार द्वारा काउंसलिंग की सुविधा भी दी जा रही है.इसके माध्यम से उन्हें जमा किये जाने वाले दस्तावेजों एवं सूचनाओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया जाता है.

सचिवालय अब हाइटेक निगरानी में, हर मूवमेंट पर रहेगी नजर

पटना. सचिवालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित होने जा रही है. अब विभिन्न सचिवालय भवनों में सीसीटीवी कैमरों के साथ केंद्रीकृत निगरानी तंत्र स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए अलग-अलग भवनों में नियंत्रण कक्ष और व्यूइंग सेंटर तय कर दिये गये हैं. गृह विभाग की पहल पर यह पूरी व्यवस्था बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से लागू की जायेगी. अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की संभावना है. योजना के तहत विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, पुराना सचिवालय और सिंचाई भवन में निगरानी केंद्र स्थापित किये जायेंगे. विश्वेश्वरैया भवन के पार्किंग गार्डन क्षेत्र में मुख्य नियंत्रण कक्ष बनाया जायेगा, जबकि जरूरत पड़ने पर प्रवेश द्वार के पास स्थित आगंतुक कक्ष का भी उपयोग किया जा सकेगा.

नक्सलवाद का अंत कर विकास की रफ्तार हुई तेज: सम्राट चौधरी

- सीएम की समृद्धि यात्रा में डिप्टी सीएम जहानाबाद- अरवल पहुंचे

पटना . उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले जहानाबाद और अरवल नक्सल प्रभावित इलाके थे, जहां शाम के बाद ठहरने में भी डर लगता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त कर राज्य में सुरक्षा और विकास का माहौल स्थापित किया है. समृद्धि यात्रा में जहानाबाद-अरवल पहुंचे उपमुख्यमंत्री ने जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले पटना से जहानाबाद पहुंचने में घंटों लगते थे, जबकि अब यह दूरी करीब 40 मिनट में तय हो रही है. अब लोग रात में भी सुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. सड़कों की हालत खराब थी और कुल सड़क नेटवर्क महज छह हजार किलोमीटर था, जो अब बढ़कर करीब 1.40 लाख किलोमीटर हो गया है. राज्य में फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों के साथ एक्सप्रेस-वे का तेजी से विस्तार हो रहा है. बिजली क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहले 17 लाख उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गये हैं. राज्य में 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का बिल शून्य आ रहा है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलायी गयीं, जबकि पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 50 लाख से अधिक रोजगार दिये गये हैं.

पुलिसवालों के बच्चों के लिए प्ले स्कूल का किया जायेगा निर्माण

पटना. बिहार पुलिस मुख्यालय में सोमवार को पुलिस कल्याण कोष की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी, जिसमें पुलिसकर्मियों के हित में कई अहम फैसले लिये गये. डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी. बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ उठाया, जिन पर सहमति बन गयी. पहला निर्णय पुलिस केंद्रों में कार्यरत जवानों के छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर लिया गया. इसके तहत पुलिस केंद्रों में प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर निश्चिंत रह सकें. यह पहल पुलिस परिवारों को बड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है. दूसरा अहम फैसला कनीय पुलिस अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर हुआ. बिहार पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में गेस्ट हाउस बनाये जाने पर सहमति बनी है. बैठक में डीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन, एडीजी सीआइडी पारस नाथ और एडीजी बजट कमल किशोर सिंह समेत कई वरीय अधिकारी इसमें शामिल हुए.

राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेंगे बिहार के मठ-मंदिर : प्रो रणबीर

पटना . बिहार के मंदिरों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जायेगा. बिहार धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष प्रो रणबीर नंदन ने यह जानकारी दी है. चैत्र नवरात्र के अवसर पर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रो नंदन ने कर्नाटक के मैसूर स्थित प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन-पूजन किया. साथ में उनकी पत्नी नम्रता भी मौजूद थीं. उन्हें मां के गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

आज होगी चुनाव में नामांकन शुल्क बढ़ाने संबंधी मामलों की सुनवाई

पटना. एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा पटना हाइकोर्ट में 17 अप्रैल को प्रस्तावित चुनाव में बढ़ाये गये नामांकन शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी . यह याचिका अधिवक्ता सरोज कुमार द्वारा दायर की गयी है. याचिका में शुल्क वृद्धि को मनमाना और अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग हाइकोर्ट से की गयी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में नामांकन शुल्क न्यूनतम स्तर पर था, जिसे अचानक कई गुना बढ़ाकर अधिवक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला गया है. मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, पटना, एडवोकेट्स एसोसिएशन तथा रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाया गया है.

चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका: जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर अब हाइकोर्ट का रुख किया है. इस संबंध में जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सोमवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की.

हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए किया एमओयू

पटना . बिहार राज्य सहकारी बैंक (बीएससीबी) और एएफसी इंडिया लिमिटेड के बीच सोमवार पटना स्थित बैंक में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. इसके तहत बीएससीबी के ग्राहकों के लिए व्यापक स्तर पर कैपासिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित किये जायेंगे. वित्तीय साक्षरता, वित्तीय इंक्लूजन और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा दिया जायेगा. मौके पर बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे, निदेशक सतेंद्र नारायण सिंह, निदेशक विनय कुमार, निदेशक सुधी रंजन प्रसाद, रोहिका जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमन कुमार सिंह आदि मौजूद थे.

मॉनसून से पहले जलजमाव खत्म करने का अल्टीमेटम

संवाददाता, पटना

मॉनसून 2026 से पहले जलजमाव की समस्या खत्म करने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. उपमुख्यमंत्री सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ निर्देश दिया है कि सभी नगर निकाय समय रहते तैयारी पूरी करें, अन्यथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सोमवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था की मजबूती और जलजमाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर की जाए. उन्होंने कहा कि आमजन को मानसून के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं. मंत्री ने यह भी कहा कि पंपिंग सेट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो.

लोहिया जयंती पर जदयू कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा, पहुंचे निशांत

पटना. जदयू प्रदेश कार्यालय में सोमवार को प्रखर समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनायी गयी. इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किये. कार्यक्रम में शामिल निशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉ लोहिया के समाजवादी विचारों को अपनी नीतियों के जरिए धरातल पर उतारने का काम किया है.

ब्लैक बंगाल, जमुनापारी और सिरोही नस्ल की 200 बकरियों का हुआ प्रदर्शन

संवाददाता, पटना

पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार को बकरी उत्सव-2026" का आयोजन किया गया. इसमें बिहार के विभिन्न जिलों 52 बकरी पालकों ने लगभग 200 बकरियों का प्रदर्शन किया. बीटल, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, सिरोही एवं बरबरी शामिल थीं. मौके पर मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि अटारी निदेशक डॉ अंजनी कुमार ने

कहा कि बकरी उत्सवों का आयोजन राज्य के चारों जोनों में किया जाना चाहिए. अटारी एवं बिहार के कृषि विज्ञान केंद्र सहयोग करेंगे. उन्होंने पशुओं के उपचार में हर्बल चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं प्रत्येक केवीके में हर्बल गार्डन स्थापित करने की बात कही.

अमर उजाला

प्रवाह

7 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 24 मार्च 2026

महंगाई और युद्ध, कुछ लोगों के लिए थोड़े समय के लिए अमीरी ला सकते हैं, पर अंत में हमेशा बर्बादी ही लाते हैं। - अर्नेस्ट हेमिंग्वे

लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी के पहले सार्वजनिक संबोधन ने राष्ट्र की चिंताओं को ध्वनित करने के साथ ही समाधान की दिशा भी दिखाई है। ऐसे वैश्विक संकटों में एकजुटता और आत्मनिर्भरता ही देश के सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं।

संकट और संदेश

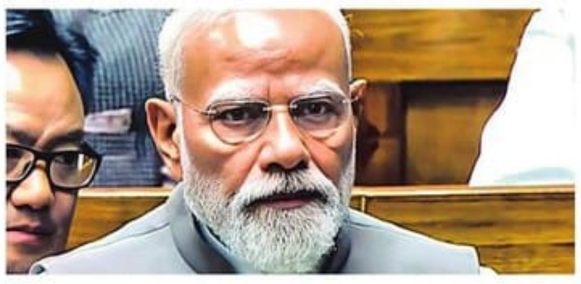

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की महत्वपूर्ण बैठक के एक दिन बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत की आधिकारिक रणनीतिक स्थिति को तो स्पष्ट किया ही, इसने राष्ट्र की चिंताओं को ध्वनित करने के साथ ही समाधान की दिशा भी दिखाई है। पिछले महीने की 28 तारीख को ईरान पर अमेरिका व इस्राइल के संयुक्त हमलों से शुरू हुए इस संघर्ष ने होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग को प्रभावित किया है, जहां से दुनिया का 20 फीसदी ईंधन गुजरता है। प्रधानमंत्री का यह कहना निस्संदेह आश्वस्तकारी है कि अब हम पहले के 27 की जगह करीब 41 देशों से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। लेकिन, जिस तरह से युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसे देखते हुए मांग व आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने की चुनौती जरूर होगी। इसके अतिरिक्त, इस युद्ध ने चाबहार, भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारा और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारा (आईएनएसटीसी), जैसी पश्चिम एशिया में चल रही उन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी संकट खड़ा कर दिया है, जिनसे भारत के हित जुड़े हैं। ऐसे में, भारत को अपने उन समझौतों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, जिनके सफल संचालन के लिए पश्चिम एशिया में शांति अनिवार्य शर्त है। उन वैकल्पिक मार्गों की ओर मुड़ने की भी जरूरत है, जो वैश्विक संकटों में भी हमें कमजोर न पड़ने दें। भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो प्रवासी भारतीयों की वापसी के आंकड़ों में भी दिखता है। गौरतलब है कि करीब 3.75 लाख भारतीय अब तक सुरक्षित लौट चुके हैं, जिनमें 700 से अधिक पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हालांकि, यह स्थिति दो मोर्चों पर चुनौती पेश कर सकती है। एक तो लौटने वालों के पुनर्वास की चुनौती होगी, और दूसरा इसके आर्थिक नुकसान भी हैं। भारत को हर वर्ष विदेश में रहने वाले भारतीयों से जितना रेमिटेंस प्राप्त होता है, उसका करीब आधा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जहां करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं। इसके अलावा, जिस तेजी से देश ने डिजिटलीकरण को अपनाया है, उसे देखते हुए विदेशी सर्वरों पर निर्भरता एक राष्ट्रीय जोखिम भी पैदा कर सकती है। ऐसे में, प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने का निर्देश दिया है। जैसा कि कोरोना संकट के समय में भी देखा गया था, ऐसे वैश्विक संकटों का फायदा उठाने के लिए जमाखोरों के गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, जिन पर नियंत्रण जरूरी है। ट्रंप का पांच दिन में समझौता करने का दावा मौजूदा स्थितियों में भले ही संशयपूर्ण हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि ऐसे वैश्विक संकटों में एकजुटता और रणनीतिक स्वायत्तता ही देश के सबसे अहम हथियार हैं।

वैश्विक संकट रातोंरात खत्म नहीं होते

पिछले हफ्ते, दो भारतीय एलपीजी टैंकर होर्मुज पार कर भारत पहुंचने में सफल रहे। कुछ और टैंकरों के आने की खबरें हैं। यह भारत की सक्रिय कूटनीति और तेहरान के साथ सीधे तालमेल का नतीजा है। इससे समस्या से कुछ हद तक निजात जरूर मिल सकती है, पर यह संकट रातोंरात खत्म होने वाला नहीं है।

पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध का भारत के मिड-डे मील से क्या लेना-देना है? इसका संक्षिप्त उत्तर है-बहुत गहरा। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी है, जिसकी लपटें अब तेजी से फैल रही हैं। तीन हफ्तों के भीतर ही युद्ध दूर-दराज की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर रहा है और करोड़ों बच्चों व परिवारों के जीवन पर असर डाल रहा है। दुनिया भर में ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, जिससे ऐसी असमानता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जो पहले कभी नहीं देखी गई।

रसोई गैस (एलपीजी) वह ईंधन है, जिससे भारत में लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं। यही गैस प्रधानमंत्री पोषण (पीएम पोषण) मिड-डे मील योजना के तहत लगभग 11 करोड़ बच्चों के लिए भोजन बनाने में उपयोग होती है, और आंगनवाड़ी केंद्रों (जहां छह साल से कम उम्र के लाखों बच्चों को पूरक पोषण मिलता है) की रीढ़ है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले संकीर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। इसी से होकर दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल और गैस गुजरती है। ऐसे में, युद्ध के कारण होर्मुज से होने वाली आपूर्ति पर पड़े दबाव ने गैस सिलिंडरों की उपलब्धता को प्रभावित किया है। नतीजतन, कई आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों की रसोइयों में या तो गैस की अनियमित आपूर्ति हो रही है या उन्हें मजबूरन लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है।

भारत में मिड-डे मील योजना से जुड़े लगभग 27 लाख रसोइए और सहायक कर्मियों में से 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। इनमें से कई महिलाएं तो हालिया संकट से पहले भी लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर थीं। अब एलपीजी संकट गहराने के साथ और अधिक महिलाएं पारंपरिक चूल्हों की ओर लौट रही हैं।

दिल्ली समेत देश के कई शहरों की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोग भी एक बार फिर चूल्हों की ओर लौटने को मजबूर हैं। सूरत के टेक्सटाइल उद्योगों में कामकाज धीमा पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और ओडिशा से आए प्रवासी मजदूर गैस सिलिंडर की किल्लत और महंगाई के कारण अपने घरों को लौट रहे हैं। आम परिवारों पर भी महंगाई की मार स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि घरेलू (गैर-सब्सिडी) एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हो चुकी है, जबकि काले बाजार में इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बाइक से सामान पहुंचाने वालों का मुनाफा खत्म हो रहा है, और एफएमसीजी कंपनियां डिटर्जेंट, बिस्कुट, टूथपेस्ट और पैकेजिंग जैसे उत्पादों की लागत बढ़ाने की चेतावनी दे रही हैं।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भले ही सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर मिल रहा हो, पर लंबी देरी के कारण उन्हें भी लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि, जिन लोगों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी), महंगे दामों पर गैस खरीदने की क्षमता, या फिर इंडक्शन चूल्हे के साथ भरोसेमंद बिजली है, वे इस संकट से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। पर अधिकांश लोगों के पास ऐसे विकल्प नहीं हैं।

गौरतलब है कि भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, और इनका करीब 90 फीसदी हिस्सा होर्मुज मार्ग से होकर ही गुजरता है। इस मार्ग में आई बाधाएं, भारत में मौजूदा एलपीजी संकट की एक बड़ी वजह बन गई हैं। पिछले हफ्ते, दो भारतीय एलपीजी टैंकर होर्मुज पार कर गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचने में सफल रहे। इनके जरिये करीब 92,712 टन एलपीजी भारत पहुंची, जो देश की एक दिन की जरूरत के बराबर है। खबरें हैं कि कुछ और टैंकर भारत आ सकते हैं। यह भारत की सक्रिय कूटनीति और तेहरान के साथ सीधे तालमेल का नतीजा है। इन सबके बावजूद यह संकट रातोंरात खत्म होने वाला नहीं है।

भारत हर साल लगभग 3.1 से 3.3 करोड़ टन एलपीजी की खपत करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन इसकी केवल लगभग 40 फीसदी जरूरत ही पूरी कर पाता है। बाकी की आपूर्ति खाड़ी देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा होर्मुज के रास्ते ही की जाती है। हालांकि, भारत ने आपातकालीन स्थिति के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का भंडारण तैयार कर रखा है, जो आयात बंद होने की स्थिति में दो से तीन महीने तक काम आ सकता है। पर रसोई गैस के मामले में अतिरिक्त भंडार मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मौजूदा बाधाएं पेट्रोल पंपों की तुलना में रसोई घरों को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। इसलिए, रसोई ईंधन के लिए कोई भरोसेमंद 'प्लान बी' (वैकल्पिक योजना) एक ही समाधान पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि इसमें विविधता, भंडारण और मांग में लचीलापन, इन तीनों का संतुलित मेल जरूरी है। आपूर्ति के स्रोत बढ़ाना-जैसे अमेरिका और खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से भी दीर्घकालिक समझौते करना-एक ऐसा कदम है, जिस पर पहले से काम चल रहा है। इसका असर अमेरिका से बढ़ते आयात में साफ दिख रहा है।

ऐसे में, भारत को घरेलू स्तर पर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का गंभीरता से आकलन करना होगा और भंडारण क्षमता का विस्तार भी जरूरी होगा, क्योंकि मंगलूरू और विशाखापत्तनम में मौजूद सुविधाएं मांग के मुकाबले सीमित हैं। पाइपलाइन से गैस (पीएनजी) वितरण का विस्तार, बिजली से खाना पकाने के विकल्प और वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग-ये सभी मिलकर दबाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे देश में, जहां असमानताएं बेहद गहरी हैं, रसोई ईंधन के लिए कोई एक सार्वभौमिक 'प्लान बी' संभव नहीं है। कम आय वाले परिवारों और छोटे दुकानदारों के लिए तुरंत कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना और भी कठिन है। ऐसे में कोयला और लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ता है, जिसके गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव सामने आते हैं।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने ऊर्जा संकट को एक कड़वी सच्चाई बना दिया है। यह उस धुएं में साफ दिखती है, जो स्कूल के बच्चों के लिए खाना बनाती महिलाओं की आंखों में चुभता है; यह उस कर्ज में झलकती है, जो रसोई गैस खरीदने के लिए लिया जा रहा है; और यह उस महंगाई में महसूस होती है, जो धीरे-धीरे हर घर के बजट को खा रही है।

जाहिर है, भारत को अब नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में अपनी रफ्तार तेज करनी होगी और देश के भीतर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे संकटों का सामना मजबूती से किया जा सके।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

नॉर्मन विंसेंट पील

यदि हम मन में आत्मविश्वास और साहस के विचार रखते हैं, तो वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, भय और संदेह के विचार हमें पतन की ओर ले जाते हैं।

मन तो चुंबक की तरह है

***बाहरी** परिस्थितियां हमारे आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। इसलिए, यदि आप जीवन में सफलता और शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। बिना खुद पर भरोसा दिखाए, आप न तो सफल हो सकते हैं और न ही सुखी। खुद पर किया गया यह भरोसा आत्मविश्वास कहलाता है। यह आत्मविश्वास कोई अहंकार नहीं, बल्कि इस सत्य की स्वीकृति है कि आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं।*

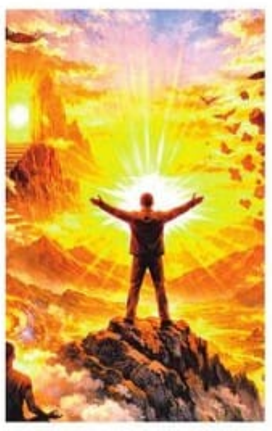

अक्सर हम अपनी कमियों और विफलताओं का इतना अधिक चिंतन करते हैं कि अपनी असली ताकत को ही भूल जाते हैं। ऐसे में, आप अनजाने में अपने चारों ओर पराजय का एक घेरा बना लेते हैं। याद रखिए, आपके विचार ही आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप हार के बारे में सोचेंगे, तो हार जाएंगे, पर यदि आप अपने मस्तिष्क में विजय का चित्र बनाएंगे, तो आपकी मानसिक ऊर्जा उस चित्र को हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय हो जाएगी। इसलिए, अपने मन से हीनता की भावना को बाहर निकाल दें। हीनता की इस दीवार को ढहाने के लिए आपको अपने मन को सकारात्मक सुझावों से भरना होगा। इसके लिए, जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसके विपरीत एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार को जगह दें। उदाहरण के लिए, यदि आप महसूस करते हैं कि 'मैं यह नहीं कर सकता', तो साहसपूर्वक कहें, 'मैं वह सब कुछ कर सकता हूं, जो मेरे लिए आवश्यक है।'

दरअसल, हमारा मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। यदि हम आत्मविश्वास और साहस के विचार रखते हैं, तो हम वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, भय और संदेह के विचार हमें पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए, हर रोज खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर ने आपको डरपोक नहीं, बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम के साथ बनाया है। याद रखें यह प्रक्रिया निरंतर अभ्यास की मांग करती है। इसलिए, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें और यह मान लें कि वे पहले से ही आपके हैं। जब आप इस मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होने लगती हैं। बाधाएं अब आपको डराती नहीं, बल्कि वे आपकी क्षमता को परखने का अवसर बन जाती हैं।

विश्वास का अर्थ यह है कि आप अपने डर के बजाय अपनी संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं और सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अपने मन को शांति और विश्वास से भरें, और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई और उज्ज्वल दिशा की ओर मुड़ जाता है।

- द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के अनूदित अंश

मन में जीत का चित्र बनाइए

सूत्र

आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है, क्योंकि वही आपके विचारों, निर्णयों और कर्मों को दिशा देता है। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, तब भय कमजोर पड़ जाता है और संभावनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसलिए, अपने मन में विजय का चित्र बनाइए, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा को लक्ष्य की ओर प्रवाहित करता है।

दूसरा पहलू

हरियाणा के भिवानी जिले के रोहनात गांव के माथे पर लगे 'बागी' के कलंक को मिटाने के लिए 78 साल से लड़ाई जारी है।

दशकों से वजूद की लड़ाई लड़ता एक गांव

हरियाणा के भिवानी जिले का रोहनात महज गांव नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता और आजादी के मतवालों की वह दास्तान है, जिसे तोपों के गोलों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जनमानस के सीने में मशाल बनकर जलती रही। इस गांव का वजूद खत्म करने के लिए जमीन तक नीलाम कर दी गई। बागी गांव का कलंक माथे पर लगा दिया, जिसे मिटाने के लिए 78 साल से लड़ाई जारी है। व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताने के लिए इस गांव ने कभी आजादी का जश्न नहीं मनाया।

गुरदीप सिंह

रोहनात और इसके साथ लगते गांवों ने 29 मई, 1857 को अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों के खजाने लूट लिए।

तत्कालीन उपायुक्त ने 14 सितंबर, 1857 को गांव की जमीन नीलाम करने का फरमान सुना दिया। रोहनात वासियों ने कभी आजादी का जश्न नहीं मनाया। वे आज भी बागी होने का कलंक झेल रहे हैं।

रोहनात का जर्रा-जर्रा इसकी गौरवगाथा बयां करता है। गांव में घुसते ही ऐतिहासिक कुआं ध्यान खींचता है। बताते हैं कि सैकड़ों महिलाओं ने अपनी अस्मत बचाने के लिए इसी कुएं में जलसमाधि ली थी। कुछ दूरी पर ही विशाल ठूंठ के रूप में खड़ा बूढ़ा बरगद अंग्रेजों की बर्बरता की मूक गवाही देता है। इसकी शाखाओं पर विद्रोही बेटों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी।

11 मई, 1857 की बात है। दिल्ली में पहले स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों को संदेशा भिजवाया। रोहनात और इसके साथ लगते गांवों ने 29 मई, 1857 को अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और उनके खजाने लूट लिए। जेल तोड़कर कैदियों को भगा दिया। 12 अंग्रेज अफसर हिसार और 11 हांसी में मारे गए। बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने 30 सितंबर, 1857 को गांव पुट्ठी मंगलखां में तोपें तैनात कर रोहनात पर भीषण गोलाबारी कर दी। गांव के नेता बीरड़ दास बैरागी को तोप से उड़ा दिया। नोंदाराम जाट को रोड रोलर से कुचल दिया और रूपा खाती को बरगद पर फांसी दे दी। महिलाओं को अस्मत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगानी पड़ी। हिसार के तत्कालीन उपायुक्त मिस्टर विलियम ख्वाजा ने हांसी के तहसीलदार को 14 सितंबर, 1857 को गांव की जमीन नीलाम करने का फरमान सुना दिया। 20 जुलाई, 1858 को 20,656 बीघा, 19 बिस्वे जमीन नीलाम कर इसे बागी गांव का दर्जा दे दिया।

इतिहासकार डॉ. महेंद्र सिंह बताते हैं कि रोहनात के लोग जमीन पर मालिकाना हक और दस्तावेज से बागी शब्द हटवाने की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। रोहनात वासियों ने कभी आजादी का जश्न नहीं मनाया। उनका मानना है, वे आज भी गुलामी की दासता झेल रहे हैं। हालांकि, 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां ध्वजारोहण कर आश्वासन दिया कि उनका खोया वजूद लौटाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यहां की नौजवान पीढ़ी पूर्वजों पर गर्व करती है, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के बजाय बलिदान का रास्ता चुना। उन्हें भरोसा है कि एक दिन सरकार सुध लेगी और उनके ऊपर से बागी का कलंक जरूर हटेगा।

आंकड़े

आतंकवाद का केंद्र

2025 में दुनिया भर में आतंकवाद से होने वाली कुल मौतों में 70 प्रतिशत केवल पांच देशों में हुईं। इनमें पाकिस्तान शीर्ष पर है।

पाकिस्तान	1,139
बुर्किना फासो	846
नाइजीरिया	750
नाइजर	703
कांगो	467

आंकड़े विभिन्न देशों में आतंकवाद से होने वाली मौतों की, संख्या में।

स्रोत : वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026

हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि प्रभु का स्वभाव कोमल और शरणागत वत्सल है। उनकी भक्ति के लिए योग्यता नहीं, पूर्ण समर्पण की जरूरत होती है।

प्रभु तो शरणागत वत्सल हैं

सीता जी की खोज करते हुए हनुमान जी लंका के मध्य में एक अद्भुत भवन देखते हैं। वह भवन रावण के महलों जैसा तामसी नहीं था। वहां 'राम' नाम अंकित था और आंगन में तुलसी के पौधे लहलहा रहे थे। हनुमान जी चकित रह गए कि राक्षसों की नगरी में ऐसा वैष्णव भक्त कौन है? वह विभीषण का घर था। आधी रात के समय जब विभीषण जागे और प्रभु का स्मरण किया, तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनसे भेंट की। विभीषण ने जब एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखा, तो वह अत्यंत प्रभावित हुए और पूछ बैठे कि *तुम्ह हरि दासन्ह महं कोई। मोरें हृदय प्रीति अति होई॥*

परस्पर परिचय के बाद विभीषण ने बड़े ही करुण स्वर में हनुमान जी से पूछा कि क्या मुझ जैसे तामसी राक्षस पर भी कभी प्रभु श्रीराम कृपा करेंगे? मैं तो दुष्टों के बीच वैसे ही रहता हूं, जैसे दांतों के बीच जीभ। तब हनुमान जी ने विभीषण को अपनी भक्ति का रहस्य समझाते हुए एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, 'हे विभीषण! प्रभु का स्वभाव अत्यंत कोमल और शरणागत वत्सल है। मेरी ओर ही देखिए। मैं एक वानर हूं, जिसे लोग सुबह याद करना भी शुभ नहीं मानते। फिर भी कृपानिधान ने मुझ पर अपनी असीम कृपा दिखाई और मुझे अपना प्रिय दास बना लिया।

अंतर्यात्रा
संकलित

हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि भक्ति में योग्यता नहीं, केवल 'आर्त भाव' और 'पूर्ण समर्पण' की आवश्यकता होती है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 24 मार्च, 1954

फौजी व आर्थिक मदद में भारी अंतर

फौजी व आर्थिक मदद में भारी अंतर
पाकिस्तान पर अंकुश रखा जायगा
अमरीकी राजदूत जॉर्ज ऐलन का भाषण

भारत में अमेरिकी राजदूत जॉर्ज एलन ने कहा कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को फौजी मदद देना भारत-पाकिस्तान के संबंधों में हस्तक्षेप करना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली फौजी व आर्थिक मदद में भारी अंतर है।

एसआईआर विरोध के साये में चुनाव

चार राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग और एसआईआर विरोधी अभियान का साया दुर्भाग्यपूर्ण है।

अवधेश कुमार — मुद्दा

चार राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सबसे राहत देने वाला पक्ष इसका सीमित चरणों में संपन्न होना है। इन पांचों प्रदेशों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता 25 लाख ईवीएम मशीनों के माध्यम से 824 विधानसभा सीटों के लिए 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में दो चरण में मतदान होंगे, जबकि शेष राज्यों में एक ही चरण में।

भारत की सुरक्षा व्यवस्था अब उस स्थिति में पहुंच गई है, जहां सुरक्षा बलों की कुछ ही टुकड़ियों को एक से दूसरी जगह चुनाव कराने के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं। अब भारत में चुनावी हिंसा न के बराबर है। पश्चिम बंगाल अवश्य डरावना अपवाद बना हुआ है, किंतु वहां हिंसा मतदान के दिन से पूर्व और बाद में ही ज्यादा होती है। इन प्रदेशों में केवल असम में भाजपा तथा पुदुचेरी में राजग की सरकार है। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में द्रमुक तथा केरल में एलडीएफ या वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है। इस चुनाव में नेतृत्व, विकास, हिंदुत्व जैसे सामान्य मुद्दे तो हैं ही, एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका को विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति अपनाई है।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भी दिया जा चुका है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिला है। इस दृष्टि से देखें, तो यह चुनाव पिछले सारे चुनावों से भिन्न नजर आएगा। हालांकि, एसआईआर को लेकर जैसा विरोध और आरोप-प्रत्यारोप पश्चिम बंगाल से देखने को मिला है, उससे लगता है कि शायद मतदाता सूची से सबसे ज्यादा नाम वहीं कटे हैं। पर सच यह है कि सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु से कटे हैं। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया में 74 लाख 07 हजार 207 लोगों के नाम हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 66 लाख लोगों के नाम कटे। केरल में आठ लाख, असम में केवल दो लाख और पुदुचेरी में सबसे कम 77 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। असम में विशेष पुनरीक्षण कराया गया था। एसआईआर प्रक्रिया के बाद संशोधित मतदाता सूची से संपन्न बिहार चुनाव में राजग को एकपक्षीय बहुमत प्राप्त हुआ। राहुल गांधी द्वारा एसआईआर व चुनाव आयोग के विरुद्ध चलाए सारे अभियान जनता की दृष्टि में निष्फल साबित हुए। बेशक उनकी सभा में भीड़ आती रही, पर जमीन पर कहीं भी एसआईआर मतदाताओं के बीच मुद्दा नहीं बन सका। छोटी-मोटी परेशानियों और एकाध विवादों को छोड़कर आम लोगों को एसआईआर से कोई समस्या नहीं हुई।

मगर ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं हैं। पश्चिम बंगाल इस समय ऐसा राज्य साबित हो रहा है, जिसके लिए कोई प्रक्रिया, विधान किसी तरह का सांविधानिक पद, केंद्र सरकार की योजनाएं आदि की स्वीकृति और अस्वीकृति ममता बनर्जी की मनमर्जी पर है। उन्होंने एसआईआर को इस तरह पेश किया, मानो यह वास्तविक मतदाताओं और विशेषकर तृणमूल समर्थकों को सूची से बाहर निकालने का भाजपा के षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। इसे मुस्लिम विरोधी भी बताया जा रहा है। वह स्वयं काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तक गईं। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया। मगर शीर्ष अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया और लगभग 60 लाख तार्किक विसंगतियों के निराकरण के लिए विभिन्न राज्यों के न्यायाधीशों को जिम्मेदारी सौंपी।

ममता बनर्जी ने इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की, पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने का साहस न करें। पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य है, जहां चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद संपूर्ण मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरक मतदाता सूची जारी की जाएगी। हालांकि, केरल में वाम मोर्चे ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है, किंतु कांग्रेस के लिए तो है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के लिए भी यह प्रमुख मुद्दा नहीं है और वहां कांग्रेस चूंकि सीमित भूमिका में है, इसलिए शायद इसकी ज्यादा गूंज सुनाई नहीं पड़ेगी।

तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भाजपा इतनी सशक्त नहीं है कि वह सरकार बना सके। बंगाल में भी तृणमूल भाजपा में जबर्दस्त टक्कर है। भाजपा जीत गई, तब तो ममता बनर्जी यही कहेंगी कि चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया। अगर वह जीत गईं, तो कहेंगी कि एसआईआर प्रक्रिया को जनता ने ठिकाने लगा दिया। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी! वास्तव में चुनाव आयोग और एसआईआर विरोधी अभियान के साये में मतदान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चाई सबके सामने है, परंतु किसी सूरत में विपक्ष के प्रमुख नेता इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

डॉलर में मजबूती और बाजार में गिरावट से रुपया पहली बार 94 के नीचे

क्रूड में उछाल से रुपये पर बढ़ा दबाव, बाद में 93.53 पर बंद

नई दिल्ली। डॉलर में मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट से सोमवार को रुपया दिन के कारोबार में 50 पैसे टूटकर पहली बार 94 के स्तर के नीचे 94.03 पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में सुधरकर डॉलर के मुकाबले 93.53 के पिछले कारोबारी सत्र के भाव पर बंद हुआ।

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने रुपये को और कमजोर कर दिया। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया भारी गिरावट के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 93.84 पर खुला और गिरकर पहली बार 94 के नीचे पहुंच गया। रुपया शुक्रवार को 64 पैसे की गिरावट के साथ 93 के स्तर के नीचे बंद हुआ था। ब्यूरो

मीराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर घरेलू बाजारों के बीच शुक्रवार को रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और पहली बार 94 का आंकड़ा पार कर गया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों के बाहर जाने का भी रुपये पर दबाव पड़ा।

क्यों टूट रहा रुपया

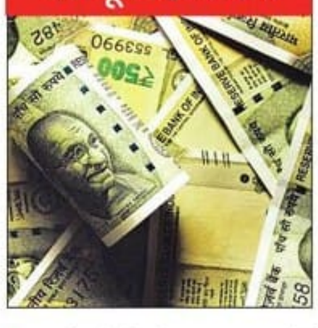

■ विशेषज्ञों के अनुसार भारत का आयात खर्च बढ़ रहा है और रुपये पर दबाव पड़ रहा है। विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार पैसा निकालना और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट भी रुपये की कमजोरी की वजह बनी।

■ आरबीआई की भूमिका पर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक बाजार में मौजूद रहा, लेकिन डॉलर की ज्यादा मांग के कारण रुपये को गिरने दिया गया। आने वाले समय में रिजर्व बैंक हस्तक्षेप कर सकता है।

युद्ध शुरू होने के बाद 3 फीसदी टूटा भाव...किसे फायदा, किसे नुकसान

28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय रुपये में लगभग 3 फीसदी की गिरावट आई है। रुपया कमजोर होने से आयात महंगा होता है और महंगाई बढ़ती है। भारत तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का बड़ा हिस्सा आयात करता है। रुपया गिरने से इन चीजों की कीमत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई का दबाव बढ़ता है।

■ **आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल जैसी कंपनियां जो विदेशों में अपना माल बेचती हैं, रुपया कमजोर होने से फायदे में रहती हैं।**

विदेश यात्रा, महंगी चीजें खरीदना या विदेश में पढ़ाई करने वालों को रुपया गिरना महंगा पड़ता है। एनआरआई बेहतर विनिमय दर का फायदा उठाकर अधिक पैसे भारत भेज सकते हैं। रुपया लगातार गिरता रहे तो विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और वे भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल सकते हैं।

अमेरिकी डॉलर में मजबूती

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। निवेशक जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ी है। डॉलर सूचकांक, जो अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा को मापता है, बढ़कर 99.62 पर पहुंच गया। वहीं, यूरो, येन और पाउंड जैसी मुद्राएं कमजोर रहीं। बढ़ती महंगाई की चिंता के कारण दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक अब सख्त रुख अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है, तो डॉलर और मजबूत हो सकता है, जबकि अन्य मुद्राओं पर दबाव बना रहेगा।

नए-पुराने कर कानूनों के तहत काम करेगा ई-फाइलिंग पोर्टल

जुलाई में रिटर्न भरने के लिए होगा पुराने फॉर्म का इस्तेमाल

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसका ई-फाइलिंग पोर्टल पुराने और नए कर कानूनों, दोनों के तहत काम करेगा। पिछले सालों से जुड़े सभी निर्धारण, अपील और दूसरी कार्रवाई तब तक पुराने कानून के तहत ही चलती रहेंगी, जब तक उनका अंतिम निपटारा नहीं हो जाता। सरकार इस बात के लिए जरूरी कदम उठा रही है कि दोनों कानूनी ढांचे इनकम टैक्स पोर्टल पर बिना किसी रुकावट के एक साथ काम करें।

नए कानून, 2025 के लागू होने से कुछ दिन पहले जारी किए गए सवालों के एक सेट में आयकर विभाग ने कहा कि जो टैक्सपेयर जुलाई 2026 में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, वे पुराने कानून के तहत तय किए गए फॉर्म का इस्तेमाल करके करेंगे। टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर का भुगतान जून 2026 से शुरू होगा, ये कानून के अनुसार किया जाएगा। नया कानून छह दशक पुराने कानून की जगह लेगा। ये एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। आयकर विभाग ने कहा, एक अप्रैल 2026 से 1961 का कानून रद्द हो जाएगा। हालांकि, इसके प्रावधान एक अप्रैल से पहले शुरू होने वाले सभी टैक्स वर्षों पर लागू होते रहेंगे। एजेंसी

न्यूज डायरी

निर्यात प्रोत्साहन योजना में छूट सीमा बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को निर्यात उत्पादों शुल्क और कर छूट योजना पर लगाई गई 50 फीसदी की सीमा हटा ली। यह योजना निर्यातकों को उनके द्वारा उत्पादित और वितरित किए जाने वाले निर्यात उत्पादों पर लगे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के करों और शुल्कों की भरपाई करती है। ये किसी अन्य कार्यक्रम के तहत रिफंड नहीं होते। इस कदम से निर्यातकों को बेहतर नकदी प्रवाह मिलेगा और प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। एजेंसी

अलोक सिंह इंडिगो के मुख्य रणनीति अधिकारी

नई दिल्ली। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व सीईओ अलोक सिंह भारतीय एयरलाइन इंडिगो के मुख्य रणनीतिक अधिकारी होंगे। इंडिगो ने सोमवार को इसकी घोषणा की। यह नियुक्ति 6 अप्रैल से प्रभावी होगी। अलोक सिंह को रणनीति और व्यवसाय विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के लिए जाना जाता है। इंडिगो का कहना है कि उनकी विशेषज्ञता कंपनी को विस्तार और प्रतिस्पर्धात्मक मजबूती में मदद करेगी। एजेंसी

कोल इंडिया की इकाई का आईपीओ 25 फीसदी भरा

नई दिल्ली। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.का आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) दूसरे दिन यानी सोमवार को 25 फीसदी सब्सक्राइब हुआ। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, इस इश्यू के तहत 7.97 करोड़ शेयरों के मुकाबले 2.02 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। योग्य संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 62 फीसदी भरा, जबकि खुदरा निवेशकों का हिस्सा 17 फीसदी भरा। एजेंसी

आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में 79,256 करोड़ रुपये डाले

मुंबई। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में एकदिवसीय वैरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) नीलामी के जरिये सोमवार को 79,256 करोड़ रुपये की अस्थायी नकदी डाली। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा, धनराशि 5.26फीसदी की कट-ऑफ और भारित औसत दर पर डाली गई। केंद्रीय बैंक ने इससे पहले 20 मार्च को तीन दिन की वीआरआर नीलामी के जरिये बैंकिंग प्रणाली में 25,101 करोड़ की नकदी डाली थी। एजेंसी

इंडियन बैंक ने इन्फ्रा बॉन्ड से जुटाए 5,000 करोड़

मुंबई। इंडियन बैंक ने 10 वर्ष की अवधि वाले दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉन्ड जारी कर 7.15 फीसदी की कूपन दर पर 5,000 करोड़ जुटाए हैं। बैंक को 7.13 फीसदी कूपन दर पर 3,100 करोड़ के लिए दो बोलियां मिलीं। इसके अलावा, 7.14 फीसदी और 7.15 फीसदी कूपन दर पर क्रमशः 4,100 करोड़ रुपये एवं 5,050 करोड़ रुपये की दो-दो बोलियां प्राप्त हुईं। एजेंसी

कच्चे तेल में उबाल से सेंसेक्स 1,837 अंक टूटा, 15 लाख करोड़ डूबे, आज दिखेगी तेजी

बाजार एक साल के निचले स्तर पर, युद्ध शुरू होने से अब तक 50 लाख करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। तेल की कीमतों में उछाल से सेंसेक्स 1,836.57 अंक टूटकर एक साल के निचले स्तर पर 72,696.39 पर बंद हुआ। निफ्टी 601.85 अंक गिरकर 22,512.65 पर बंद हुआ। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों की बाजार पूंजी 15 लाख करोड़ घटकर 414.77 लाख करोड़ रुपये रह गई।

सेंसेक्स की 30 में 27 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। टाइटन सबसे ज्यादा 6.24 फीसदी नुकसान में बंद हुआ। सिर्फ तीन कंपनियों के शेयर एचसीएल टेक, पावरग्रिड और इन्फोसिस 1.83 फीसदी तक बढ़त में रहे। बीएसई पर कुल 4,556 शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 3,858 गिरावट में रहे और सिर्फ 581 शेयर बढ़त में बंद हुए। **बाजार में यह गिरावट 2020 के उस चर्चित क्रैश की छठी बरसी पर हुई है, जब निफ्टी 50 एक ही दिन में 13% गिर गया था।** उस दिन बाजार इसलिए गिरे थे क्योंकि सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। ब्यूरो

सर्वाधिक टूटने वाले शेयर

टाइटन	6.24%
ट्रेंट	5.90%
अल्ट्राटेक सीमेंट	5.20%
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स	4.85%
इंडिगो	4.85%

बाजार में इसलिए आई बड़ी गिरावट

यह गिरावट बड़े पैमाने पर हुई। मुख्य वजहें थीं...बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल और बाजार की अस्थिरता में तेजी, जो दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। शेयरों में बढ़त और गिरावट का अनुपात 1:14 के तेज स्तर पर रहा, जो इस बात का संकेत है कि बड़े पैमाने पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है।

विशेषज्ञों के अनुसार, तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना और रुपये का कमजोर होना निवेशकों को सतर्क बना रहा है।

■ जियोजित फाइनेंशियल के विनोद नायर ने कहा, बाजार में यह गिरावट एशियाई बाजारों की कमजोरी, मिडिल ईस्ट तनाव और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित रुकावट को दर्शाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद निवेशक और भी सतर्क हो गए।

धातु कंपनियों के शेयर 4.25 फीसदी धड़ाम

बाजार में भारी गिरावट के बीच मेटल सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखी गई और निफ्टी मेटल सूचकांक करीब 4.25 फीसदी गिरकर 10,927 पर आ गया। मार्च में अब तक निफ्टी मेटल करीब 11 फीसदी गिर चुका है।

लगातार निकासी कर रहे विदेशी संस्थागत निवेशक

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध रूप से 10,414.23 के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,033.97 करोड़ की खरीदारी की। विदेशी निवेशकों ने मार्च में अब तक 88,180 करोड़ की निकासी की है। विदेशी निवेशकों ने मार्च में भारतीय शेयरों और बॉन्ड से 11 अरब डॉलर से अधिक रकम निकाल ली है।

गिफ्ट निफ्टी 800 अंक उछला

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के बाद गिफ्ट निफ्टी और वैश्विक बाजारों में सुधार देखने को मिला। खबर लिखे जाने तक गिफ्ट निफ्टी वायदा लगभग 800 अंकों की बढ़त के साथ 23,280 पर था। अगर ये जारी रहा तो सेंसेक्स करीब 2000 अंक ऊपर खुल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम संघर्ष की दिशा और कच्चे तेल की कीमतें तय करेंगी कि आगे बाजार में सुधार होगा या और ज्यादा गिरावट आएगी।

एचडीएफसी बैंक तीन सत्र में 12 फीसदी टूटा

कार्यकारी चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट जारी है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में बैंक का शेयर करीब 12 फीसदी टूट गया, जिससे पूंजीकरण में 1.52 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। सोमवार को बैंक का शेयर बीएसई पर 4.70 फीसदी गिरकर 743.75 रुपये पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक समय यह 5 फीसदी टूटकर 52 सप्ताह के अपने निचले स्तर 740.95 रुपये तक आ गया था। एनएसई पर यह 4.65 फीसदी गिरकर 744.15 रुपये पर बंद हुआ।

सोना 9,050 रुपये सस्ता चांदी 4.36 फीसदी टूटी

कमजोर मांग से सराफा कीमतों में आई गिरावट

नई दिल्ली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू मांग में नरमी से सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में करीब 6 फीसदी तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोना 9,050 रुपये या करीब 6 फीसदी सस्ता होकर 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव आ गया। चांदी की कीमत भी 10,500 रुपये या 4.36 फीसदी की गिरावट के साथ 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, सराफा धातुओं में पिछले सप्ताह की गिरावट बढ़ गई। सोमवार को दिन के कारोबार में हाजिर सोना चार महीने के निचले स्तर पर फिसल गया। इस तेज गिरावट की वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें ऊंची हो गईं और महंगाई की चिंताएं बढ़ गईं। इससे कठोर मौद्रिक रुख की आशंका बढ़ गई, जिससे अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर में मजबूती को बढ़ावा मिला। इससे सोने-चांदी पर और दबाव बढ़ गया।

वेंचुरा के एन एस रामास्वामी ने कहा, ईरान संघर्ष के कारण हालिया तेल के झटके ने उन देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जो सोने के भंडार का निर्माण कर रहे थे।

अब क्या करें निवेशक

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल और इंडसइंड सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का कहना है कि सुरक्षित निवेश होने के बावजूद सोने की तेजी कमजोर पड़ रही है। आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अनिश्चितता बनी है। जब तक तनाव, महंगाई और ब्याज दरों पर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक सोने पर दबाव बना रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 43 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 227.42 डॉलर या 5.06 फीसदी टूटकर 4,263.73 डॉलर प्रति औंस रह गया। चांदी 4.25 डॉलर या 6.3 फीसदी टूटकर 63.53 डॉलर प्रति औंस रह गई। पिछले सप्ताह सोने की कीमत 5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2026 के सबसे निचले स्तर पर आ गई। यह सोने में 43 वर्षों की सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट रही।

संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत

आरबीआई ने कहा, पश्चिम एशिया संकट और अमेरिकी व्यापार जांच से बढ़ी अस्थिरता

मुंबई। रिजर्व बैंक का कहना है कि वैश्विक संकटों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और वित्तीय स्थिति नियंत्रित है। सोमवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बुलेटिन में कहा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हैं और ये बाहरी झटकों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, मिडिल ईस्ट में जारी संकट और अमेरिका की नई ट्रेड जांचों ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2025-26 के लिए दूसरे अग्रिम जीडीपी अनुमान से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से स्थिर बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी के संकेतों से अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद बनी हुई है। वहीं, खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई।

रिजर्व बैंक ने कहा कि सिस्टम में तरलता पर्याप्त बनी हुई है। वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह बढ़ा है, जिसमें बैंक और गैर-बैंक स्रोतों से दोनों में वृद्धि हुई है। एजेंसी

जनवरी में 2.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा खरीद

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी में विदेशी मुद्रा बाजार में 2.52 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा खरीदी। ये पिछले 8 महीनों में पहली नेट खरीदारी थी। यह कदम रुपये पर दबाव के बीच आया। मासिक बुलेटिन के अनुसार, जनवरी में बैंक ने लगभग 28 अरब डॉलर खरीदे और 25.47 अरब डॉलर बेचे। दिसंबर में आरबीआई ने बाजार में नेट 10 अरब डॉलर बेचे थे। रिजर्व बैंक स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में हस्तक्षेप करता है ताकि मुद्रा विनिमय दर की अस्थिरता को कम किया जा सके। एजेंसी

सरकारी बैंकों के विलय की योजना नहीं : केंद्र

नई दिल्ली। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय या एकीकरण का फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा, पहले किए गए बैंकों के विलय से मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक बने हैं, जिनकी कार्यक्षमता और पहुंच में सुधार हुआ है। विलय के बाद बैंकों को बड़े कर्ज देने की क्षमता बढ़ी, कम लागत वाले जमा तक बेहतर पहुंच मिली और उनका ग्राहक आधार व बाजार विस्तार हुआ।

मंत्री ने कहा, डिजिटलीकरण और बेहतर प्रबंधन से लागत में कमी आई है और कामकाज ज्यादा प्रभावी हुआ। इन सुधारों से बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। एजेंसी

युद्ध ने बदली भारतीयों की पसंद घरेलू पर्यटक स्थलों पर उमड़ी भीड़

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारतीय यात्रियों की यात्रा पसंद बदल गई है। हाल के हफ्तों में लोग मिडिल ईस्ट की जगह एशियाई और घरेलू गंतव्यों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। यात्रा प्लेटफॉर्म इक्सिगो की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के हफ्तों में घरेलू स्थानों की बुकिंग बढ़ी है। इसका मुख्य कारण फ्लाइट में रुकावटें और मिडिल ईस्ट में हवाई क्षेत्र की सीमाएं हैं। ब्यूरो

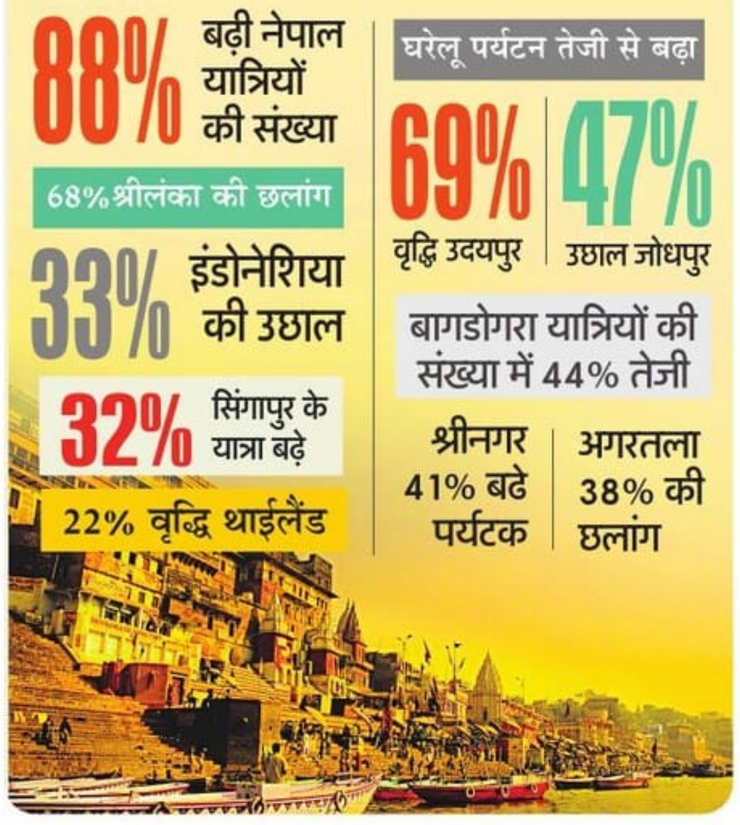

जेपी मामला : वेदांता की याचिका पर एनसीएलएटी ने रोकी सुनवाई

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को वेदांता ग्रुप को निर्देश दिया कि वह अपनी अपील में अदाणी समूह को भी शामिल करे। वेदांता ने इस अपील के जरिए एनसीएलएटी द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए अदाणी इंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ की बोली को मंजूरी देने के आदेश को चुनौती दी है।

चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की बेंच ने वेदांता से कहा कि वह अदाणी इंटरप्राइजेज को याचिका की सूचना दें और उन्हें पक्षकार बनाएं। बेंच ने सुनवाई मंगलवार के लिए स्थगित कर दी। वेदांता ने एनसीएलएटी में दो अपीलें दायर की हैं। पहली में रिजॉल्यूशन प्लान की वैधता को चुनौती दी गई है और दूसरी में कर्जदाताओं की समिति और एनसीएलएटी द्वारा प्लान की मंजूरी को चुनौती दी गई है। जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 57,185 करोड़ का कर्ज है। इसे चुकाने में डिफॉल्ट होने के बाद जून, 2024 में दिवाला प्रक्रिया में डाला गया था। एजेंसी

घरेलू उद्योग को बचाने के लिए चीन रेयान धागे पर लग सकता है डंपिंग-रोधी शुल्क

नई दिल्ली। भारत सरकार की व्यापार जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने चीन से आने वाले रेयान धागे पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह ड्यूटी 386 डॉलर से 1,071 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के बीच हो सकती है। यह शुल्क खासतौर पर 75 डेनियर से अधिक मोटाई वाले रेयान धागे पर लागू होगा। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है।

जांच में पाया गया कि चीन से सस्ते दाम पर आयात (डंपिंग) बढ़ने से भारत के घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। इसके चलते बाजार में

कीमतें भी दबाव में आ गई हैं। अगर वित्त मंत्रालय इस सिफारिश को मंजूरी देता है, तो यह ड्यूटी पांच साल तक लागू रहेगी। इस कदम का मकसद भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को राहत देना और घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाना है। एजेंसी

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौद्रिक नीति समिति का कैलेंडर जारी

रेपो रेट पर पहला निर्णय 8 अप्रैल को

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौद्रिक नीति समिति की छह बैठकों का कैलेंडर जारी किया। पहली बैठक 6-8 अप्रैल को होगी। मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। यह समिति रेपो रेट जैसी नीतिगत दरों का फैसला करती है। आमतौर पर बैठक के तीसरे दिन वोटिंग के माध्यम से निर्णय होता है। फैसले की घोषणा गवर्नर करते हैं।

मौद्रिक नीति समिति की दूसरी समीक्षा बैठक जून में होगी ,इसके बाद अगस्त, अक्तूबर, दिसंबर और फरवरी में तीन-दिवसीय बैठकें होंगी। मौद्रिक नीति समिति का काम घरेलू आर्थिक परिस्थितियों और खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लेना है। पिछली बैठक में फरवरी 2026 में समिति ने शॉर्ट-टर्म लेंडिंग रेट यानी रेपो रेट 5.2 फीसदी पर स्थिर रखा था। सरकार ने पहले अगस्त 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्य और सहनशीलता सीमा घोषित की थी, जिसे मार्च 2021 में अगले पांच वर्षों के लिए बनाए रखा गया था। महंगाई का लक्ष्य 2 से 6 फीसदी है। मार्च 2026 तक इस लक्ष्य की दूसरी समीक्षा होने वाली है। ब्यूरो

कब-कब होंगी एमपीसी की बैठकें

पहली बैठक	6–8 अप्रैल, 2026
दूसरी बैठक	3–5 जून, 2026
तीसरी बैठक	3–5 अगस्त, 2026
चौथी बैठक	5–7 अक्टूबर, 2026
पांचवीं बैठक	2–4 दिसंबर, 2026
छठी बैठक	3–5 फरवरी, 2027

भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में ढील

हर लेनदेन अलग से सेटल करने की जरूरत नहीं

मुंबई। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को विदेशी निवेशकों के लिए ट्रेड सेटलमेंट नियमों में छूट दी। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में भरोसा बढ़ाना है। बाजार में पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़े विदेशी फंड आउटफ्लो देखे गए हैं। इसके बाद सेबी ने ये बड़ा बदलाव किया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा कि अब बड़े विदेशी निवेशक नेट आधार पर ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें अब हर लेनदेन को अलग-अलग सेटल करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यूरो

इसका क्या होगा असर

इस बदलाव से विदेशी निवेशकों की फंडिंग जरूरतें और ट्रेडिंग खर्च कम होंगे। विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में वापस आने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और बाजार में नकदी बढ़ा सकता है। सेबी की नई सुविधा विदेशी निवेशकों के लिए बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकती है।

बाजार मध्यस्थों के लिए नियामक ढांचे में बदलाव

बोर्ड ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट और वैकल्पिक निवेश कोष से संबंधित प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी। इसके तहत एआईएफ को किसी योजना को बंद करने की प्रक्रिया में ढील देने को मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने बाजार मध्यस्थों के लिए नियमों में बदलाव किया है। केवल प्राथमिकी दाखिल होने मात्र से किसी व्यक्ति को काम करने से रोकने या अयोग्य ठहराने के नियम को हटाया गया।

अधिकारियों के लिए कड़े नियम

मुंबई। सेबी ने सोमवार को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हितों के टकराव संबंधी नियम कड़े कर दिए। नए नियमों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को अपना कार्यकाल शुरू होने पर निजी शेयर निवेश को बेचना या फ्रीज करना होगा। वे नौकरी के दौरान किसी भी ट्रेड में हिस्सा नहीं ले सकते। चेरपर्सन सहित सेबी के शीर्ष चार स्तर के अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का विवरण घोषित करेंगे। अधिकारी उन मामलों से स्वयं को अलग रखेंगे, जिनमें उनका कोई आर्थिक हित या संघर्ष हो। यह बदलाव सेबी द्वारा नवंबर 2025 में की गई सिफारिशों के आधार पर आया है। ब्यूरो

एजुकेशन & कॅरिअर

जितना आप खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे।

अमर उजाला **Job Alert**
Real-time job alerts amarujala.com/jobs

रेलवे ने जारी किया विज्ञापन

सहायक लोको पायलट के पदों पर मौके

11,127 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 14 जून, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष
यहां आवेदन करें : rrbapply.gov.in

भारत संचार निगम लिमिटेड ■ 120 पद

वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षु के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2026
वेतनमान रुपये 24,900 से लेकर रुपये 50,500 तक निर्धारित
यहां आवेदन करें bsnl.co.in

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अवसर ■ 59 पद

मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल, 2026
योग्यताएं संबंधित विषय में इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री
यहां आवेदन करें engineersindia.com

सशस्त्र सीमा बल में मौके ■ 233 पद

हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर रिक्तियां
अंतिम तिथि : 20 अप्रैल, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 27 वर्ष
यहां आवेदन करें : recruitment.ssb.gov.in

इरेडा में रोजगार की संभावनाएं ■ 32 पद

महाप्रबंधक, अतिरिक्त महाप्रबंधक व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि 05 अप्रैल, 2026
वेतनमान रुपये 30,000 से लेकर रुपये 3,00,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें ireda.in

सीसीआरएएस में निकली भर्ती ■ 16 पद

सलाहकार व वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पद खाली
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि 30 मार्च से 01 अप्रैल, 2026
पात्रताएं एमडी, एमएस व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें ccras.nic.in

योग्य अभ्यर्थी करें अप्लाई...

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम : सहायक प्रबंधक (विद्युत) के पदों पर मौके।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 17 अप्रैल, 2026
- ncrtc.co.in
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली : प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 01 अप्रैल, 2026
- ird.iitd.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

ताकि बना रहे जीवन में संतुलन

लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें और खुद के प्रति लचीला व व्यावहारिक रवैया अपनाएं, ताकि बेवजह का तनाव हावी न हो

लॉरेन कुयकेन्डाल
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

Harvard Business Review

लक्ष्य निर्धारण को एक दूरदर्शी और लचीली प्रक्रिया के रूप में देखना बेहद प्रभावी दृष्टिकोण है, क्योंकि यह हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता देता है। जब हम लक्ष्यों को पत्थर की तरह कठोर मानने के बजाय मिट्टी की तरह लचीला समझते हैं, तो हम बदलती परिस्थितियों, जैसे काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें और मानसिक शांति के बीच बेहतर संतुलन बना पाते हैं। यह मानसिकता हमें असफलता से हताश होने के बजाय सीखने और अपने रास्ते को समय-समय पर सुधारने की प्रेरणा देती है। इसे लागू करने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें, ताकि दीर्घकाल में निरंतर प्रगति और सफलता सुनिश्चित हो सके।

■ नियमित रूप से समीक्षा करें
अपने लक्ष्यों को स्थिर उपलब्धि के बजाय निरंतर प्रगति की प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक व्यावहारिक और प्रभावी तरीका है। आप समय-समय पर, जैसे हर सप्ताह या महीने रुककर खुद से यह सवाल करें कि जो लक्ष्य आपने तय किया है, क्या वह अभी भी आपकी वर्तमान परिस्थितियों, जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है या नहीं। यदि परिस्थितियां बदल गई हैं, तो लक्ष्य में बदलाव करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी होती है। यह सोच आपको फोकस बनाए रखने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपकी प्रगति निरंतर और संतुलित बनी रहती है।

■ जरूरत के अनुसार गुणवत्ता रखें
उच्च मानकों के अनुसार काम करने का मतलब यह नहीं कि हर बार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही हो, बल्कि यह समझना है कि कब किसी काम को पर्याप्त अच्छे स्तर पर पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार 'पूर्णता' के पीछे भागने से समय और ऊर्जा दोनों अधिक खर्च होते हैं, जबकि वही ऊर्जा यदि परिवार या अन्य जरूरी प्राथमिकताओं पर लगाई जाए, तो जीवन अधिक संतुलित बनता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जहां जरूरत हो वहां बेहतर गुणवत्ता रखें।

■ आंशिक सफलता पर ध्यान दें
यदि आपने 60 मिनट व्यायाम का लक्ष्य रखा था, लेकिन किसी कारण से केवल 15 मिनट ही कर पाए, तो इसे असफलता नहीं, बल्कि प्रगति के रूप में देखना चाहिए।

असल बात यह है कि आपने शुरुआत की और कुछ न करने के बजाय कुछ किया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। लक्ष्य को थोड़ा लचीला बनाकर यह स्वीकार करना कि 15 मिनट भी सफलता है, आपको निराश होने से बचाता है और आगे भी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

■ प्राथमिकताएं समय के अनुसार निर्धारित करें
हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी काम की प्राथमिकता सबसे ऊपर होती है, तो कभी आराम ज्यादा जरूरी हो जाता है। बदलती प्राथमिकताओं में संतुलन बनाना ध्यान भटकना नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करना है। यह सोच हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं को समय देना भी जरूरी है। जब हम हालात के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो हम अधिक संतुलित, शांत और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ पाते हैं।

खुद को परखें

1. हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में मीथेन उत्सर्जन करने वाले शीर्ष तेल और गैस स्थलों की सबसे अधिक संख्या किस देश में थी?
   (a) ईरान
   (b) रूस
   (c) तुर्कमेनिस्तान
   (d) वेनेजुएला
2. हाल ही में खबरों में रहा दक्षिण शेटलैंड द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है?
   (a) अंटार्कटिका
   (b) यूरोप
   (c) उत्तरी अमेरिका
   (d) दक्षिणी अमेरिका
3. अनुमोदित मॉडल और निर्माता आदेश फ्रेमवर्क के लिए नोडल प्राधिकरण कौन-सा मंत्रालय है?
   (a) विद्युत मंत्रालय
   (b) वाणिज्य मंत्रालय
   (c) भारी उद्योग मंत्रालय
   (d) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

उत्तर-1.c, 2.a, 3.d

इंटर्नशिप अलर्ट

एफएसएसएआई इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा एफएसएसएआई इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह इंटर्नशिप स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उच्च डिग्री धारकों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है, जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सीखने का अनुभव मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को रुपये 10,000 प्रतिमाह वजीफा प्रदान किया जाएगा तथा इंटर्नशिप के सफल समापन पर अंतिम रिपोर्ट/प्रस्तुति की समीक्षा के पश्चात संबंधित एफएसएसएआई (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रयोगशालाओं से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक sites.fssai.gov.in/internship/inform.php पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

भारत सरकार की पहल

नेशनल साइंस डे क्विज-2026

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने माईजीओवी के साथ मिलकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन क्विज आरंभ की है, जो महिला वैज्ञानिकों के योगदान, प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों और स्टेम क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाती है। आकर्षक और ज्ञान-आधारित प्रारूप के माध्यम से यह क्विज जागरूकता बढ़ाने, भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा भारत के समावेशी और प्रगतिशील वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र पर गर्व की भावना को मजबूत करने का प्रयास करती है। यह क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक बार ही इसमें भाग ले सकता है। क्विज में कुल दस प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 300 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता का ई प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यताओं की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक tinyurl.com/yc7hkrsy पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से 28 मार्च, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट हफ्ते की परीक्षाएं

एनसीईआरटी ग्रुप ए, बी, सी परीक्षा-2026

- **परीक्षा की तिथि :** 25 व 27 मार्च, 2026
- इस परीक्षा में सेक्शन-ए में सामान्य अंग्रेजी, बोधगम्यता, सामान्य जागरूकता और समसामयिक घटनाओं से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सेक्शन-बी में संबंधित विषय और कंप्यूटर ज्ञान आदि से प्रश्न शामिल होंगे।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/4cby87kc

यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा-2025

- **परीक्षा की तिथि :** 29 मार्च से लेकर 01 अप्रैल, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य हिंदी और निबंध के लिए 150-150 अंकों के प्रश्न होंगे, जबकि सामान्य अध्ययन के पेपर-I, II, III और IV के लिए 200-200 अंकों के प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए तीन-तीन घंटे का समय दिया जाएगा।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/yt5mbytd

सामान्य ज्ञान

स्वयान पहल

■ क्या है
यह भारत में उभरती हुई एक तकनीकी-शिक्षा एवं अनुसंधान पहल है, जिसका उद्देश्य ड्रोन और संबंधित उन्नत तकनीकों में देश की क्षमता को मजबूत करना है।

■ चर्चा में क्यों
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 'स्वयान' पहल के तहत ड्रोन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया।

■ शीर्ष संस्थानों की भागीदारी
आईआईएससी, आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, सी-डैक और एनआईईएलआईटी सहित 30 शीर्ष संस्थानों की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

■ कार्यशालाओं का आयोजन
इसमें लघु डिग्री कार्यक्रमों, बूटकैंप और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है तथा चुनौतियों और नवाचार प्लेटफार्मों के माध्यम से उद्योग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

ऊर्जा — Life Dream Love

जब रोशनी बन जाए इलाज

मौसम या धूप में कमी से कई तरह की मानसिक-शारीरिक दिक्कतें हो जाती हैं। नए शोध बता रहे हैं कि इस तरह के कई विकारों में लाइट थेरेपी बहुत कारगर है। इसमें अलग-अलग रंग की रोशनियों से इलाज किया जाता है।

मौसम में परिवर्तन, लंबी दूरी की यात्रा या दिन के उजाले की अवधि में होने वाले बदलाव इन्सान की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर अलग-अलग प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं। मानव शरीर की जैविक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिद्म के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। जब दिन में उजाले की मात्रा कम या अधिक हो जाती है, तो इससे सर्केडियन रिद्म (जैविक घड़ी) प्रभावित हो सकती है। इसके कारण कुछ लोगों में शरीर की ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जबकि कुछ लोगों में इसके प्रभाव और भी अधिक गंभीर रूप ले सकते हैं।

ऐसे ही प्रभावों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी 'एसएडी'। यह एक प्रकार का मौसमी अवसाद है, जो आम तौर पर सर्दियों के मौसम में अधिक देखा जाता है, जब दिन छोटे होते हैं और धूप कम निकलती है। इस स्थिति में व्यक्ति को उदासी, थकान, प्रेरणा की कमी, अधिक नींद आना, ध्यान में कमी और सामाजिक गतिविधियों में रुचि कम होने जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। कुछ लोगों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उनके दैनिक काम-काज और जीवन की गुणवत्ता तक प्रभावित होने लगती है। इन समस्याओं के उपचार में लाइट थेरेपी को एक प्रभावी विधि माना जाता है।

■ क्या है लाइट थेरेपी
लाइट थेरेपी में एक विशेष प्रकार के कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की तरह काम करता है। यह तेज प्रकाश शरीर की सर्केडियन रिद्म (जैविक घड़ी) को संतुलित करने में मदद करता है और मस्तिष्क में मूड को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, जैसे कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करता है। इसकी मदद से व्यक्ति की ऊर्जा, मनोदशा और नींद के पैटर्न में सुधार हो सकता है। इस थेरेपी में व्यक्ति रोज कुछ समय तक एक विशेष लाइट थेरेपी लैंप के सामने बैठता है।

■ कई विकारों में उपयोग
लाइट थेरेपी में अलग-अलग तरह की रोशनी का इस्तेमाल शरीर या त्वचा की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य प्रकार हैं- ब्लू लाइट थेरेपी, जो मुंहासों के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। रेड लाइट थेरेपी त्वचा की सूजन कम करके घाव भरने और त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद करती है। यूवी लाइट थेरेपी का उपयोग सोरायसिस या विटिलिगो जैसी त्वचा की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा ब्राइट लाइट थेरेपी अवसाद या नींद से जुड़ी समस्याओं में मूड को बेहतर बनाने के लिए दी जाती है। इन सभी में अलग-अलग रंग और तीव्रता की रोशनी का उपयोग करके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाला जाता है।

■ विशेषज्ञ की राय
अमेरिका के वर्मोंट राज्य के बर्लिंगटन शहर में स्थित वर्मोंट विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर केली रोहन के अनुसार, सीजनल अफैक्टिव डिसऑर्डर या मौसमी अवसाद के इलाज के लिए केवल 'लाइट बॉक्स' ही अकेला उपचार नहीं है। अमेरिका में लगभग 5 प्रतिशत लोग इस समस्या से जूझते हैं। अगर आपको इसके लक्षण महसूस हों, तो खुद इलाज करने के बजाय चिकित्सक से सही सलाह लें, क्योंकि जो लोग इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आंखों में खिंचाव और सिरदर्द जैसी सामान्य समस्याएं देखी जा सकती हैं। हालांकि, कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए।

सबसे पहले चिकित्सक की सलाह

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सक और 1980 के दशक से प्रकाश चिकित्सा के प्रभावों का अध्ययन कर रहे डॉ. रेमंड लैम के अनुसार, 'रेटिना पर प्रकाश चिकित्सा के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैकुलर डिजनरेशन या डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी रेटिना संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को लाइट थेरेपी शुरू करने से पहले किसी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।' विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि जो लोग फोटोसेंसिटाइजिंग दवाएं (एंटीसाइकोटिक थियोरिडाजिन और कीमोथेरेपी दवाएं) लेते हैं, उन्हें लाइट थेरेपी शुरू करने से पहले किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। लैम ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि लाइट थेरेपी संवेदनशील व्यक्तियों में उन्माद का दौरा पैदा कर सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि चिकित्सीय लैंप का उपयोग केवल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि कुछ दवाएं और स्वास्थ्य स्थितियां लाइट थेरेपी के अनुकूल नहीं हो सकती हैं।

योग टिप्स

घुटनों में दर्द है तो ऐसे करें वज्रासन

वज्रासन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इससे अपच, गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अलावा भोजन के बाद इस आसन में बैठने से पाचन में सहायता मिलती है। कूल्हों के ऊपर वज्र नाड़ी स्थित होती है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं, तो एड़ियों के दबाव से यह नाड़ी सक्रिय हो जाती है। यह नाड़ी हमारी बड़ी आंत से जुड़ी मानी जाती है। वज्र नाड़ी के सक्रिय होने से पाचन तंत्र में जागृति आती है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त वज्रासन करने पर पैरों और जांघों में रक्त प्रवाह कुछ कम हो जाता है, जिससे पेट के क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। यही कारण है कि वज्रासन को पाचन के लिए अत्यंत लाभकारी आसन माना गया है। अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो आप सहायक वस्तुओं की सहायता से वज्रासन को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से कर सकते हैं। आप वज्रासन को तकिया, मसनद या कंबल की सहायता से बहुत आराम से कर सकते हैं। वज्रासन करने के लिए एक छोटा गोलाकार मसनद लें। वज्रासन की स्थिति में बैठें। मसनद को दोनों टखनों के नीचे रखें। कमर सीधी रखें और दोनों एड़ियां आपस में मिलाएं। मसनद और तकिए के साथ वज्रासन करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठें। फिर धीरे-धीरे वज्रासन की स्थिति में आएं। पिंडलियों और जांघों के बीच एक तकिया रखें। इससे घुटनों पर दबाव कम होगा और आसन अधिक आरामदायक लगेगा। भोजन के बाद इसका अभ्यास करें, परंतु अधिक देर तक न बैठें।

ढाकाराम
योगाचार्य

आज का दिन

24 मार्च, 1945

बिलबोर्ड पत्रिका के पॉप एल्बम चार्ट की शुरुआत हुई थी। इस पत्रिका के पॉप चार्ट में अमेरिकी पियानो वादक और गायक नैट किंग कोल का 'किंग कोल ट्रायो' नंबर वन पर पहुंचने वाला पहला एल्बम था।

- 1905 : फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्ने का निधन हुआ था।
- 1976 : अमेरिकी फुटबाल खिलाड़ी पाइटन मैनिंग का जन्म हुआ था।
- 1999 : नाटो ने यूगोस्लाविया पर बमबारी की थी।
- 2002 : हैले बेरी श्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थीं।

व्रत त्योहार

आज : चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी।
कल : वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 12.00 से 13.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 04 चैत्र मास शक 1948, चैत्र मास 12 प्रविष्टे, 05 सव्वाल हिजरी 1447, चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी 13.49 तक उपरांत अष्टमी, मृगशिरा नक्षत्र 17.32 तक उपरांत आर्द्रा नक्षत्र, सौभाग्य योग 27.08 तक उपरांत शोभन योग, वणिज करण 13.49 तक उपरांत विष्टि (भद्रा) करण, चंद्रमा मिथुन राशि में दिन-रात।

■ सूर्योदय : 06.23
■ सूर्यास्त : 18.31
(भारतीय मानक समयानुसार)

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : सफलता मिलने पर भी मन अशांत रहेगा। व्यावसायिक लाभ कम होगा। परिवार में परेशानी रहेगी।

वृष : मानसिक सुख-शांति बनी रहेगी। शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में उत्तम धन लाभ होगा।

मिथुन : योजना में निराशा हो सकती है। व्यय की अधिकता रहेगी। व्यवसाय में आय-व्यय सम रहेंगे।

कर्क : उच्चस्तरीय संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। मित्रों का समागम रहेगा।

सिंह : सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। बीमा आदि से अर्थ प्राप्ति संभव है।

कन्या : मानसिक तनाव से बचें। संतान पक्ष से मतभेद बना रहेगा। व्यावसायिक लाभ में सुधार आ सकता है।

तुला : सकारात्मक सोच बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में सोच समझकर निर्णय लें। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

वृश्चिक : नई योजना में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। घर में शांति रहेगी।

धनु : आरोग्य सुख में वृद्धि होगी। साक्षात्कार में चयन हो सकता है। विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में दबदबा बना रहेगा।

मकर : मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। नौकरी में कार्य भार अधिक रहेगा। सहयोगियों से निराशा होगी।

कुंभ : आत्मबल बनाए रखें। योजना में आंशिक सफलता मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी आ सकती है।

मीन : उद्देश्य में सफलता मिलेगी। राजनीतिक संबंधों का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में नया अनुबंध एवं धन लाभ होगा।

जन्मदिन

इमरान हाशमी, अभिनेता

इस वर्ष प्रारंभ में श्रम संघर्ष बना रहेगा। योजनाओं में विलंब होगा। जून से अक्टूबर तक समय अनुकूल रहेगा। योजनाएं साकार होंगी। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति से संतुष्ट रहेंगे। अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। जमा पूंजी में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सुडोकू

	1			6	7			2
							7	
		6	8			5		1
			6					9
	9			5			4	
4					1			
1		2			3	4		
	8							
7			2	9			5	

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

5	1	4	3	6	7	9	8	2
8	3	9	1	2	5	6	7	4
2	7	6	8	4	9	5	3	1
3	5	7	6	8	4	2	1	9
6	9	1	7	5	2	8	4	3
4	2	8	9	3	1	7	6	5
1	6	2	5	7	3	4	9	8
9	8	5	4	1	6	3	2	7
7	4	3	2	9	8	1	5	6

डेली हेल्थ कैप्सूल

औषधीय गुणों से भरपूर हैं अरंडी के पत्ते

अरंडी के पत्तों को आयुर्वेद में काफी फायदेमंद माना जाता है। इससे कई समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है।

खराब जीवनशैली के कारण लोग जोड़ों के दर्द, सूजन और पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं के लिए आयुर्वेद में एक प्राचीन औषधि है अरंडी के पत्ते। इन पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं, जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। सरसों या तिल के तेल के साथ गरम करके इन पत्तों का लेप या सिकाई करने से जोड़ों की जकड़न कम होती है। एंटी-सेप्टिक गुणों के कारण इनसे दाद और सोरायसिस जैसी त्वचा की समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है। इन पत्तों में रेचक गुण होते हैं, जो आंतों को उत्तेजित करके पेट को साफ रखने में मदद करते हैं। इनका उपयोग कब्ज, गैस और पेट की सूजन को कम करने में भी किया जाता है। इन पत्तों का पेस्ट घावों को जल्दी भरता है और बालों को बढ़ने में मदद करता है। अरंडी की कोमल पत्तियों का रस (2-3 चम्मच) सुबह खाली पेट पीने से पीलिया और लिवर से जुड़ी समस्याओं में लाभ होता है। अनिद्रा के लिए तेल गरम करें, इसमें अरंडी के पत्ते डाल दें। जब तेल सामान्य हो जाए, तो इससे सिर पर लगाएं। इससे आपका तनाव कम होगा, नींद अच्छी आएगी।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

अरंडी के पत्ते पेट और लिवर के लिए फायदेमंद हैं। इसका गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है। इनका इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेकर ही करें।

-डॉ. राजीव पुंडीर
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

संपादकीय जागरण

मंगलवार, 24 मार्च, 2026 : चैत्र शुक्ल - 6 वि. 2083

बड़ी सफलता के लिए कुछ कड़े निर्णय करने ही पड़ते हैं

विरोधाभासी ट्रंप

ईरान पर भीषण हमले करने की धमकियां देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह यकायक पांच दिन तक ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले रोकने की बात कही, वह उनके विरोधीभासी रवैये का नया प्रमाण ही है। उन्होंने गत दिनों ही यह धमकी दी थी कि यदि ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग नहीं खोला तो उसके बिजली संयंत्रों को तबाह कर दिया जाएगा। इस पर ईरान ने चेताया था कि यदि ऐसा हुआ तो उक्त जल मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और बिजली संयंत्रों की मरम्मत होने तक उसे खोला भी नहीं जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने ईरान से सकारात्मक बात होने और इसके नतीजे में उसके बिजली संयंत्रों और तेल एवं गैस ठिकानों पर अमेरिकी हमले पूरी तौर पर रोकने की घोषणा की। निःसंदेह यह राहत की बात होती, यदि ईरान ने उनके इस दावे पर सहमति जताई होती। ट्रंप के दावे के विपरीत ईरान का कहना है कि अमेरिका से न तो कोई प्रत्यक्ष बात हुई और न ही परोक्ष। इसकी भी अनदेखी न करें कि चंद दिन पहले ही ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा था कि अमेरिका से वार्ता के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसने धोखा दिया है। उनका आशय अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत के बीच इजरायल और अमेरिका के उन हमलों से था, जो 28 फरवरी को शुरू हुए।

माना जाता था कि पिछले वर्ष जून की तरह इस बार भी ईरान इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों का अधिक दिनों तक सामना नहीं कर पाएगा, पर इन हमलों में अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं सैन्य अधिकारियों को खोने के बाद भी ईरान जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम बना हुआ है। उसने इजरायल के साथ ही खाड़ी के देशों को भी निशाना बनाकर युद्ध को एक नया विस्तार तो दिया ही, होर्मुज जल मार्ग बंद कर दुनिया भर में तेल एवं गैस का संकट भी खड़ा कर दिया। यह किसी से छिपा नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान की इस आक्रामक युद्ध रणनीति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। लगता है ईरान की चौतरफा जवाबी कार्रवाई और उसकी बढ़ी हुई मारक क्षमता देखकर ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें? कहीं वे इस युद्ध से निकलने की सम्मानजनक राह तो नहीं तैयार कर रहे हैं? जो भी हो, उनकी समस्या इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि एक ओर जहां ऊर्जा संकट की चुभन अमेरिका को भी महसूस होने लगी है, वहीं दूसरी ओर मित्र देश इस युद्ध में दखल देने को तैयार नहीं। ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, उस पर भरोसा करना कठिन है। ईरान से कथित वार्ता उसे छलावा देने की उनकी चाल भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तो जगजाहिर ही है कि वे अपने कहे से पलटने में माहिर हैं। उनका विरोधाभासी स्वभाव उन्हें अविश्वसनीय बनाने के साथ उनकी फजीहत ही कराता है।

विकास की राह

विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) बढ़ रहा है और यहां के लोगों की औसत आय में भी वृद्धि कर रही है। पिछले वर्ष की तुलना में 7.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 5,31,610 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। बिजली की खपत में वृद्धि हो रही है तथा कारोबार, पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। यह भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन व आवास सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली सरकार को ठोस नीतियां बनानी होंगी

'विकसित दिल्ली' के संकल्प के साथ भाजपा सत्ता में आई है। पिछले एक वर्ष में इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, किंतु संकल्प को पूरा करने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, दूषित यमुना, सार्वजनिक परिवहन, सड़कों की स्थिति, पेयजल, सफाई और आवास जैसी कई गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। इनके समाधान के नाम पर वर्षों से केवल राजनीति होती रही है। वर्तमान सरकार से इन समस्याओं के वास्तविक समाधान की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए सरकार को ठोस नीतियां बनानी होंगी और उनका समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

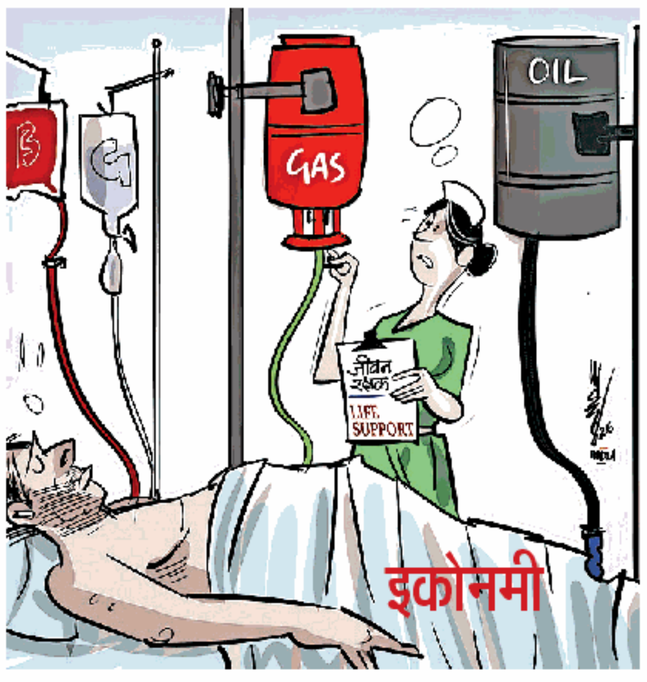

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या ईरान युद्ध और लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है?

आज का सवाल

क्या फिलहाल अमेरिका द्वारा ईरानी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना न बनाने के फैसले से पश्चिम एशिया में तनाव कुछ घटेगा?

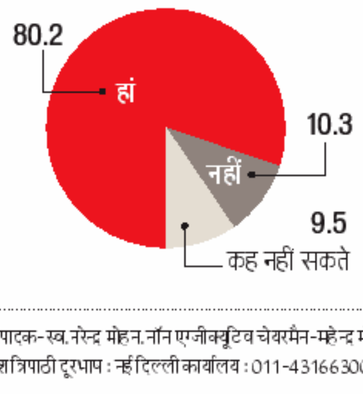

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मुस्लिम मन का अंतर्द्वंद्व

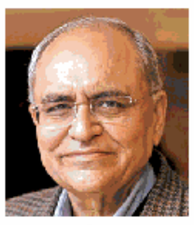

बलबीर पुंज

भारतीय उपमहाद्वीप का जो मुस्लिम गाजा या ईरान पर तीखी प्रतिक्रिया देता है, वही पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में गाए गए मुसलमानों पर चुप्पी साध लेता है

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग से पश्चिम एशिया युद्धभूमि में परिवर्तित हो चुका है। पिछली एक सदी में यह पहली बार है, जब भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान किंकर्तव्यविमूढ़ हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अब तक इस्लाम को किससे तथाकथित 'खतरा' है, इसे लेकर उनकी एक स्पष्ट धारणा थी। तमाम मुस्लिमों की सहानुभूति ईरान के साथ है, परंतु वे इस युद्ध का खुलकर समर्थन इसलिए नहीं कर पा रहे है, क्योंकि ईरान प्रतिक्रियास्वरूप अपने हवाई हमलों से पश्चिम एशिया-खाड़ी के घोषित इस्लामी देशों को भी जख्मी कर रहा है। अब जाएं, तो किधर जाएं?

ईरानी कोप के शिकार खाड़ी देशों में यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इराक और जार्डन के साथ वह सऊदी अरब भी है, जहां सदियों पहले हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इस्लाम ने मजहबी आकार लिया, कुरान का अवतरण हुआ। मुसलमानों के लिए पवित्र मक्का-मदीना यहीं स्थित है। आखिर भारतीय उपमहाद्वीप के तमाम मुसलमान सऊदी और अन्य मुस्लिम देशों पर ईरानी आक्रामकता को 'इस्लाम पर हमला' क्यों नहीं कह रहे हैं? इसका उत्तर खाड़ी देशों की वर्तमान राजनीतिक दिशा और नेतृत्व में निहित है।

सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस), जिनका परिवार मक्का-मदीना का संरक्षक है, 2017 से लगातार ईरान की नीतियों और 1979 की उसकी इस्लामी क्रांति को इस्लामी दुनिया में बढ़ती असहिष्णुता के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस बात के लिए एमबीएस ईरान को कोस रहे हैं, उसका दोषी सऊदी अरब भी रहा है, क्योंकि सऊदी शासन लंबे समय तक कट्टरपंथी वहाबी-सलाफी विचारधारा से प्रभावित 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) की कठोर व्याख्या करते हुए सूफीवाद, शिया परंपराओं और मजार-दरगाह परंपरा का विरोध करता रहा। पेट्रो-डालर की शक्ति से संपन्न सऊदी अरब ने इस विचारधारा के प्रसार के तहत वैश्विक स्तर पर मस्जिदों, मदरसों और इस्लामी संस्थानों का भारी वित्तपोषण किया। 1980 के दौर में अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के समर्थन से सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में जिहाद को बढ़ावा दिया। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी संगठन वहाबी-सलाफी की वैचारिक घुट्टी से ही प्रेरणा पाते हैं, किंतु 21वीं सदी के बदलते वैश्विक परिदृश्य, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उदय, ई-वाहनों के प्रसार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों के चलते सऊदी अरब स्वयं को मध्यकालीन मानसिकता

ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों का विरोध करने के लिए लखनऊ में एकत्रित लोग ● पीटीआई

से बाहर निकालकर व्यावहारिक, उदार और सह-अस्तित्व आधारित समाज बनाना चाहता है। एमबीएस के नेतृत्व में सऊदी अरब पूर्णतः शरीयत-आधारित इस्लामी देश नहीं रह गया है। सत्ता संभालने के बाद उनका कहना था, 'हम अपनी जिंदगी के अगले 30 वर्ष विनाशकारी विचारों से जूझने में नहीं बिताएंगे। हम उन्हें समाप्त कर देंगे।' इसी के चलते बीते एक दशक से सऊदी अरब में वे सामाजिक सुधार हो रहे हैं, जो विशुद्ध इस्लामी दृष्टिकोण में वर्जित (हराम) हैं। इनमें मनोरंजन-पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं को बिना पुरुष संरक्षक के वाहन चलाने की अनुमति, कामकाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने सहित श्रम कानूनों में सुधार शामिल हैं। उन नियमों में भी सुधार किया जा रहा है, जो सह-अस्तित्व में बड़ी बाधा हैं। इसी कड़ी में दो वर्ष पहले पड़ोसी देश यूएई में स्वामीनारायण मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। बहरीन भी हिंदू मंदिर हेतु जमीन आवंटित कर चुका है। वास्तव में सदियों बाद सऊदी अरब समेत खाड़ी देश कट्टरवादी इस्लामी बेड़ियों को काट रहे हैं। जैसे-जैसे अरब देश स्वयं को उदार, सहिष्णु और आधुनिक बना रहे हैं, वैसे-वैसे भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एक वर्ग इन देशों से निराश हो रहा है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ समझना आवश्यक है।

प्रथम विश्वयुद्ध में जब ब्रिटेन ने तुर्किये पर हमला किया, जिसके शासक को इस्लामी जगत में खलीफा की पदवी हासिल थी, तब दुनिया में केवल अविभाजित भारत के मुसलमान खलीफा पद की बहाली हेतु आंदोलित हो उठे, जिसे हम खूनी 'खिलाफत आंदोलन' के नाम से जानते हैं। तब दक्षिण-पूर्व एशिया (इंडोनेशिया-मलेशिया सहित) खिलाफत आंदोलन से अप्रभावित रहा, जहां मुसलमानों की बड़ी संख्या बसती थी। इसके कारण स्पष्ट हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का विस्तार मुख्यतः बाहरी आक्रांताओं के जरिये हुआ, जिससे यहां के मुसलमानों में राजनीतिक-साम्राज्यवादी चेतना प्रबल रही, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया में यह प्रक्रिया अधिक शांतिपूर्ण, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से विकसित हुई। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश मुसलमान न केवल अपनी पूर्व-इस्लामी जड़ों से कट चुके हैं, बल्कि उससे घृणा भी करते हैं, जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के ज्यादातर मुस्लिमों में स्थानीय सांस्कृतिक निरंतरता कायम है। तब भारत के मुसलमानों ने उस्मानी खिलाफत को वैश्विक इस्लामी सत्ता के रूप में देखा। तब मुस्लिम समाज के अभिजात्य वर्ग की यह धारणा बनी कि खिलाफत की रक्षा वस्तुतः भारत में इस्लामी परचम को फिर से लहराने का उपक्रम है, इसलिए तब मालाबार समेत देश के कई हिस्सों में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसके विपरीत, दक्षिण-पूर्व एशिया के मुस्लिम समाजों के लिए तुर्किये का प्रश्न दूरस्थ था।

प्रथम विश्वयुद्ध से तुर्किये के क्रमिक पतन और पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप से पश्चिम एशिया का राजनीतिक भूगोल बदला और कई इस्लामी देश अस्तित्व में आए। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका ने सऊदी के साथ 'सुरक्षा के बदले तेल' का समझौता किया और उसके लगभग सभी खाड़ी देशों से रणनीतिक संबंध हैं। यही समूचा परिदृश्य भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों में व्याप्त गहरे अंतर्द्वंद्व को उजागर करता है। जो मुस्लिम वर्ग, गाजा प्रकरण या ईरान में अमेरिका-इजरायल की बमवर्षा पर तीखी प्रतिक्रिया देता है, वही पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों में मारे गए सैकड़ों मुसलमानों पर चुप्पी साध लेता है। क्या उनकी यह कशमकश भविष्य में और गहराएगी या बदलते वैश्विक यथार्थ के साथ एक नई करवट लेगी?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

युद्ध की तपिश से बचने की चुनौती

जयंतीलाल भंडारी

पश्चिम एशिया में लंबे खिंचते युद्ध से दुनिया के साथ-साथ भारत की आर्थिक चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं

पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में आम लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों मसलन पेट्रोल-डीजल, गैस, बिजली, उर्वरक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के संभावित उपायों पर विचार किया गया। चूंकि पश्चिम एशिया में युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, ऐसे में सरकार की ओर से देश भर में निर्बाध आपूर्ति, स्थिर लाजिस्टिक्स और कुशल वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। मोदी सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों से उपयुक्त समन्वय करना होगा। इसके साथ ही भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयासों के साथ नए निर्यात गंतव्य विकसित करने होंगे।

पश्चिम एशिया में लंबे खिंचते युद्ध से दुनिया के साथ-साथ भारत की आर्थिक चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। हाल में गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत किया गया है। आइसीआइसीआइ बैंक ने भारत के विकास दर अनुमान को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक कच्चे तेल के वैश्विक दाम बढ़ने और आपूर्ति बाधित होने के कारण भारत के ऊर्जा आयात बिल में जबरदस्त उछाल की आशंका है। साथ ही निर्यात में कमी और महंगाई में तेजी संबंधी चुनौतियों के कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था की संतुलित स्थिति के सामने खतरा दिखाई दे रहा है।

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच विस्तारित होते हुए युद्ध से देश के कई हिस्सों में रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलिंडरों की आपूर्ति में बाधा से परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं। निर्यातकों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। सेंसेक्स में गिरावट और डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में कमी का परिदृश्य भी सामने है। निवेशक भारतीय बाजार से अपना धन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। युद्ध का प्रभाव भारत के वित्तीय बाजार पर भी पड़ने लगा है। निवेशकों की संपत्ति में

चिंता बढ़ा रही है रसोई गैस की किल्लत ● पीटीआई

गिरावट आई है और भारतीय कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) तेजी से घटा है। इससे पहले ऐसी गिरावट कोविड के दौरान मार्च 2020 में देखी गई थी, पर युद्ध के ऐसे असर के बीच भी भारत की कुछ ऐसी प्रभावी आर्थिक अनुकूलताएं हैं, जो देश की विकास दर को भारी आघात से बचाने वाली हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है और महंगाई को नियंत्रित रखने तथा आम आदमी पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टाक बढ़ाने, खुले बाजार में खरीदे गए खाद्यान्न की रणनीतिक बिक्री करने और जरूरी आयात की सुविधा जैसे कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। वह निर्यातकों को राहत देने के लिए रेजिलिएंस एंड लाजिस्टिक इंटरवेंशन फार एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ) योजना लेकर आई है। इसका उद्देश्य ऐसे निर्यातकों को मदद देना है, जो माल ढुलाई लागत और बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी तथा युद्ध से जुड़े निर्यात जोखिमों का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत एमएसएमई निर्यातक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। सरकार खाड़ी देशों में जाने वाले सामान का बीमा खर्च भी उठाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय झंडे वाले तेल और गैस टैंकरों को 'होर्मुज स्ट्रेट' से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है।

दुनिया में तेजी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद देश में सामान्य पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य से भी कम है। देश के पास विशाल खाद्यान्न भंडार, पेट्रोल-डीजल आपूर्ति के लिए रणनीतिक भंडार, जरूरत की दवाइयों का पर्याप्त स्टाक भारत की आर्थिक अनुकूलताओं के रूप में दिखाई दे रही हैं। जहां रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन देश के आम आदमी के लिए भोजन की गारंटी है, वहीं कई जरूरतमंद देशों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का आधार भी है। पिछले वर्ष 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ और इस वर्ष इससे भी अधिक उत्पादन की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम के पास केंद्रीय पूल में अप्रैल 2026 तक लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध होने का अनुमान है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। छह साल पहले कोविड से जंग में हमारे खाद्यान्न भंडार ही बड़ा सहारा बने थे। जब ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध से दुनिया में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं और खाद्यान्न आपूर्ति में व्यवधान दिख रहा है, तब भारत का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन राहतकारी है।

भारत अमेरिका तथा रूस सहित अन्य देशों से अधिक मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ाने हेतु वैकल्पिक रणनीति पर काम कर रहा है। पहले भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था। अब इन देशों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। युद्ध के बीच जरूरी दवाओं संबंधी चिंताएं भी कम हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाई उत्पादक देश है और जेनेरिक दवाई उत्पादन में पहले नंबर पर है। भारत के पास 700 अरब डालर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे वह किसी भी आर्थिक जोखिम का सरलतापूर्वक सामना करने में सक्षम है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सजग स्थिरता

गति का रहस्य जितना भौतिक जगत में गहन है, उतना ही वह चेतना के क्षेत्र में भी सूक्ष्म और अर्थपूर्ण बन जाता है। गति को समझने के लिए किसी एक बिंदु का स्थिर होना आवश्यक है। यह सापेक्षता का सिद्धांत केवल भौतिक नियम नहीं, अपितु जीवन के गूढ़ सत्य को भी रेखांकित करता है कि मनुष्य का जीवन निरंतर प्रवाहमान है।

बाह्य संसार अपने विविध रूपों में सतत परिवर्तनशील है। क्षण-क्षण में रूप, स्थिति और परिस्थिति बदलती रहती है। उसी के साथ मनुष्य का मन भी चंचलता के प्रवाह में बहता रहता है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही गति में हों, तब सत्य का साक्षात्कार कठिन है। इसीलिए संसार का वास्तविक स्वरूप, उसका गूढ़ रहस्य, सहज ही पकड़ में नहीं आता। यहां ठहराव की आवश्यकता अनुभव होती है। ठहराव का अर्थ जड़ता नहीं, अपितु सजग स्थिरता है। ऐसी स्थिति जहां मन की चंचल तरंगें शांत होकर एकाग्रता में परिवर्तित हो जाती हैं। यह स्थिरता बाह्य परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना से उत्पन्न होती है। ध्यान, योग और साधना ऐसे ही साधन हैं, जो मनुष्य को इस ठहराव की दिशा में अग्रसर करते हैं।

ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, जहां विचारों का कोलाहल धीरे-धीरे मौन में विलीन होने लगता है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे चेतना सूक्ष्म और जागरूक बनती है। साधना इन दोनों का समन्वय है, जहां निरंतर अभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने भीतर के स्थिर बिंदु को खोजता है। जब यह स्थिरता प्राप्त होती है, तब संसार की गति को एक नई दृष्टि से देखा जा सकता है। तब परिवर्तन भय का कारण नहीं रहता, बल्कि एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार्य हो जाता है। व्यक्ति बाह्य हलचलों के मध्य रहते हुए भी भीतर से अचल बना रहता है। यही आंतरिक स्थिरता उसे सत्य के निकट ले जाती है।

ट्विंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

समय के अनुरूप स्वरूप बदलें संस्थाएं

'प्रासंगिकता खोता संयुक्त राष्ट्र' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. सुरजीत सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए उसकी घटती प्रासंगिकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। प्रस्तुत विचार वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में काफी हद तक यथार्थ के करीब प्रतीत होते हैं। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब ऐसी संस्थाओं की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेख में यह स्पष्ट होता है कि शक्तिशाली देशों के हितों के आगे सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अक्सर कमजोर पड़ जाती है, जबकि सुधार के लिए ठोस संस्थागत ढांचे पर अपेक्षित चर्चा कम दिखती है। विडंबना यह है कि जो संस्थाएं वैश्विक न्याय की प्रहरी कही जाती हैं, वे ही कई बार शक्तिशाली देशों की सुविधा के अनुसार सक्रिय दिखाई देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्विक निर्णय केवल कूटनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं। समस्या का मूल कारण निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, वीटो जैसी असंतुलित शक्तियों का उपयोग और जवाबदेही का अभाव है। समाधान के रूप में वीटो प्रणाली में सुधार, विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना और नीतिगत पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही, क्षेत्रीय संगठनों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। अंततः, संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता तभी बनी रह सकती है जब वह केवल विचार-विमर्श का मंच न रहकर प्रभावी क्रियान्वयन का माध्यम बने और वैश्विक जनहित को सर्वोपरि रखे। संस्थाओं को समय के अनुरूप अपना स्वरूप बदलना ही चाहिए, अन्यथा उनकी प्रासंगिकता संदिग्ध रहती है।

awanishg30@gmail.com

जलवायु परिवर्तन से संकट

मार्च में ही उत्तर मध्य और पश्चिमी भारत के राज्यों में तापमान का तेजी से बढ़ना और लू जैसी परिस्थितियों का समय से पहले बनना यह संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। जहां पहले मई और जून में लू से मौतों की खबरें आती थीं, वहीं अब मार्च में ही ऐसे समाचार सामने आने लगे हैं। इससे स्पष्ट है कि मौसम का पारंपरिक चक्र असंतुलित हो चुका है और इसका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। जिससे तापमान लगातार ऊपर जा रहा है। इस बढ़ते तापमान का प्रभाव केवल गर्मी तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम हो रहा है और रात का तापमान अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शरीर को राहत नहीं मिल पाती। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है क्योंकि लगातार गर्मी में रहने से शरीर की सहनशक्ति कम होती है और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान का बढ़ना एक चिंताजनक संकेत है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

बालीवुड में बदलाव

भारत लगातर हर क्षेत्र में बदलाव कर रहा था लेकिन लंबे समय से भारतीय सिनेमा में बदलाव नही हो रहा था। भारत का सिनेमा जगत एक सोची समझी योजना के तहत फिल्में व धरावाहिक बना रहा था। लेकिन आदित्य धर जैसे फिल्म निर्देशकों ने बालीवुड को सही व सच कहने की दिशा दी है। कभी सर्जीकल स्ट्राइक पर फिल्म बनाने वाले आदित्य धर ने धुरंधर जैसी मूवी बनाकर साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा में सच दिखाने की हिम्मत है। जिस प्रकार से धुरंधर की दोनों फिल्मों में हकीकत को दर्शाया गया है, वो अदभुत है। सामान्य फिल्मों से अधिक समय की होने के बाबजूद भी जनता की दृष्टि फिल्म से हटती ही नहीं है। पूर्व में भारतीय सिनेमा में बड़ी चतुराई से भारत को भारत से दूर करने की कोशिश की। अधिकतम पुरानी फिल्मों में विलेन को तिलक लगाकर, पूजा करने वाला दिखाया गया। अधिकतम फिल्मों में मुख्य विलेन ठाकुर कहकर व हिंदू पूजक नाम रखकर दिखाया गया है, ब्राह्मण हमेशा छलकपट करने वाला, सृष्टि निर्माण से दान देने वाले वैश्य को बेईमान दिखाया गया, शुद्र को हमेशा सवर्णों द्वारा पीड़ित दिखाया गया। जबकि वास्तविकता कुछ और कहती है। अधिकतम फिल्मों में मुस्लिम किरदार को देशभक्त, सच्चा मित्र, अच्छा व्यक्ति दर्शाया गया। आदित्य धर जैसे निर्माताओं ने जनता के सोच को सही तरफ लाने की मजबूत व अच्छी पहल की है।

ललित शंकर, हरिद्वार

पोस्ट

ट्रंप भले ही कह रहे हों कि ईरानी खेमे के साथ दो दिनों से संवाद जारी है, लेकिन ऐसे कोई आसार दिखते नहीं। मुझे लगता है कि इस कथित बातचीत की आड़ में वे अपनी नई रणनीति के लिए कुछ वक्त चाहते हैं बस।

वली नस्र@vali_nasr

कश्मीर सहित भारत के कोने-कोने से मिली नाना प्रकार की मदद का नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने आभार प्रकट किया। ईरान के इस कदम से पाकिस्तान में बैठे लोगों का मिजाज बिगड़ना बहुत स्वाभाविक है।

सिद्धांत सिब्बल@sidhant

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के संकट को लेकर संसद में अपने संबोधन में कोविड महामारी के दौर में उत्पन्न गतिरोध की जो याद दिलाई, वह यही दर्शाता है कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं।

शिवानी गुप्ता@ShivaniGupta_5

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजी सचिव रहे ब्रजेश मिश्रा से मैंने यह सीखा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रियता-सहभागिता बहुत जरूरी है। स्थितियों के अनुरूप इसका स्तर अलग भले हो सकता है।

वेद प्रकाश मलिक@Vedmalik1

जनपथ

अब्दुल बासित के सभी स्वप्न समझिए चूर,
यदि फिर से होगा शुरू आपरेशन सिंदूर।
आपरेशन सिंदूर नहीं है आसाँ दिल्ली,
यदि छूटी ब्रह्मोस बनोगे भीगी बिल्ली !
बेहतर होगा आप बोलिए सिर्फ सुभाषित,
वरना बंटाधार करोगे अब्दुल बासित !!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन.नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस.बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 248

तकनीकी शिक्षा के लिए दाखिले में 135 फीसदी उछाल, नरेला में बनेगा शिक्षा हब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी की तकनीकी शिक्षा में पिछले सात वर्षों में जबरदस्त विस्तार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) के अंतर्गत प्रवेश संख्या वर्ष 2019-20 में 8,394 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 19,773 हो गई है, यानी 135 फीसद की वृद्धि हुई है। 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए 1,044 करोड़ रुपये का बजट है। दिल्ली में अब डीटीयू, एनएसयूटी, आइजीडीटीयूडब्ल्यू, आइआइआइटी-दिल्ली, दिल्ली फार्मास्युटिकल विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय और दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) संग छह राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय हैं।

इनके साथ-साथ 11 इनक्यूबेशन सेंटर में नवंबर 2025 तक 449 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिन्हें 24.61 करोड़ रुपये सीड मनी (प्रारंभिक धन) दिया है। डीटीयू में 137, आइजीडीटीयूडब्ल्यू में 105 और एनएसयूडी में 83 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। एयूडी के धीरपुर और रोहिणी में दो नए कैंपस 2,306 करोड़ की लागत से बनेंगे जिनमें 7,650 छात्रों की क्षमता होगी।

अकादमिक सत्र से खुले 75 सीएम श्री स्कूल

पीएम श्री योजना दिल्ली में लंबे समय तक लागू नहीं हो पाई। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2025-26 के अकादमिक सत्र से 75 सीएम श्री स्कूल शुरू किए हैं। ये केवल बेहतर आधारभूत संरचना वाले स्कूल नहीं हैं, सर्वेक्षण इन्हें अग्रणी और भविष्य के लिए तैयार संस्थान कहता है जो पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और छात्र परिणाम सब में माडल बनेंगे। एनईपी में शुरू हुए कार्यक्रम में नींव व साइंस आफ लिर्निंग हैं।

शिक्षा पर 19,038 करोड़ रुपये खर्च, फिर भी नींव कमजोर

रीतिका मिश्रा ● जागरण

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, राजधानी में शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से अधिक खर्च किया गया है। वर्ष 2025-26 में दिल्ली ने अपने एक लाख करोड़ के कुल बजट में से 19,038.90 करोड़ रुपये यानी 19.04 प्रतिशत केवल शिक्षा पर खर्च किया है। आरबीआइ के राज्य बजट विश्लेषण के अनुसार शिक्षा पर खर्च के मामले में दिल्ली पूरे देश में बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय औसत मात्र 13.1 प्रतिशत है। नौ वर्ष पहले दिल्ली का यही खर्च 9119 करोड़ रुपये था, यानी एक दशक में ठीक दोगुना हो गया।

छठीं व नौवीं में बेहतर, तीसरी में फिसड्डी : परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक तीसरी में दिल्ली के विद्यार्थी भाषा में 62 और गणित में 57 प्रतिशत पर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत भाषा में 64 और गणित में 60 है। यानी जिस नींव पर शिक्षा खड़ी होती है, वहां कमजोर हैं। लेकिन छठी में भाषा में दिल्ली के विद्यार्थी 60 प्रतिशत पर हैं , जो कि राष्ट्रीय स्तर (57 प्रतिशत) से अधिक है।

नौवीं में भी दिल्ली के छात्रों ने भाषा में 65 प्रतिशत, गणित में 40 प्रतिशत, विज्ञान में 46 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान में 44 प्रतिशत हासिल किए, जो सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। वहीं, 12वीं में 98.35 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं जो कि राष्ट्रीय औसत 88.3 प्रतिशत से आगे हैं। वहीं, 929 ने नीट, 667 ने जेईई परीक्षा पास की है।

सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली के सभी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, बिजली कनेक्शन और चारदीवारी शत-प्रतिशत उपलब्ध है। 2024-25 में 99.5 प्रतिशत स्कूलों में खेल का मैदान भी उपलब्ध हो गया है,2017-18 में केवल 88.06% था। कंप्यूटर सुविधा भी 98.86 प्रतिशत स्कूलों में है।

19.4% हिस्सा बजट में शिक्षा का

88.7% साक्षरता दर (एनएसएस) के साथ देश में दूसरे स्थान पर , पहले पर केरल है

44.91 लाख छात्र नामांकित

साक्षरता में दूसरे स्थान पर दिल्ली

75वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) सर्वे 2017-18 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर 88.7 प्रतिशत है, देशभर में केरल (91.1 प्रतिशत) के बाद दूसरे स्थान पर। राष्ट्रीय औसत 77.7 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता दर 93.7% है और महिला साक्षरता दर 82.4 प्रतिशत है।

सकल नामांकन अनुपात में दिल्ली आगे

दिल्ली का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) सभी स्तरों पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्राथमिक स्तर में जीईआर दिल्ली में 101.8% जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 90.9% है। उच्च प्राथमिक स्तर में दिल्ली में 117.1व राष्ट्रीय स्तर पर 90.3 प्रतिशत है।

राजधानी में 2015 के बाद सबसे कम रहा प्रदूषण का स्तर : आर्थिक सर्वेक्षण

2025 में पीएम 2.5 का स्तर (100) कोरोना वाले साल 2020 (101) से भी बेहतर रहा

राज्य ब्यूरो, जागरण. नई दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राजधानी की वायु गुणवत्ता में पिछले एक दशक (2015 के बाद) में सबसे बड़ा सुधार देखा गया है। यदि कोविड-19 के असाधारण वर्ष 2020 को छोड़ दिया जाए तो साल 2025 में पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर दर्ज किया गया।

प्रदूषण के आंकड़ों में बड़ी गिरावट: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में पीएम 2.5 का औसत स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि पीएम 10 का स्तर 209 दर्ज किया गया। यह 2015 के बाद का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। खास बात यह कि 2025 में पीएम 2.5 का स्तर (100) महामारी वाले साल 2020 (101) से भी बेहतर रहा है।

बढ़ रहे हैं 'साफ हवा' वाले दिन

सर्वेक्षण में एक सकारात्मक पहलू 'अच्छी हवा वाले दिनों' की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 में जहां दिल्ली को सिर्फ 159 दिन संतोषजनक श्रेणी की हवा मिली थी, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 200 दिन हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि सुधार दिख रहा है, लेकिन हम अभी भी मानकों से काफी दूर हैं। पीएम 10 का आदर्श स्तर 60 और पीएम 2.5 का 40 होना चाहिए। दिल्ली को अभी लंबा सफर तय करना है।

विधानसभा में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश करतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

चुनौतियां अभी भी बरकरार : प्रदूषण कम होने के बावजूद दिल्ली में कुछ दिनों के दौरान प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में भी पहुंचा। रिपोर्ट में दो प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया गया है :-

धूल भरी आंधी : 15 मई, 2025 को भारी धूल के कारण पीएम 10 का स्तर 1154 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था।

दीपावली का असर : 21 अक्टूबर, 2025 को दीपावली के बाद पीएम 2.5 का स्तर 451 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के उच्च स्तर पर दर्ज किया गया।

वायु गुणवत्ता का तुलनात्मक विवरण (2018-2025)

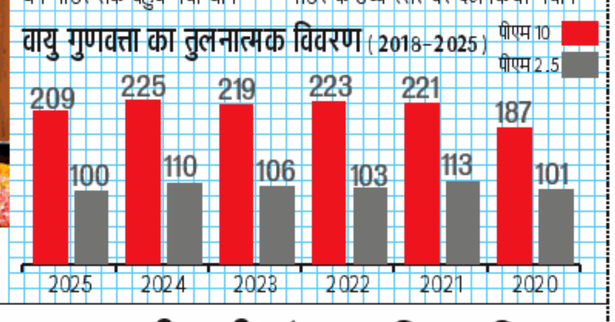

दिल्ली में 37% कचरा अब भी नहीं हो रहा निस्तारित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : तमाम प्रयासों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब भी 37 प्रतिशत कचरा बिना निस्तारण के ही लैंडफिल पर पहुंच रहा है। जिसकी वजह से कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए चल रहे प्रयासों में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भले ही निगम ने लैंडफिल साइटों की खत्म करने की समय-सीमा जुलाई 2026 ओखला लैंडफिल से लेकर दिसंबर 2026 भलस्वा लैंडफिल और दिसंबर 2027 गाजीपुर लैंडफिल की तय कर रखी है लेकिन यह कार्य तय समय-सीमा होना मुश्किल है।

दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 11,862 टन कूड़ा उत्पन्न होता है। इसमें से प्रतिदिन 7641 टन कूड़ा ही निस्तारित करने की क्षमता दिल्ली नगर निगम की है। जो कि उत्पन्न कूड़े का 64.4 प्रतिशत हैं। जबकि 37 प्रतिशत कूड़ा बिना निस्तारित किए ही लैंडफिल पर चला जाता है। सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के लिए निगम ने कार्ययोजना बना ली है। इसमें ओखला और तेहखंड कूड़े से बिजली बनाने वाले संयंत्र की क्षमता 1000-1000 टन प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी। जबकि गाजीपुर में प्रतिदिन 2000 टन नया कूड़ा से बिजली बनाने का सयंत्र स्थापित करने की योजना दिसंबर 2028 तक की है और नरेला बवाना में 3000 टन प्रतिदिन क्षमता का कूड़ा से बिजली बनाने का सयंत्र दिसंबर 2027 तक बनाना प्रस्तावित है।

30 लाख टन हर साल पहुंच रहा है कूड़ा लैंडफिल पर कूड़े के पहाड़ खत्म करने की कोशिश के बीच

एक साल में 74 लाख टन पुराने कचरे का किया निस्तारण: दिल्ली की तीनों लैंडफिल पर 120 लाख टन कचरा बचा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हर वर्ष कूड़ा निस्तारण में तेजी आ रही है। 2022-23 में 21.90 लाख मीट्रिक टन कचरा तीनों लैंडफिल से निस्तारित किया गया।

सीवेज उपचार क्षमता 794 एमजीडी तक पहुंची

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण अनुपचारित एवं आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह है। 22 नाले सीधे यमुना में गिरते हैं, जिनमें हरियाणा से आने वाला नजफगढ़ नाला और उत्तर प्रदेश का शाहदरा नाला भी शामिल है।

दिल्ली में प्रतिदिन अनुमानित 990 मिलियन गैलन (एमजीडी) सीवेज उत्पन्न होता है। इन्हें शोधित करने के लिए 37 सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) हैं। दिसंबर, 2024 में इनकी क्षमता 742 एमजीडी थी। सितंबर, 2025 में यह बढ़कर 794.26 एमजीडी हो गई। इनसे अभी 708.7 एमजीडी सीवेज उपचारित होता है। सोनिया विहार में सात एमजीडी और दिल्ली गेट पर 10 एमडीजी एसटीपी का काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक इन सभी की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करने की है। सीवर नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है।

- इस वर्ष के अंत तक सभी 37 एसटीपी को मानक के अनुरूप करने का लक्ष्य
- नजफगढ़, सप्लीमेंट्री व शाहदरा नाले में सीवेज गिरने से रोकने का प्रयास

1235 कालोनियों में बिछाई जा चुकी सीवर लाइन : राजधानी की 1799 अनधिकृत कालोनियों में से 1235 कालोनियों में सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है और 145 में काम जारी है। लगभग 18 प्रतिशत अनधिकृत कालोनियों में सीवर लाइन नहीं है। नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और शाहदरा नाला के साथ इंटरसेप्टर सीवर बिछाने का काम शुरू किया है। इससे इन गिरने वाले 108 छोटे नालों के 242 एमजीडी सीवेज को एसटीपी तक पहुंचाया जा सकेगा।

17 औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी कार्यरत : एनजीटी के निर्देशानुसार यमुना के बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। नदी में केवल पर्यावरण-अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति दी गई है। दिल्ली के 17 औद्योगिक क्षेत्रों में 13 कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) कार्यरत हैं।

विशेषाधिकार समिति ने फांसीघर मामले में दूसरी रिपोर्ट रखी

राज्य ब्यूरो, जागरण.नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने फांसी घर मामले में अपनी दूसरी अंतरिम रिपोर्ट सोमवार को सदन में पेश की। समिति ने दो बार बैठकों में अनुपस्थित रहने और उचित स्पष्टीकरण न देने पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आप के चार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला का नाम भी शामिल है। समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह राजपूत द्वारा सदन पटल पर रखी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन चारों ने जानबूझकर 13 नवंबर 2025 और 20 नवंबर 2025 को आयोजित बैठकों में अनुपस्थित रहकर विशेषाधिकार समिति की अवमानना की है और केजरीवाल ने उचित व्यवहार नहीं किया।

समिति ने पाया कि दो बार विशेषाधिकार समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने के बाद सदन के निर्देश पर चारों को एक और अवसर देते हुए छह मार्च को बुलाया गया था।

मोदी को लंबे समय तक सरकार चलाने पर विस में दी बधाई

राज्य ब्यूरो, जागरण. नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बनने पर बधाई दी है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिन के रिकार्ड को तोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब सार्वजनिक सेवा में 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संत की तरह देश की सेवा की है। राष्ट्र के विकास और सेवा के लिए समर्पित निष्कलंक अपना जीवन व्यतीत किया है। प्रधानमंत्री ने दूरदृष्टि के साथ काम किया। मैं दिल्ली के हर नागरिक की ओर से उन्हें बधाई देती हूं। उन्होंने चौबीस घंटे व साल के सातों दिन राष्ट्र की सेवा की और शासन व विदेश नीति के माध्यम से देश का गौरव और सम्मान बढ़ाया। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे बाद में विधानसभा ने पारित कर दिया।

सर्वे में बताया, दिल्ली में फिल्म शूटिंग बढ़ी

राज्य, नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए दिल्ली आर्थिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 32 लाख विदेशी पर्यटक आए, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। सर्वे के डेटा से पता चला कि 2024 में राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 32,24,675 विदेशी पर्यटक आए, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक हैं। सर्वे में कहा गया है कि शहर के पुरातात्विक स्थलों में कुतुब मीनार में सबसे ज़्यादा 32.04 लाख व लाल किला 28.84 लाख पर्यटकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसमें कहा दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए भारत दर्शन पार्क और वेस्ट टू वंडर पार्क को शहर के टूरिज्म ऐप, 'देखो मेरी दिल्ली' में जोड़ा गया है।

दिल्ली में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट तक पहुंची

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को ध्यान में रखकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजधानी में 21,915 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 425 मेगावाट है। पिछले दो वर्षों में लगभग 166.71 मेगावाट की वृद्धि हुई। वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों से 84 मेगावाट बिजली मिलती है। इस तरह से दिल्ली में 509 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है।

दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2015-16 में यहां 52.62 लाख बिजली उपभोक्ता थे। अब यह संख्या बढ़कर 73.61 लाख हो गई। इस तरह से 20.99 लाख की वृद्धि हुई है।

कुल उपभोक्ताओं में सबसे अधिक घरेलू श्रेणी 84.1 प्रतिशत उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण बिजली की मांग भी बढ़ी है। इसके साथ ही वर्ष 2015-16 में 5846 मेगावाट की तुलना में वर्ष 2025-26 में बढ़कर 8442 मेगावाट हो गई।

राजकोषीय घाटा बढ़कर हुआ1307 करोड़ रुपये

वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष 9661.31 करोड़ रुपये है। यह जीएसडीपी का 0.73 प्रतिशत है। सरकार ने राजस्व अधिशेष तो बनाए रखा है लेकिन, राजकोषीय घाटा 13,703 करोड़ रुपये हो गया है। इसका कारण पूंजीगत व्यय में 145 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2024-25 में यह 11,485 करोड़ था जिसे बढ़ाकर 28,115 करोड़ रुपये कर दिया गया।

बजट सत्र के दौरान खीर सेरेमनी में खीर बनाकर छात्रा को खिलाती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साथ में मंत्री आशीष सूद,मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज व अन्य ● ध्रुव कुमार

जीएसडीपी में कर राजस्व की हिस्सेदारी ऐसी रही (प्रतिशत में)

वित्त वर्ष	कर राजस्व (करोड़ रुपये)	जीएसडीपी का प्रतिशत
2014-15	26,604	5.38
2015-16	30,225	5.49
2016-17	31,140	5.05
2017-18	35,717	5.27
2018-19	36,625	4.96
2019-20	36,566	4.61
2020-21	29,425	3.95
2021-22	40,019	4.60
2022-23	47,363	4.74
2023-24	53,681	4.82
2024-25	59,458	4.90
2025-26	68,700	5.18

वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण

जीएसडीपी (करोड़ रुपये)

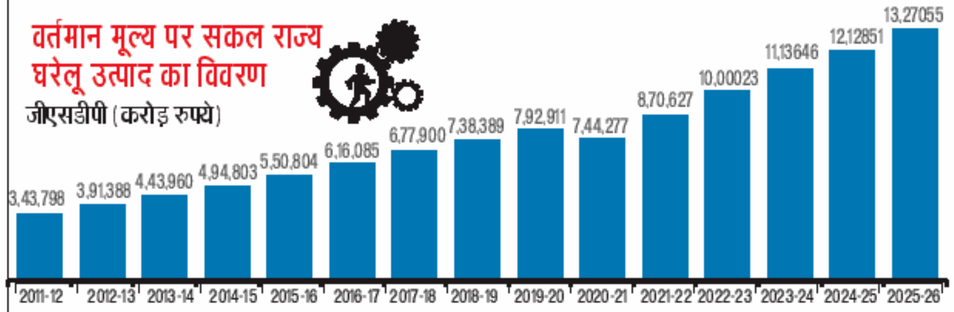

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय का विवरण

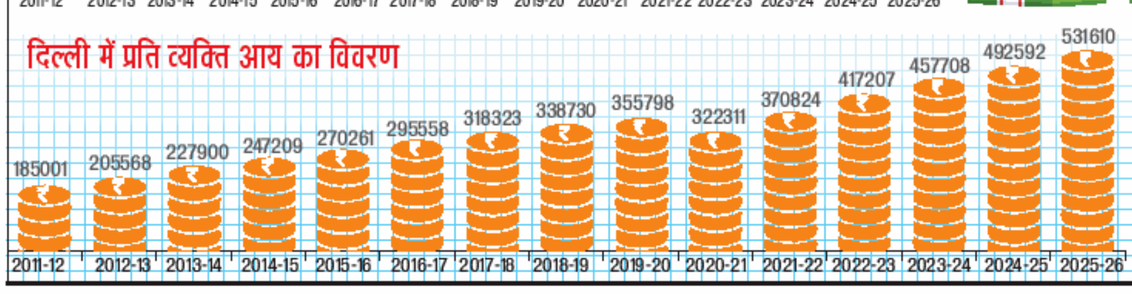

देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 6.9 प्रतिशत और दिल्ली में 7.92 प्रतिशत।

आप विधायकों ने सत्र का किया बहिष्कार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली : आप विधायकों ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन का बहिष्कार किया। सत्ताधारी भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए विरोधस्वरूप अर्थी यात्रा भी निकाली। आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोक दिया।

जरनैल सिंह, सोम दत्त और कुलदीप कुमार सहित चार आप विधायकों को इस साल जनवरी में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल के सदन में संबोधन को बाधित करने के आरोप में निलंबित कर दिया था। सत्र स्थगित न होने के कारण उनका निलंबन जारी है। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि हमें दिल्ली की जनता ने चुना है और हम उनकी समस्याओं और मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि हम अपनी आवाज न उठाएं। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। आप विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्ष की निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पा रहा है और सदन की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के साथियों को पता लगा कि आज पीएसी और सीएजी की रिपोर्ट आ रही है तो उन्होंने सदन का बहिष्कार किया। उनके द्वारा की गई गड़बड़ियों पर जब रिपोर्ट आती हो तो वह बचकर भागने का प्रयास करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन का बहिष्कार करना संसदीय मर्यादा के पूर्णतः खिलाफ है।

- विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के बाहर निकाली अर्थी यात्रा
- आप विधायकों को पुलिस ने बैरिकेड पर रोका

सत्र के दौरान दिल्ली सरकार के विरोध में विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन करतीं नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित अन्य आप विधायक व अन्य ● ध्रुव कुमार

स्वास्थ्य ढांचे में विस्तार के बावजूद कमियां बरकरार

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य ढांचे व सेवाओं में विस्तार तो हुआ है, लेकिन यह दिल्ली की आवश्यकताओं के लिहाज से अब भी सीमित है। बढ़ती आबादी और मरीजों के दबाव के लिहाज से प्रगति धीमी है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार के अस्पतालों में प्रति हजार आबादी के सापेक्ष बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी और मरीज देखभाल के साथ दवा वितरण में सुधार का दावा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर यह निष्कर्ष सोमवार को दिल्ली विधानसभा में पेश 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण का है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 के दौरान 1288 नए अस्पताल बेड जुड़ने से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड संख्या 14,380 (2024-24) से बढ़कर 15,659 हो गई, यह एक वर्ष में करीब 8.89 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वृद्धि से प्रति 1000 आबादी पर उपलब्ध बेड की संख्या 2.82 प्रतिशत से बढ़कर 2.84 प्रतिशत हो गई पर, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पांच बेड प्रति 1000 आबादी के मानक से अब भी काफी कम है। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार के अस्पतालों (40) के साथ नगर निगम और एनडीएमसी के अस्पतालों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार का दावा है, बताया गया कि सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रामा सर्विस को 2025 में 30 नवंबर तक 5.04 लाख से अधिक काल प्राप्त हुईं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का प्रतिशत 75.9 से बढ़कर 84.3 प्रतिशत हो गया, जो सेवाओं की बेहतरी का प्रमाण है।

75.9 से बढ़कर 84.3 प्रतिशत हो गया, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का प्रतिशत

1000 आबादी पर उपलब्ध बेड की संख्या बढ़कर हुई 2.84 प्रतिशत

दिल्ली में बढ़े चिकित्सा संस्थान

सर्वेक्षण में बताया गया दिल्ली में चिकित्सा संस्थानों की संख्या 3711 से बढ़कर 3878 हो गई है। 1926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल स्टाफ और 127 विशेषज्ञों की भर्ती की गई, 4478 नए पद भी सृजित किए गए।

7.45 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान योजना के तहत 7.45 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं और टीबी नियंत्रण में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की गई है।

दिल्ली के अस्पतालों में बढ़े बेड

नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024-25 में दिल्ली के अस्पतालों में कुल 62,514 बेड थे। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों में ये बढ़कर 63,802 हो गए। इनमें सरकारी अस्पतालों में कुल 33,472 बेड (52.46 प्रतिशत) हैं। इसमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 15,569 बेड हैं। बाकी केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय के अस्पतालों में हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में एक बड़ी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की भी है। निजी क्षेत्र के अस्पतालों में कुल 30,310 बेड है। इस तरह कुल 47.50 प्रतिशत बेड निजी अस्पतालों में है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 5,452 बेड जल्द बढ़ेंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण में पुराने आंकड़ों से ही नया खेल : कांग्रेस

राज्य, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा में पेश दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण पर सवाल उठाए हैं। पार्टी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में पुराने आंकड़ों से ही नया खेल किया गया है। इसमें दिए गए सीमित आंकड़ों ने ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोल दी है।

यादव ने आर्थिक सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली की आर्थिक, परिवहन, जल एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन चिंताजनक होती जा रही है। सरकार ने पिछले वर्ष अपना पहला बजट पेश करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया था। जबकि, इस साल प्रस्तुत सर्वेक्षण दिल्ली की कमजोर होती आर्थिक स्थिति को उजागर करता है। यादव ने कहा कि कई महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। पिछले एक वर्ष में 75 स्कूलों का नाम बदलकर सीएम श्री स्कूल कर दिया गया लेकिन एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया।

सेंसेक्स	सराफा	सोना	चांदी	डालर($)
72,696.39 ↓1,836.57	दिल्ली के भाव	₹1,43,600 10 ग्राम ↓₹9,050	₹2,30,000 1 किलो ↓₹10,500	₹93.53 (बदलाव नहीं)

एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स

पश्चिम एशिया में जंग खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिलने से 1,836 अंक गिरा बीएसई सूचकांक

मुंबई, प्रेट्र: पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त होने का कोई संकेत नहीं मिलने से स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,836.57 अंक यानी 2.46 प्रतिशत टूटकर 72,696.39 अंक पर बंद हुआ। बीएसई बेंचमार्क का यह एक साल का निचला स्तर है। इससे पहले सेंसेक्स चार मार्च, 2025 को 72,989 पर बंद हुआ था। कारोबार दौरान, एक समय यह 1,974.52 अंक का गोता लगाकर 72,558.44 पर आ गया था। उधर, पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 601.85 अंक यानी 2.60 प्रतिशत लुढ़ककर 22,512.65 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी का यह स्तर 11 महीने में सबसे कम है। 11 अप्रैल, 2025 को निफ्टी 22,828 पर बंद हुआ था। युद्ध अब चौथे सप्ताह में पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर पूंजी निकासी और रुपये की विनिमय दर में गिरावट ने भी निवेशकों को जोखिम से बचने के लिए प्रेरित किया है।

28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से बीएसई बेंचमार्क 8,590.8 अंक या 10.56 प्रतिशत गिर चुका है और निफ्टी 2,666 अंक या 10.58 प्रतिशत नीचे आया है। सेंसेक्स की कंपनियों में से टाइटन में सबसे अधिक 6.24 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रानिक्स, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा शामिल हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो, दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क काස्पी, जापान का निक्केई225 इंडेक्स, शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स भारी गिरावट के साथ बंद हुए। कास्पी में सबसे ज्यादा 6.49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

> पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संभावित कमी को लेकर चिंताओं के बीच एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के साथ घरेलू बाजारों में भारी गिरावट आई। वैश्विक बांड प्रतिफल में वृद्धि ने बढ़ती मुद्रास्फीति और राजकोषीय चिंताओं का संकेत दिया है। जबकि रुपये के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आने से बाजारों पर और दबाव पड़ा है। -**विनोद नायर**, रिसर्च हेड जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

72,696 पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

601 अंक लुढ़ककर 22,512 पर आया एनएसई निफ्टी

8,590 अंक गिर चुका है सेंसेक्स युद्ध शुरू होने के बाद से

निवेशकों को 48.29 लाख करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, प्रेट्र: पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद (28 फरवरी को) से अब तक निवेशकों को 48.29 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 48.29 लाख करोड़ रुपये (48,29,041.45 करोड़ रुपये) घटकर 415 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

सोना नौ हजार तो चांदी में साढ़े दस हजार की गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र: घरेलू मांग में नरमी और कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच सोमवार को सोना 9,050 रुपये या लगभग छह प्रतिशत गिरकर 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुक्रवार को सोने का बंद भाव 1,52,650 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी 10,500 रुपये या 4.36 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 2,30,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में यह सफेद धातु 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ''कीमती धातुओं में पिछले सप्ताह की गिरावट जारी रही और सोमवार को इंट्राडे ट्रेडिंग में हाजिर सोना चार महीने के निचले स्तर पर फिसल गया।'' उन्होंने इस भारी गिरावट का कारण पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को बताया। इससे तेल की कीमतें बढ़ गईं और मुद्रास्फीति की चिंताओं को हवा भी मिली।

इंट्रा-डे में डालर के मुकाबले 94 के पार जाकर सुधरा रुपया

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय मुद्रा में आई मजबूती, कारोबार के अंत में बिना बदलाव 93.53 पर बंद हुआ रुपया

नई दिल्ली, प्रेट्र: डालर के मुकाबले 50 पैसे टूटकर 94.03 के नए निचले स्तर तक पहुंचने वाला रुपया सोमवार को दिनभर के कारोबार के बाद बिना किसी बदलाव के 93.53 पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह पहली बार डालर के मुकाबले 94 के पार पहुंचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ बातचीत की पेशकश के बाद अंतिम सत्र में रुपये में यह मजबूती आई है।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में स्थानीय मुद्रा 93.84 पर खुली और इंट्राडे ट्रेड में पहली बार डालर के मुकाबले 94 का आंकड़ा पार कर गई। हालांकि, बाद में भारतीय मुद्रा ने अपनी सारी गिरावट की भरपाई कर ली और 93.53 पर बिना किसी बदलाव के बंद हुई। शुक्रवार को 64 पैसे की भारी गिरावट के बाद 93.53 पर बंद होने के साथ ही, रुपया डालर के मुकाबले 93 का आंकड़ा पार कर गया था। डालर की मजबूती का मापने वाला डालर इंडेक्स 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.78 पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड का मूल्य 10.50 प्रतिशत गिरकर 100.37 डालर प्रति बैरल हो गया है। अमेरिका का डब्ल्यूटीआइ क्रूड भी सात प्रतिशत गिरा है।

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि रुपया नकारात्मक रुझान के साथ कारोबार करेगा, क्योंकि बिगड़ते वैश्विक हालात और भू-राजनीतिक तनाव रुपये को दबाव में रख सकते हैं। हालांकि, आरबीआइ द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले हस्तक्षेप से रुपये को निचले स्तरों पर सहारा मिल सकता है।''

चालू वित्त वर्ष के लिए मौजूदा कानून के तहत ही दाखिल होंगे आयकर रिटर्न

- आयकर विभाग ने एफएक्यू के जरिये स्पष्ट की स्थिति
- नए कानून एक अप्रैल से होने वाली आय पर लागू होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र: एक अप्रैल, 2026 से नया आयकर कानून, 2025 लागू होने जा रहा है। लेकिन आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल करने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग की ओर से सोमवार को जारी एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) में स्पष्ट किया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 यानी एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच होने वाली आय का आकलन मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 के तहत ही किया जाएगा और इसी के तहत अधिसूचित फार्म का इस्तेमाल होगा। नया कानून सिर्फ वित्त वर्ष 2026-27 यानी एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली आय पर ही लागू होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है और इसमें वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भत्तों और सुविधाओं का एक संशोधित ढांचा पेश किया गया है। इसमें कुछ टैक्स राहत के साथ-साथ नियमों का पालन भी ज्यादा सख्त किया गया है। अधिसूचित किए गए नए नियमों में मुख्य बदलावों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) की छूट सीमा को बढ़ाना शामिल है। पहले जहां देश के केवल चार शहर ही 50 प्रतिशत वाली श्रेणी में आते थे वहीं अब इनकी संख्या आठ हो गई है। इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा और हास्टल के खर्च को भी बढ़ा दिया गया है और अब इसे क्रमशः 3,000 रुपये प्रति माह और 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

अन्य खास बातें

- ई-फाइलिंग पोर्टल पुराने और नए आयकर अधिनियमों के तहत अनुपालन में सहायता करेगा
- पिछले वर्षों से संबंधित सभी आकलन, अपील और अन्य प्रक्रियाएं पुराने कानून के तहत अंतिम समाधान तक जारी रहेंगी
- टैक्स ईयर 2026-27 के लिए जून 2026 से शुरू होने वाला अग्रिम कर भुगतान नए कानून के अनुसार किया जाएगा
- बिना दंड शुल्क समय सीमा के बाद दाखिल किए गए आइटीआर पर टीडीएस रिफंड का दावा किया जा सकेगा।
- नए अधिनियम के लागू होने से पहले करदाता की आय का आकलन शुरू होने पर पुराने अधिनियम के प्रविधान लागू होंगे

रुपये में रिकार्ड गिरावट से भारत के चीनी निर्यात सौदे बढ़े

मुंबई, रायटर: रुपये में रिकार्ड गिरावट और वैश्विक कीमतों में तेजी के चलते भारतीय चीनी मिलें निर्यात बाजार में सक्रिय हो गई हैं। डीलर्स के अनुसार, बीते एक सप्ताह के दौरान भारतीय मिलों ने एक लाख टन चीनी निर्यात के सौदे किए हैं। ज्यादा माल ढुलाई के कारण चीनी की वैश्विक कीमत पिछले पांच महीनों के उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है।

मुंबई के एक डीलर का कहना है कि युद्ध ने अचानक सब कुछ बदल दिया है। इसने एथनाल की बढ़ती मांग की उम्मीद में वैश्विक चीनी की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है और रुपये को रिकार्ड निचले स्तर पर ला दिया है। पिछले सप्ताह एक लाख टन चीनी निर्यात के सौदा हो चुके हैं। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। डीलरों के अनुसार, भारतीय चीनी लगभग 450 डालर प्रति टन की दर से बेची जा रही है।

सेबी ने आइपीओ के नियमों को सरल बनाया

नई दिल्ली, प्रेट्र: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आइपीओ के दस्तावेजों को सरल बनाने के लिए 'संक्षिप्त विवरण पुस्तिका का मसौदा' पेश किया है। इस कदम का उद्देश्य आइपीओ संबंधी जानकारियों को निवेशकों के लिए अधिक सुलभ और समझने में आसान बनाना है।

अब आइपीओ लाने वाली कंपनियों को अपने विस्तृत प्रस्ताव दस्तावेजों के साथ इस संक्षिप्त विवरण पुस्तिका को भी जमा करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा कि इस दस्तावेज में कंपनी के कारोबारी माडल, वित्तीय विवरण, प्रमोटरों, जोखिम कारकों और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी अत्यंत सरल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी। नियामक ने यह भी निर्देश दिया है कि कंपनियां आवेदन पत्रों और विज्ञापनों में 'क्यूआर कोड' और लिंक उपलब्ध कराएं, ताकि निवेशक विवरण पुस्तिका और मूल्य सीमा की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। सूचनाओं की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने शब्द सीमा भी निर्धारित की है। कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का सारांश 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

एफपीआइ के फंड सेटलमेंट नियमों में भी किया बदलाव

सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) के लिए फंड सेटलमेंट नियमों को आसान बनाने के साथ मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क में बदलाव किया है। इसके अलावा, बोर्ड ने हितों के टकराव और सेबी अधिकारियों से जुड़ी जानकारी पर बनी एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी की कई सिफारिशों को भी मंजूरी दी है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा ने की थी।

म्यूचुअल फंड में गिफ्ट कार्ड से भी निवेश का प्रस्ताव

बेंगलुरु, रायटर: सेबी ने नए निवेशकों को जोड़ने और वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने के लिए सोमवार को म्यूचुअल फंड में गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआइ) से निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश किया। सेबी की वेबसाइट पर जारी एक कंसल्टेशन पेपर के अनुसार, इस प्रस्ताव से गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट (पीपीआइ) खरीदने वाले उन्हें प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित कर सकेंगे। बाद में इनका उपयोग म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के लिए हो सकेगा। पीपीआइ फंड केवल किसी भारतीय बैंक खाते से इलेक्ट्रानिक बैंक हस्तांतरण या यूपीआइ के माध्यम से ही डाला जा सकेगा। इनकी वैधता अवधि जारी होने की तारीख से एक वर्ष होगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

आरबीआइ की एमपीसी बैठकों का कैलेंडर जारी

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठकों का कैलेंडर जारी किया। रेपो रेट तय करने वाली समिति की पहली बैठक 6-8 अप्रैल के बीच होगी। आरबीआइ के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति अगले वित्त वर्ष में छह बैठकें करेगी। आमतौर पर छह सदस्यीय समिति बैठक के तीसरे दिन किसी प्रस्ताव पर मतदान करती है और फैसले का एलान आरबीआइ गवर्नर करते हैं।

अगले वित्त वर्ष की दूसरी द्वि-मासिक नीति समीक्षा बैठक 3-5 जून के बीच होगी और इसके बाद अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी में तीन दिवसीय बैठकें होंगी। मौद्रिक नीति समिति एक छह-सदस्यीय निकाय है, जिसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट तय करने का काम सौंपा गया है। समिति में आरबीआइ के तीन अधिकारी और तीन बाहरी सदस्य शामिल होते हैं।

एक नजर में

'ड्रग्स मामले में बेटे को क्लीन चिट देने के लिए शाह रुख से कभी नहीं मांगी रिश्वत'

मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बांबे हाई कोर्ट में बताया कि उन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाह रुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील सीबीआइ द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज केस रद करने की मांग वाली याचिका पर बहस कर रहे थे। (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट की गुंबद पर राष्ट्रीय चिह्न लगाने की मांग पर सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत की इमारत के गुंबद पर राष्ट्रीय चिह्न लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला उसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट महासचिव से कहा कि वह सक्षम अधिकारी (प्रधान न्यायाधीश) के समक्ष उचित नोट रखें। पीठ 'बड़ा खतरनाक' के नाम से मशहूर बदरावदा वेणुगोपाल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बी. वेणुगोपाल को 'बड़ा खतरनाक' के नाम से इसलिए जाना जाता है, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों में आक्रामक व कई बार असामान्य जनहित याचिकाएं दायर करने को मशहूर हैं। (प्रेट्र)

नवरात्रि में जोमेटो से मंगवाया चिली पनीर, आया चिली चिकन

इंदौर: इंदौर में फूड डिलीवरी में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। राहुल तिवारी ने जोमेटो कंपनी से आनलाइन वेज खाना आर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में नानवेज डिश पहुंच गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घर में नवरात्रि की पूजा चल रही थी। इसी दौरान जोमेटो के जरिये वेज कांबो मील के साथ चिली पनीर आर्डर किया था। करीब 15 मिनट में आर्डर डिलीवर हो गया, लेकिन जब पैकेट खोला गया तो चिली पनीर की जगह चिली चिकन निकला। उन्होंने खाना अलग रखा व एप पर शिकायत की। कंपनी ने आर्डर की राशि वापस की, पर रेस्तरां नाइट किंग ने पार्सल वापस लेने से मना कर दिया। थाने में शिकायत की गई है। (नईदुनिया)

पुलिस अभिरक्षा में दो भाइयों ने बहन के सिर में मारी गोली, गंभीर

जासं, सहारनपुर: पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल कराने आई युवती को दो भाइयों ने पिस्टल से गोली मार दी। सिर में गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपित भाग गए। आरोपितों में से एक भाई के थाने में आत्मसमर्पण करने की सूचना थी, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। युवती को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है।

25 वर्षीय राखी 16 मार्च को लवकुश व गोविंद कुमार के साथ चली गई थी। युवती के बड़े भाई रवि कुमार ने फतेहपुर थाने में 17 मार्च को आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एसपी सागर जैन ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे अज्ञात लोग युवती को थाने के बाहर छोड़कर चले गए। वह थाने पहुंची व बयान दर्ज करने को कहा। दोपहर में पुलिस प्राइवेट स्विफ्ट कार से युवती को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। एसआइ विजयपाल व महिला सिपाही प्रीति युवती के साथ थे। मेडिकल के बाद युवती के बयान दर्ज कराने के लिए उसे कोर्ट ले जाना था। ढाई बजे सीएचसी के बाहर पुलिस ने जैसे ही युवती को कार में बैठाया, तभी मोंटी व रवि वहां पहुंचे। युवती के कार में बैठते ही मोंटी ने पिस्टल से तीन गोलियां चला दीं। एक गोली सिर में लगने से राखी लहूलुहान हो गई।

आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रख लंबे समय तक भर्ती टालना अनुचित: कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी संस्थानों द्वारा नियमित नियुक्तियों को दरकिनार कर लंबे समय तक आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों से काम लेने की प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की है। कहा यह शोषण व अन्याय को बढ़ावा देने वाला कदम है।

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने बरेली नगर निगम को निर्देश दिया कि 13 वर्षों से आउटसोर्स पर काम कर रहे कंप्यूटर आपरेटर के नियमितीकरण पर पुनर्विचार करें। कहा, 'जब किसी कर्मचारी से लंबे समय तक लगातार काम लिया जाता है और उसका कार्य विभाग के लिए आवश्यक व स्थायी प्रकृति का है तो उसे आउटसोर्सिंग के जरिये रखना शोषणकारी व्यवस्था का संकेत है।' ऐसी व्यवस्था से कर्मियों के साथ अन्याय होता है व सरकार नियमित भर्ती की अनदेखी करती है।

याची कफी अहमद खान 2011 से नगर निगम में कार्यरत है। पहले उसे दैनिक वेतन पर रखा गया, बाद में उसकी सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से जारी रखी गईं। 13 साल तक लगातार काम करने के बावजूद उसके नियमितीकरण का आवेदन खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा, 'राज्य आदर्श नियोक्ता होता है व उसका कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों से निष्पक्षता व जिम्मेदारी का व्यवहार करे, न कि शोषण। जब किसी विभाग में काम स्थायी रूप से बढ़ता है तो सरकार को स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, न कि आउटसोर्सिंग के जरिए काम चलाना चाहिए।'

'नाबालिग के हिस्से की संपत्ति बेचने को मां को अनुमति जरूरी नहीं'

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि अगर संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग का हिस्सा है और इसका (संपत्ति का) प्रबंधन परिवार के किसी वयस्क सदस्य द्वारा किया जा रहा है तथा वह नैसर्गिक संरक्षक हैं तो नाबालिग के हिस्से को बेचने के लिए उसे अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

दिवंगत अमित कुमार की पत्नी डाली ने नाबालिग बेटी वंशिका की अभिभावक घोषित किए जाने के लिए मुजफ्फरनगर के की अदालत में आवेदन किया था।

किसानों के पूर्ण कर्ज माफी का प्रस्ताव नहीं

लोकसभा में सोमवार को बोलतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण • एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

वित्त मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से समय पर व पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराना शामिल है। सरकार ने बिना गारंटी वाले अल्पकालिक कृषि ऋणों को 1.60 लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया है। फसल बीमा व भूमि धारक किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिये सीधे नकद हस्तांतरण शुरू किया है।

अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1922 में सेवा-संबंधी शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेवामुक्त हुए सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिव्यांगता पेंशन पर छूट का प्रविधान था। जब आयकर अधिनियम, 1961 लागू हुआ, तो छूट जारी रही।

'पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थिति पर नजर रखे सरकार'

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने अपने बुलेटिन में कहा है कि भारत को पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थिति पर बारीकी से नजर रखनी होगी और उसके असर को कम करने के लिए पहले से ही कदम उठाने होंगे। मार्च के बुलेटिन में आरबीआइ ने यह भी बताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से बचाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आर्थिक स्थिरीकरण कोष बनाने से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और ज्यादा वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। आरबीआइ के मार्च के बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर छपे लेख में इस बारे में बताया गया है।

कर्नाटक में जल्द लगेगी 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के मोबाइल पर रोक

- मंत्री मधु बंगारप्पा ने विधान परिषद में दी जानकारी
- बच्चों पर इंटरनेट मीडिया के प्रभाव को लेकर बढ़ रहीं चिंता

बेंगलुरु, प्रेट्र: कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सोमवार को कहा कि सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के बीच मोबाइल फोन और इंटरनेट मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी, क्योंकि बच्चों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रहीं हैं।

कर्नाटक विधान परिषद में मधु बंगारप्पा एमएलसी प्रताप नायक और जवारे गौड़ा द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने सरकार से तत्काल और कड़े कदम उठाने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि बच्चों में मोबाइल की लत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कहा कि प्रतिबंध पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर रहा है और सरकार अब विभिन्न हितधारकों से परामर्श करके कड़े दिशानिर्देश तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन सीखने के लिए उपयोगी तो हैं, लेकिन हानिकारक सामग्री का स्रोत बनते जा रहे हैं।

गला दबाकर पत्नी को मारा, कार में शव रखकर लगा दी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में कार में आग लगने से कथित तौर पर सीमा पटेल की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस सुनियोजित हत्या में आरोपित डाक्टर पति एवं उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, डाक्टर ने अपनी पत्नी की पहले गला दबाकर हत्या की। इसके बाद शव ठिकाने लगाने के लिए कार में आग लग जाने की कहानी बनाई। जबकि उसने कार की पिछली सीट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी।

आरोपित के अनुसार, 21 मार्च को सागर जिले में टोल प्लाजा के पास एक कार में आग लगने 30 वर्षीय सीमा पटेल की मौत हो गई थी। वहीं, पति नीलेश व उसके दो सहयोगियों ने कूद कर जान बचाने की कहानी रची थी। हालांकि, महिला के स्वजन ने इसे सुनियोजित हत्या बताया था।

पैरासिटामोल, मल्टीविटामिन व 90 एफडीसी अनधिकृत पाए गए, देशव्यापी जांच

नई दिल्ली, एएनआइ: भारत के औषधि महानियंत्रक-डीसीजीआइ ने अनधिकृत फिक्स्ड डोज कंबिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर देशव्यापी कार्रवाई शुरू की है। दवा नियामक ने राज्यों से अनधिकृत पाई गई 90 एफडीसी की जांच करने को कहा है, भले ही उन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों द्वारा अनुमोदित किया गया हो या नहीं। इन दवाओं में मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, पैरासिटामोल, क्लोट्रिमाजोल, आदि शामिल हैं।

दुनिया में रनवे के नीचे पहली बार बन रही भूमिगत यातायात सुरंग

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा, भारतीय विमानन प्राधिकरण से मिल गई है अनुमति, इससे जुड़ा काम प्रगति पर है

हैदराबाद, प्रेट्र: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य के उत्तरी भाग से शहर में आने वाले वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए, बेगमपेट हवाई अड्डे के रनवे के नीचे 'दुनिया में पहली बार' एक भूमिगत यातायात सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्रियों डी श्रीधर बाबू और पोन्नम प्रभाकर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति का गठन करेगी, ताकि विपक्षी सदस्य मूसी नदी तट विकास परियोजना पर अपने सुझाव दे सकें।

उन्होंने कहा कि हमें बेगमपेट हवाई अड्डे के रनवे के नीचे एक अंडरपास बनाने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण से अनुमति मिल गई है। दुनिया में कहीं भी किसी हवाई अड्डे के रनवे के नीचे अंडरपास नहीं है। पहली बार हमने केंद्र सरकार को इसके लिए राजी किया है। काम प्रगति पर है। मूसी नदी तट विकास परियोजना पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी लोगों के पुनर्वास के लिए तैयार है जो अपनी जमीन या घर खो देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे महानगर प्रदूषण, खराब जल निकासी व यातायात जाम जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं हैदराबाद की स्थिति बेहतर है।

अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है भ्रष्टाचार, संपत्ति की रिकवरी ही सफलता की कुंजी: ईडी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भ्रष्टाचार-रोधी वैश्विक सम्मेलन में ईडी निदेशक राहुल नवीन ने सोमवार को कहा कि संपत्ति की रिकवरी, कार्रवाई के बाद का विचार नहीं है, बल्कि यह कानून के क्रियान्वयन की सफलता का वास्तविक पैमाना है। इसी कार्यक्रम में सीबीआइ निदेशक प्रवीण सूद ने कहा कि आज भ्रष्टाचार अंतरराष्ट्रीय, परिष्कृत और तकनीकी होता जा रहा है।

राजधानी दिल्ली में 23-25 मार्च तक आयोजित जीएलओबीई (ग्लोब) नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राहुल नवीन ने प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाने, उसकी रोकथाम, जब्ती और वापस दिलाने के एजेंसी के दायित्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीएसी) में निहित आधुनिक भ्रष्टाचार-रोधी ढांचे के तहत संपत्ति की रिकवरी कानून के क्रियान्वयन की सफलता का सबसे सच्चा पैमाना है। इस मामले में उन्होंने कहा कि ईडी ने लगभग 5.6 अरब अमेरिकी डालर की संपत्ति वापस दिलाई है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी संपत्ति भी शामिल है।

एडीएजी कंपनियों के विरुद्ध जांच से सुप्रीम कोर्ट नाखुश

नई दिल्ली, प्रेट्र: अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़ी बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच में सीबीआइ और ईडी की ओर से दिखाई जा रही अनिच्छा पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों को इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया। तीन जजों की पीठ ने सीबीआइ व ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया और सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ईडी को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत पूर्व ब्यूरोक्रेट ईएएस सरमा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

'बूढ़े' हो रहे जर्मनी में कुशल भारतीयों के लिए अवसर

जागरण न्यूज नेटवर्क • नई दिल्ली। 'बूढ़े' हो रहे जर्मनी में भारतीयों के लिए नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। जर्मनी स्वास्थ्य सेवा और आइटी जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की लगातार कमी से जूझ रहा है। इस संकट का मुख्य कारण बढ़ती उम्र वाली आबादी और जर्मनों का कार्यबल में शामिल होना कम होना है। नियोक्ता अब इस कमी को पूरा करने के लिए भारत से कुशल श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं।

बर्टेल्समन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को हर साल 2,88,000 विदेशी कर्मचारियों की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2040 तक जर्मनी की वर्कफोर्स 10 प्रतिशत तक कम हो सकती है। जहां जर्मनी में कम जन्म दर एक समस्या है, वहीं भारत में 25 वर्ष से कम आयु के 60 करोड़ लोग हैं, जो एक बड़ा वर्कफोर्स प्रदान करते हैं।

भारत और जर्मनी के बीच 2022 में 'माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारतीयों के लिए वहां काम करना काफी आसान हो गया है। इसके बाद, 2024 के अंत में जर्मनी ने भारतीय नागरिकों के लिए स्किल्ड वर्क वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 प्रति वर्ष कर दिया था।

Last Day To Join Private channel

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS PURCHASE WILL BE WORTH IT.

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Uploding starts from 5AM

🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)